

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

#### **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 477] No. 477] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2014/भादपद 25, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2014/BHADRA 25, 1936

वित्त मंत्राालय (राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशालय) (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

#### अधिसुचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

# विषय :-सोडियम साइट्रेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच - अंतिम जांच परिणाम

सा.का.नि. 663(अ).--सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए; पिकया

1. मेरे समक्ष सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतद्पश्चात् रक्षोपाय नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मैसर्स पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, सं.187/1क, करोली निकट खटराज चौकड़ी, तहसील कालोल, जिला गांधी नगर, गुजरात की ओर से अपने अधिवक्ता मैसर्स टीपीएम सालिसिटर्स एंड कंसल्टेंट्स के माध्यम से एक आवेदनपत्र भारत में सोडियम साइट्रेट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया गया है जिससे भारत में "सोडियम साइट्रेट" (जिसे एतद्पश्चात् विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी कहा गया है) के संवर्धित आयातों द्वारा सोडियम साइट्रेट के घरेलू उत्पादकों को कारित की जाने वाली गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से रक्षा की जा सके।

3698 GI/2014 (1)

- 2. रक्षोपाय नियमावली के उक्त नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का घरेलू उत्पादक के संयंत्र का स्थल दौरा करके जरूरी समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया। इस बात से संतुष्ट होने पर कि नियम के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और आवेदनपत्र को दिनांक 24.2.2014 को अयतन कर दिया गया है, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत सोडियम साइट्रेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरूआत का नोटिस दिनांक 4 मार्च, 2014 को जारी कर दिया गया और उसे उसी दिन अर्थात् 4 मार्च, 2014 को ही भारत के राजपत्र असाधारण में सा.कािज 140(अ) के तहत प्रकािशत कर दिया गया।
- 3. दिनांक 4 मार्च, 2014 के जांच शुरूआत नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र में अगोपनीय पाठ की एक प्रति केंद्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और निम्निलिखित सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार प्रेषित की गई:

## (I) घरेलू उद्योग

# क. पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, नं. 187/1क, करोली, निकट खटराज चौकड़ी तहसील कालोल, जिला गांधी नगर, गुजरात-382721

### (II) अन्य भारतीय उत्पादक

- क. सुनील कैमिकल्स, 311, जानकी सेंटर, आफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई-400053
- ख. इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 11, वाल्मीक कम्प्लेक्स, सीजी रोड, अहमदाबाद, 380006, गुजरात
- ग. जी. एम्फ्रे लैबोरेट्रीज, सामबावा चैम्बर्स चौथा तल, सरपी. एम. रोड, नवनिध फार्मा लैब, 37, बिंदल ईस्ट, साकीनाका, मुंबई, महाराष्ट्र
- घ. नवनिध फार्मा लैब, 37 बिंदल ईस्ट साकीनाका, मुंबई
- ङ. वैंग फार्मास्युटिकल्स एंड कैमिकल्स, ए-77, विशाल एन्क्लेव, नई दिल्ली-110027
- च. वी.एम. कैमिकल्स सी/1, 243 जीआईडीसी, II फेज, अम्बावाड़ी, सुरेन्द्र नगर, गुजरात-363035

#### (III) आयातक

- क. क्रिस्टल क्राप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जीआई-17, जीटी करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया आजादपुर, दिल्ली-110023
- ख. देस्मो एक्सपोर्ट्स, 125 अरेन्जा आर्केड, सेक्टर 17, वासी, नवी मुंबई-400703, महाराष्ट्र
- ग. न्यू ड्रग्स एंड कैमिकल कंपनी, 4 जय महल एस्टेट, द्वितीय तल 20/48, लोहार चाल, महाराष्ट्र

- घ. कलरकान एशिया प्राइवेट लिमिटेड, 38-एबी, गवर्नमेंट औद्योगिक एस्टेट चारकाप, कांदीवली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र
- ङ. एसीआईडी इंडिया, मुल्रात्रा द्वितीय तल, 334, नरसी नाथ स्ट्रीट, मुंबई-400703, महाराष्ट्र
- च. प्रदीप कुमार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, 701, अरूण चैम्बर्स, 80 ताइदेव रोड, मुंबई, महाराष्ट्र
- छ. अभिजल कैमिकल्स, 5/4 मुंगेकर इंडस्ट्रियल एस्टेट, आफ ऐरे रोड, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र
- ज. अदानी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट सं. 2729 से 2731, रोड-1, 1, लोधिका, जीआईडीसी, ग्राम-मेटोडा, तालुका लोधिका, राजकोट-360021, गुजरात
- झ. सुजाता कैमिकल्स, 802, जीआईडीसी, माकडपुरा वडोदरा-390010, गुजरात
- ञ. प्रकाश कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्दु चाचा हाउस, छानी चुंगी नाका के पीछे, वड़ोदरा, गुजरात
- ट. आरएम कैमिकल्स गुरूकृपा काम्प्लेक्स, 131, अन्ना पिलाई स्ट्रीट, सोकारपेट, चेन्नई-600001, तमिलनाइ
- ठ. पिक्जर लिमिटेड, पिफ्जर सेंटर, पटेल ईट, एसवी रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम) मुंबई-400102, महाराष्ट्र
- ड. एफडीसी लिमिटेड बी-८, एमआईडीसी एरिया, वालुज-४३११३६, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
- ढ. वालान्स फार्मास्युटिक्ल लिमिटेड, तृतीय तल डेम्पो ट्रेड सेंटर, बिल्डिंग, प्रताप प्लाजा, ईडीसी काम्पलेक्स, पणजी-403001, गोवा
- ण. कायरा डिस्ट्रिक्ट को-आप मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लिमिटेड, स्टेशन रोड, आनंद-388001, गुजरात
- त. स्केरीबेर डायनामिक्स डेयरीज लिमिटेड, ई-94, एमआईडीसी, भगवान रोड, बारामती, जिला पुणे-413133, महाराष्ट्र
- थ. वासा फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, डी1 एवं डी2, द्वितीय तल, "निकुम्भ" एनआर, रिलायन्स हाउस, सीजी रोड, अहमदाबाद-380006, गुजरात

# (IV) निर्यातक

- क. क्विंगडाओ सोनेफ कैमिकल कंपनी लिमिटेड, आरएम 1504, जिन्हुआ बिल्डिंग, संख्या 100, नानिर्जिंग रोड, शान्डांग क्विंगडाओ, चीन
- ख. वीफैंग वाट इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी लिमिटेड सं. डी 2704, डांगफेंग स्ट्रीट, शानडांग-26100 वीफेंग, चीन
- ग. हाइ हुई ग्रुप कंपनी, लिमिटेड, जुकाउंटी का इंडस्ट्रियल पार्क, शानडांग-276500, रिझावो, चीन
- घ. फूडकेम इंटरनेशनल कारपोरेशन बिल्डिंग, 9, 2277, झुचोग्झी रोड, झान्जियांग हाई टेक पार्क, शंघाई-201203, चीन
- ङ. इक्सिंग झेनफेन मेडिकल कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, झाउटी टाउन, इक्सिंग सिटी, जियांग्सु प्रांत, 214262, चीन

- च. हैनान हौरांग कैमिकल कंपनी लिमिटेड, शक, बीजिंग बिल्डिंग, सं. 56, गुओसाओ रोड, हैनान हाइकोठ-570125, चीन
- छ. लियानउनगांग डोंग्टाई फूड इन्गिडिएन्टस कंपनी लिमिटेड, कमरा 28, यूनिट-1 सं. ए3, भवन 28 यिंगझोउ रोड, जिन्यु जिला, जियांग्सु-222000 लिआन युनगांग चीन
- ज. लियानयुगांग शुरेन के चुआंग फूड एडिटिव कंपनी लिमिटेड, दि ईस्ट आफ लिन्हांग रोड, दापु कैमिकल इंडस्ट्रीज जोन, लियानूनगैंग टीईडीए, जियांग्सू, 222000 चीन
- झ. हानसान फार्माटेक ग्रुप लिमिटेड, 275, डान पार्क रोड, मुरखाम, ओन्टारियो, कनाडा
- ञ. गडोट बायोकैमिकल इंडस्ट्रीज एलटीसी पी.ओ. बॉक्स, 10636, हाइफा बे, 26118, इजरायल
- ट. शोवा काको कारपोरेशन, निस्सो बिल्डिंग 6एफ 2-2, डोजिया 1, कोमे, किटा-कु, जापान
- ठ. कैमिकल सप्लाई कंपनी एलएलसी, 10405, एमडब्ल्यू 37वां टैरेस, मियामी फ्लोरिडा
- ड. आर्कर डेनियल्स मिडलैंड कंपनी, 4666 फेरीज पार्क वे डिकेटुर, आईएल 62526, यूनाइटेड स्टेटस आफ अमेरिका, यूएसए
- ढ. कारगिल आईएनसी 15407, मैकगिन्टी रोड डब्ल्यू चेजाटा, एमएन 55391- 2365 (800) 227-445
- ण. टाटे एंड लायल पीएलसी 1 किंग्सवे लंदन डब्ल्यूसी 2 बी 6 एटी, यूनाइटेड किंगडम (v) निर्यातक राष्ट्र :
- क. चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास 50 –घ, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- ख. संयुक्त राष्ट्र का राजदूतावास, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- ग. स्पेन का राजदूतावास, 12, पृथ्वीराज रोड, (वान मार्केट, नई दिल्ली-110001
  - 4. उपलब्ध जानकारी के अनुसार ज्ञात निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नाविलयां इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे जांच शुरुआत नोटिस के 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत करा दें।
  - 5. निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए :
    - क. व्यापार एवं आर्थिक सेक्सन, यूरोपियन यूनियन का भारत में प्रतिनिधिमंडल 65, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-110003, ई मेल : chaitanya.kaushal@eeas.europa.eu
    - ख. मिनिस्टर काउंसेल (आर्थिक कार्य) मलेशिया का उच्चायोग, 50एम सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, ई-मेल : <u>brecta.robert@miti.gov.my</u>
  - 6. सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए
  - 7. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया :
    - क. घरेलू उद्योग : पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, सं. 187/1,ए, कैरोली निकट खटराज चौकड़ी, तालुका, कालोल, गांधी नगर, गुजरात-382721
    - ख. आयातक : (i) मैसर्स अदानी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, तालुका लोधिका, जिला राजकोट-360021

- ग. मैसर्स एफडीसी लिमिटेड, 142-148 एसवी रोड जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई ग, मैसर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लिमिटेड आनंद-388001, गुजरात
- 8. जांच शुरुआत नोटिस के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से भी प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ -
  - क. डेस्मो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, दिनांक 21/3/2014 के पत्र के तहत
  - ख. इशिता इग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड फार्मास्युटिकल्स, दिनांक 17.03.2014 के पत्र के तहत
  - ग. प्रकाश कैमिकल्स एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड, दिनांक 09.04.2014 के पत्र के तहत
  - घ. न्यू ड्रग्स एंड कैमिकल्स कंपनी दिनांक 27.3.2014 के पत्र के तहत
  - ड. वांग फार्मास्युटिकल्स एंड कैमिकल्स, दिनांक 03.04.2014 के पत्र के तहत
- 9. विदेश मंत्रालय, यूरेशिया प्रभाग ने अपने दिनांक 19 जून, 2014 की फाइल सं. डब्ल्यू आई (एडी) 123/04/2014 के तहत एक पत्र अग्रेषित किया जिसमें उन्होंने उसके साथ रूसी परिसंघ के उचोग एवं वद्मापार उपमंत्री श्री विक्टर इव्टुखोव का दिनांक 5 जून, 2014 का एक मौखिक नोट सं. 923/एन संलग्न किया था जिसमें यह कहा गया कि वर्ष 2012-13 से जांच की अविध के दौरान, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्षक सं. 29181520 के अंतर्गत आने वाली वस्तु का आयात तथा भारत को रूसी परिसंघ से आयात तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है और इसलिए सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (धारा 8ख) तथा डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत रक्षोपाय प्रावधानों के अनुसार रूसी परिसंघ को जांच के अंतर्गत आने वाले देशों की सूची से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।
- 10. मैसर्स सुनील कैमिकल्स, 311, जानकी सेंटर, आफ वीरा देशाई रोड अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053 ने अपने दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के पत्र के तहत भारत में सोडियम साइट्रेट के बढ़ते आयातें के विरूद्ध रक्षोपाय साधन करने के लिए आवेदनपत्र दायर करने में घरेलू उद्योग को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन, बिक्री और मालसूची के संबंध में भी आंकड़े उपलब्ध कराए; जिन पर विचार किया गया और समग्र क्षति विश्लेषण करने के लिए उन्हें रिकार्ड में लिया गया।
- 11. समुचित निर्धारण करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचारों पर विचार किया गया। प्राप्त या अधिप्राप्त अगोपनीय सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

# II. हितबद्ध पक्षकारों के विचार (जांच शुरूआत नोटिस के पश्चात्)

- 12. इस मामले में जारी किए गए जांच शुरूआत नोटिस के प्रत्युत्तर में केवल कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने ही अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की है, जो निम्नलिखित हैं :
- क. डेस्मो एक्सपोर्टस लिमिटेड
- क. सोडियम साइट्रेट पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. इशिता इग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड फार्मास्युटिकल्स

- क. आयात, घरेलू उत्पादन और बिक्रियों से संबंधित असत्यापित आंकड़ों का गलत निर्वचन किया गया है और उसके परिणामस्वरूप की गई कोई भी कार्रवाई राष्ट्रीय खासकर एसएसआई विनिर्माताओं के हित में नहीं है।
- ख. आयातित अपरिष्कृत विचाराधीन उत्पाद को पुन:प्रसंस्कृत किया जाता है और उसकी घरेलू एवं निर्यात बाजारों में बिक्री शुद्ध रूप में जाती है और यदि उस पर कोई शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो वह निर्यातकों को अप्रतिस्पर्धी बना देगा तथा उससे विदेशी मुद्रा अर्जन में घाटा होगा।
- ग. कुल मांग जांच शुरूआत नोटिस में प्रावधान की गई मांग की तुलना में बहुत अधिक है क्योंकि अन्य भारतीय विनिर्माताओं की बिक्री का एक बड़ा प्रतिशत आयातित सोडियम साइट्रेट का प्रसंस्करण करने के बाद होता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की बिक्री जांच शुरूआत नोटिस में किए गए उल्लेख की तुलना में बहुत अधिक है और इसलिए एक विस्तृत जांच आवश्यक है।
- घ. किसी प्रकार के शुल्क से इयाधिकार वाली स्थिति बन जाएगी और इससे विचाराधीन उत्पाद और अन्य परिष्कृत उत्पादों जैसे मक्खन, चीन, जीवन रक्षक ओआरएस, डायलसिस रिएजेंट की कीमतें बढेगी।

## ग. प्रकाश कैमिकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड

- क. याचिकाकर्ता पाटनरोधी और रक्षोपाय दोनों शुल्कों की मांग एक साथ नहीं कर सकते हैं, जैसाकि उन्हें प्राप्त है, क्योंकि दोनों के ही उद्देश्य अलग-अलग हैं।
- ख. इस याचिका में चार घरेलू उत्पादकों के वास्तिवक उत्पादक का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस पर ध्यान दिए जाने से याचिकाकर्ता का यह दावा अस्वीकार्य हो जाएगा कि वे 90 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।
- ग. सहायक उत्पादक ने वर्ष 2010-11 से आज तक कोई उत्पादन नहीं किया है जबिक याचिका में उसे 44 प्रतिशत उत्पादन के लिए उत्तरदाई बताया गया है। अतः, जांच शुरूआत का नोटिस तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है।
- घ. याचिका में जिन निर्यातकों का उल्लेख किया गया है उनमें से कोई भी वास्तविक निर्यातक नहीं है और यदि वे निर्यात करते हैं तो उनकी मात्रा बह्त कम है।
- ड. याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद के सर्वसम्मत निर्यातक हैं, इसलिए आयातों के कारण कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है।
- च. याचिकाकर्ताओं ने कुल मांग का उल्लेख नहीं किया है। 14000 एमटी की अनुमानित मांग को याचिकाकर्ता द्वरा 4000 एमटी उत्पादन के दावे से पूरा नहीं किया जा सकता है और यदि कोई श्ल्क अधिरोपित कर दिया जाता है तो उससे याचिकाकर्ताओं का एकाधिकार हो जाएगा।
- छ. इस विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के साथ-साथ कच्चे माल के मूल्य में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है और इसलिए ऐसे उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।

ज. शुल्क लगाने से अधोगामी प्रयोक्ताओं का प्रचालन अर्थक्षम नहीं रहेगा और अंतिम उत्पादों खासकर फार्मा की कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को भारी घाटा होगा।

#### घ. नवीन ड्रग एवं कैमिकल कंपनी

- क. इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क से चीन के विनिर्माताओं द्वारा साइट्रिक एसिड की आपूर्ति बढ़ा दी जाएगी। साइट्रिक एसिड वह कच्चा पदार्थ जिसका प्रयोग भारतीय विनिर्माता इसका निर्माण करने के लिए करते हैं।
- ख. याचिकाकर्ता केवल फार्मा ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करते हैं जो केवल फार्मा और खाद्य उद्योग की जरूरतों को पूरा करती है, न कि कृषि रसायन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि जैसे अन्य रसायन उद्योगों की।
- ग. इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से फार्मा एवं खाद्य उद्योग के अलावा अन्य उद्योगों को कष्ट होगा क्योंकि याचिकाकर्ता विनिर्माण के अलावा अन्य घरेलू उत्पादकों के आर्डर लंबित पड़े रहेंगे और वे मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं।

### ड. वैंग फार्मास्यूटिकल्स एंड कैमिकल्स

क. चीने से सस्ते आयातों के कारण सोडियम साइट्रेट उद्योग के बुरे दिन चल रहे हैं। यूएसए और यूरोप ने पहले ही चीन के उत्पादों पर भारी पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अपने उद्योग की रक्षा करने के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए 35 प्रतिशत पाटनरोधी की दर से पाटनरोधी शुल्क लगेगा।

## III. सार्वजनिक सुनवाई :

- 13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का 20 जून, 2014 को नोटिस भेजा गया था जो दिनांक 23.06.2014 को आयोजित होनी थी। तथापि, अपिरहार्य पिरिस्थितियों के कारण इस सार्वजनिक सुनवाई को पुनः निर्धारित किया गया और अंततः 07.07.2014 को इसका आयोजन किया गया। निम्निलिखित पक्षकारों ने इस सुनवाई में भाग लिया :
  - घ. पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
  - ङ. सुनील कैमिकल्स (समर्थक)
  - च. वैंग फार्मास्युटिकल्स (अन्य घरेलू उत्पादक)
  - छ. इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अन्य घरेलू उत्पादक)
  - ज. प्रकाश कैमिकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)
  - झ. मिनिस्टर काउंसलर (आर्थिक कार्य), मलेशिया उच्चायोग
- 14. सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुसार मौखिम रूप से अभिव्यक्त किए गए अपने विचारों का लिखित रूप से प्रस्तुतिकरण करें। तत्पश्चात, एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को भी घरेलू उद्योग सहित, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों, यदि कोई हो का प्रति प्रत्युत्तर देने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान

सार्वजिनक सुनवाई में भी, इस सार्वजिनक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यकत अपने विचारों को दिनांक 17 जुलाई, 2014 तक लिखित प्रस्तुतिकरण करें। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति घरेलू उद्योग सित अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। सभी हितबद्ध पक्षकारों को, घरेलू उद्योग सित अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों का प्रतिप्रत्युत्तर दिनांक 25 जुलाई, 2014 तक दायर करने का अवसर प्रदान किया गया। लिखित प्रस्तुतिकरणों, प्रति प्रत्युत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचारों की जांच की गई और समुचित निर्णय करते समय उन पर ध्यान दिया गया। तथापि, मिनिस्टर काउंसेलर (आर्थिक कार्य) मलेशिया का उच्चायोग, जिसने इस सार्वजिनक सुनवाई में भाग लिया था, नामक एक हितबद्ध पक्षकार ने न तो कोई मौखिक प्रस्तुतिकरण किया और न ही कोई लिखित प्रस्तुतिकरण और न ही घरेलू उद्योग द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण का कोई प्रति प्रत्युत्तर दायर किया।

## सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् लिखित प्रस्तुतिकरण

- 15. मैसर्स पोजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 17 जुलाई, 2014 के पत्र के तहत निम्नलिखित लिखित प्रस्तुतिकरण किया :
  - क. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम साइट्रेट" है। सोडियम साइट्रेट का रासायनिक यौगिक होता है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डाइसोडियम साइट्रेट और ट्राइसोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। उनके द्वारा उत्पादित वस्तु भारत में आयातित वस्तु के समनुरूप है। इस विचाराधीन उत्पाद का लेनदेन निम्नलिखित नामों से भी किया जा सकता है।
    - (i) सोडियम साइट्रेट
    - (ii) ट्राइसोडियम साइट्रेट
    - (iii) ट्राइ सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट
    - (iv) सोडिया साइट्रेट डिहाइड्रेट
    - (v) ट्रिबेसिक सोडियम साइट्रेट
    - (vi) सोडियम साइट्रेट ट्रिबेसिक डिहाइड्रेट
    - (vii) सोडियम साइट्रेट डाइबेसिक सेस्कप्रिहाइड्रेट
    - (viii) सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बाओक्स्ट्रा
  - ख. सोडियम साइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः एक्स्पेक्टोरेंट और यूरीन अल्क नाइजर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग फार्मास्युटिकल ऐड तथा डेयरी उद्योग में खाद्य एडिटिव के रूप में भी किया जाता है जो चीज विनिर्माण और पेय पदार्थों की जरूरत को पूरा करता है। यह एक जल उपचारी रसायन भी है और इसका प्रयोग प्रयोगशाला रिएजेंट के रूप में भी किया जाता है।
  - ग. याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु भारत में आयातित वस्तु के समान वस्तु है। दोनों ही उत्पादों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं प्रकार्यों, उतपाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे पैरामीटरों के रूप में तुलनीय गुणधर्म हैं। घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बारे में अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों की तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों में आयातित वस्तु से तुलनीय है।

- घ. वर्तमान आवेदनपत्र मैसर्स पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदनपत्र का मैसर्स सुनील कैमिकल्स द्वारा समर्थन किया गया है।
- इ. मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स नविवध फर्मा लेब, मैसर्स जी. एम्फ्रे लेबोरेटरीज, मैसर्स वैंग फार्मास्युटिकल्स एंड कैमिकल्स तथा मैसर्स वी. एम. कैमिकल्स वे कंपिनयां हैं जो बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कर रही हैं। याचिकाकर्ता की बाजार आसूचना के अनुसार कुछ सीमांतक उत्पादक जैसे मैसर्स वासा फार्मा, मैसर्स अदानी फार्मा और मैसर्स सुजाता कैमिकल्स, जो इससे पहले इस संबंधित उत्पाद का उत्पादन कर रहे थे, में अब आयात का आश्रय लिया है और उन्होंने सतत पाटन के कारण आयातित उत्पाद का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया है।
- च. याचिकाकर्ता ने अपनी ज्ञात बिक्री मात्रा पर विचार किया है और उसी को उतपादन के रूप में माना है। आवेदक का उत्पादन सोडियम साइट्रेट के उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है।
- छ. मैसर्स वैंग फार्मास्युटिकल्स और मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस जांच में घरेलू उद्योग के रूप में प्रतिभागिता की है। यह अनुरोध किया जाता है कि महानिदेशक महोदय उनका उत्पादन विवरण मांग सकते हैं और तदनुसार याचिकाकर्ता के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं।
- ज. मैसर्स वैंग फार्मास्युटिकल्स ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दी जाने वाली प्ली का समर्थन किया है। तथापि, मैसर्स इशिता इग्स एंड फार्मास्युटिकल्स, जिसने संबद्ध वस्तु का घरेलू उत्पादक होने का दावा भी किया है, ने रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने का विरोध किया है। इस कड़े विरोध का कारण यह प्रतीत होता है कि यह कंपनी इस विचाराधीन उत्पाद का आयात करती है और उसकी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करती है।
- झ. विधि के अंतर्गत यह अपेक्षा है कि आयातों में अचानक एवं एकाएक वृद्धि हुई हो। डब्ल्यूटीओ ने अर्जेन्टीना फुटवीयर मामले में यह उत्पादित किया है कि संवर्धित आयात अचानक एवं यकायक हुए हों।

"यह निर्धारण कि क्या आयातों में" इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में वृद्धि की जरूरत केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण ही नहीं है। दूसरे शब्दों में, "किसी जांच के लिए साधारण रूप से केवल यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं होगा कि कितपय उत्पाद के आयात इस वर्ष पिछले वर्ष या पांच वर्ष पहले की तुलना में अधिक हुए इसके अतिरिक्त, यह पुनरावृत्ति प्रतीत होती है कि, आयातों में वृद्धि की कोई मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी। आयातों में यह वृद्धि ऐसी संवर्धित मात्रा में हुई हो जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षितिकारित कर रही हो या गंभीर क्षितिकारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रही हो जिससे रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की जरूरत पूरी हो सके ओर रक्षोपासय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX : 1 (क) दोनों में ही इस भाषा का प्रयोग में यह अपेक्षा की जाती है कि आयातों में वृद्धि गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त महतवापूर्ण हो जिससे कि यह "गंभीर क्षिति" कारित हो सके या गंभीर क्षिति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर सके।"

- ञ. याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि सोडियम साइट्रेट के आयातों में समग्र एवं संगत दोनों रूपों में तीव्र वृद्धि हुई है। आयातों में यह वृद्धि अचानक और बहुत अधिक है जो बाजार विकृति और बाजार विकृति की चुनौती कारित कर रही है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "नियमों के आशय के अंतर्गत वृद्धि" हुई है।
- ट. सोडियम साइट्रेट के आयातों में समग्र रूप से तीव्र वृद्धि हुई है और इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2010-11 से मार्च 2014 तक वृद्धि हुई। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-14 के वास्तविक आंकड़ों में और अधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

पैरामीटर/वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयात	2,621	2,877	3,721	5,300

- ठ. भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में तेजी से वृद्धि हुई है और यह वृद्धि रक्षोपाय जांच प्रारंभ करने के समय पाई गई वृद्धि की तुलना में बह्त अधिक है।
- इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की खपत की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। आयातों में इतनी अधिक सीमा तक वृद्धि हुई कि खपत की तुलना में आयातों का प्रतिशत भारतीय खपत का 71 प्रतिशत हो गया।

पैरामीटर/वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
खपत की तुलना में आयात	57%	55%	57%	71%

## घरेलू उद्योग द्वारा रिज्वाइंडर मै वर्ष 2013-14 मे 71% के स्थान पर 69% को सही किया

## ढ. आयातों में वृद्धि के कारण :

(i) घरेलू बाजार में अधिकांश आयात चीन से हुए हैं जिसकी बहुत अधिक बेशी क्षमता है और इसीलिए वह सोडियम साइट्रेट का निर्यात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने साइट्रिक एसिड और कुछ साइट्रिक लवणों जिसमें सोडियम साइट्रेट भी शामिल था, के आयातों के विरूद्ध पाटनरोधी जांच आयोजित की थी, जिसमें यूएस प्राधिकारियों ने उत्पादित किया कि चीन के पास बहुत अधिक क्षमता है।

वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010
स्पष्ट खपत					
क्षमता	1443	1932	2047	2193	2195
उत्पादन	1247	1719	1807	1779	1834
जीएपी (उत्पादन-खपत)	924	1259	1332	1190	1227

<sup>\* &#</sup>x27;000 पौंड में; स्रोत : यूएसएस जांच परिणाम

- (ii) मांग आपूर्ति में भारी अंतर है जो चीन जनगण से निर्यातकों को अपना सामान भारत को निर्यात करने के लिए मजबूर कर रहा है।
- ण. घरेलू उद्योग को गंभीरत क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती

- (i) याचिकाकर्ता द्वारा इस विचाराधीन मांग का निर्धारण भारत में इस उत्पाद के आयात, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू ब्रिक्री के रूप में की गई है। इसमें ग्राही खपत भी शामिल है जो इस मामले में मौजूद नहीं है। इस विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग में संपूर्ण क्षति अविध में वृद्धि हुई है।
- (ii) घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2012-13 तक वृद्धि होने के बाद गिरावट आई।

पैरामीटर/वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन	1,184	1,211	1,531	1,521

(i) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी वर्ष 2012-13 तक वृद्धि होने के पश्चात अभिनव अवधि में गिरावट आई है। उद्योग को भारत में पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद विगत दो वर्षों में कम कीमत के आयातों और आयातों में उद्रेक के कारण भारी अनप्रयुक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के केवल 45 प्रतिशत का ही उपयोग कर रही है।

पैरामीटर/वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
क्षमता उपयोग	44	45	56	46

- (ii) संवर्धित आयातों के कारण आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- (iii) घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वर्ष 2012-13 तक वृद्धि होने के पश्चात गिरावट आने लगी।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेल् बिक्री (एमटी में)	505	632	1036	999

- (iv) आयातों की उतराई कीमत (क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (ख) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से पर्याप्त कम है। आयात घरेलू कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे है। इस कीमत अधोरदन के परिणामस्वरूप कीमत निग्रहण हो रहा है।
- (v) घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा सहन किए गए इस घाटे में संपूर्ण क्षति अविध के दौरान वृद्धि होती रही।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाभ/हानि (रुपए/एमटी में)	-100.00	-198.76	-184.14	-593.15

(vi) निवेश पर अभिलाभ भी ऋणात्मक था और इसमें संपूर्ण क्षति अविध में गिरावट आई।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निवेश पर अभिलाभ (प्रतिशत) (अनुक्रमित)	-100	-155	-146	-549

त. घरेलू उद्योग द्वारा पहले से ही सहन की जा रही गंभीर क्षिति के अलावा सोडियम साइट्रेट के संवर्धित आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर बहुत अधिक है। विदेशी उत्पादकों के पास पर्याप्त अनप्रयुक्त क्षमता है। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी उत्पादक यथासंभव सीमा तक अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं।

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उतराई कीमत (औसत)	रुपए/एमटी	44.67	52.62	53.87	48.92
उतराई कीमत (औसत)	अनुक्रमित	100.00	117.80	120.67	109.51
घरेलू बिक्री कीमत (औसत)	रुपए/एमटी	100.00	123.58	114.00	125.32
	अनुक्रमित				

- थ. यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के आयात पहले से ही घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति कारित कर रहे हैं, और यदि रक्षोपाय शुल्क का तत्काल अधिरोपण वही किया जाता है तो उसके बढ़ने की अधिक संभावना है।
- द. घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि :
  - (i) इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है;
  - (ii) आयात घरेलू कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे हैं।
  - (iii) यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, फिर भी घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, आयात घरेलू कीमतों का निग्रहण कर रहे थे।
  - (iv) आयातों में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है;
  - (v) आयातों के कारण घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री यात्रा, लाभ, भारी क्षति और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ के रूप में गंभीर क्षति हुई है।
- ध. क्षिति कारित करने वाले अन्य कारक
  - विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को खित मांग में गिरावट के कारण नहीं आई।
  - (ii) इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रणाली से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खपत की प्रणाली में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति में कोई योगदान नहीं हो सकता है।
  - (iii) ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने में अपना योगदान दिया हो।
  - (iv) इस उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास इस मामले में क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।

- (v) क्षिति का विश्लेषण केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में है। इसलिए, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग की क्षिति का संभावित कारण नहीं है।
- (vi) घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति विचाराधीन उत्पाद के कारण नहीं है। याचिकाकर्ता ने आंकड़ों को प्रथम किया है और केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़े प्रदान कराए हैं।

#### न . कारणात्मक लिंक

- i. हाल की अवधि में घरेलू बाजार में आयात के परिमाण में अचानक और तीव्र वृद्धि हुई है।
- ii. आयात का परिमाण बहुत अधिक है और संपूर्ण इंजुटी अवधि में वृद्धि की रुझान प्रदर्शित करता है
- iii. भारतीय उत्पादन और मांग के संबंध में आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- iv. हाल ही में, उत्पादन, विक्रय और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। भारत में महत्वपूर्ण आयात की दृष्टि से बिना उपयोग की क्षमताओं की महत्वपूर्ण मात्रा की समस्या से घरेलू उद्योग जूझ रहा है।
- v. आयात के परिणामत: (i) कीमत का दबाव (ii) वित्तीय हानि (iii) नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न (iv) घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता के कम-उपयोग हुए हैं।
- vi. आयात के परिमाण में वृद्धि हुई है और भारत के उत्पादन और उपयोग के संबंध में यह महत्वपूर्ण है, इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में जहां आयात के बाजार अंश तेजी से बढ़े हैं, भारतीय उद्योग के अंश में कमी आयी है और ये कम रहें।
- vii. कम मूल्य पर आयात से कीमतों पर दबाव पड़ा है, जिससे लाभ की संभावना में कमी आई है।
- viii. घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी, कम स्तर की उत्पादकता, क्षमताओं के कम-उपयोग और वित्तीय हानि की समस्याएं झेल रहा है।

## प. जन हित

- ं. जन हित पर सुरक्षोपाय के प्रभाव का सामान्यत: तीन अलग पक्षों- उत्पादक, उपभोक्ता और सामान्य जनता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में विचार करने पर वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा।
- विचाराधीन उत्पादों के आयात पर रक्षोपाय मुख्य घरेलू निर्माताओं के हित में होगा। बढ़े हुए आयात
  परिमाण से घरेलू उद्योग को आगे होने वाली क्षति को इन उपायों द्वारा रोका जाएगा। घरेलू उद्योग को
  अत्यधिक क्षति हो रही है और रक्षोपाय शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को इस क्षति से निजात मिलेगी।
- iii. सुरक्षोपाय शुल्क लगाना घरेलू उपभोक्ताओं के हित में होगा, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने और विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता वाले प्रतिस्पर्धी भारतीय घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं के हित में है, यह तभी संभव है जब बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से यह उबर सके।
- iv. सशक्त और प्रतिस्पर्धी भारतीय घरेलू उद्योग व्यापक स्तर पर जनहित में है। बढ़े हुए आयात से होने वाली क्षति को बिना रोके यह संभव नहीं है।
- v. सोडियम साइट्रेट के उपभोग वर्ग निम्नांकित है -:

उपभोग वर्ग	लगभग उपभोग (एम टी)
चीज	प्रिजरवेटिव के रूप में
कफ सिरप	एक्स पेक्टोरेंट के रूप में
सॉफ्ट ड्रिंक्स	लवणीय एवं तीखे स्वाद के रूप में
जेली	लवणीय एवं तीखे स्वाद के रूप में
फोटोग्राफिक उद्योग	एंटी कगुरलेंट के रूप में

फर्माष्युटिकल उद्योग बी	एंटी कगुरलेंट के रूप में
पेय	लवणीय और तीखे स्वाद के रूप में

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

vi. उपभोक्ता वर्ग में अंतोत्पाद की लागत पर परिणामी प्रभाव महत्वहीन है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न युजर सेकटर पर इस प्रभाव की विस्तृत लागत दी गई है। घरेलू उत्पादों, घरेलू उपभोक्ताओं और सामान्य जनता के हितों को जनहित के रूप में समझा जा सकता है। इस संबंध में, अंततोगत्वा अंत्योत्पाद पर लगभग नगन्य प्रभाव का विचार करते हुए और यह विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग की उत्तर जीविता आवश्यक है, यह निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क जनहित में है।

#### v. समायोजन योजना

- i. याचिकार्ता की वर्तमान क्षमता 3300 एम टी है। याचिकाकर्ता की योजना क्षमता के वर्तमान स्तर को क्रिमिक रूप बढ़ा कर 6600 एम टी प्रतिवर्ष करने की है।
- ii. उच्चतर परिमाण को परिणामत: कच्चे माल की और अधिक आावश्यकता/ इसे और अधिक संसाधित करने की आवश्यकता होगी। इससे कंपनी कच्चे माल आपूर्तकर्ताओं से तिमाही संविदा निष्पादित कर सकेगी। कंपनी को मोल-जोल करने की शक्ति प्राप्त होगी और इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे उत्पादन की लागत में कमी आएगी।
- iii. वर्तमान सेटअप जैसे, कन्वेयर वेल्ट, एफ एस एस (फील, शील, स्टीच) मशीन आदि के आटोमेशन द्वारा कंपनी और अधिक क्षमता एवं उत्पादन प्रापत कर सकेगी। इसके परिणामत: कम संख्या में कामगार और अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकेंगे। इस आटोमेशन से श्रम लागत, मरम्मत और अंडरकवर लागत, विनिर्माण व्यय, उत्पादन की प्रति इकाई अवमूल्यकन के संदर्भ में लागत में बचत होगी।
- iv. कंपनी सौर ऊर्जा को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहती है। इससे ऊर्जा लागत में कमी आएगी।
- v. क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रशासन और विक्रय मानवशक्ति में भारी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी।

# 16. मैसर्स बांग फर्माष्युलिटकल्स एंड कैमीकल्स द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2014 के उनके पत्र के माध्यम से लिखित अनुरोध इस प्रकार है:-

- क. आयात के बढ़े हुए परिमाण के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बंद हो सकते हैं।
- ख. यदि देश में इस उत्पाद की मांग दो गुनी या तीन गुनी बढ़ जाती है, जैसा कि इस रक्षोपाय शुल्क का विरोध करने वाले प्रतिनिधिगण दावा करते हैं, तो भी घरेलू उद्योग के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करना कठिन नहीं होगा।
- ग. चूंकि <u>द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया</u> ने सोडियम साइट्रेट के बिना पंजीकृत प्रक्रिया के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, देश में इस पदार्थ का ''<u>फर्मा/चिकित्सा उपयोग के लिए नहीं''</u> नाम आवेदन लगाकर/बताकर भारी मात्रा में आयात हो रहा है। वास्तव में, उत्पाद ऐसा है जिसे और आगे प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता है। आयातक इस आशय के दावे मात्र विनियमनों और निषेधों से बचाने के लिए करते हैं।
- **ध**. मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस दावे के विषय में आवेदन के प्रति यह कहा जा सकता है कि यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि पिछले कई वर्षों से इस उत्पाद की उत्पादक-कंपनी होने के दावा करने वाली कंपनी इस सुरक्षोपाय शुल्क का विरोध कर रही है। इतने पुराने उत्पादक द्वारा सुरक्षोपाय शुल्क का विरोध किए जाने के पीछे तार्किकता नहीं हो सकती है।
- उनके इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है कि इस देश में इस उत्पाद को उत्पादित करने की आवश्यकता नहीं है और चीन से इसके आयात किए जाने में व्यापक जनहित है।
- च. एकाधिकार के दावे के पीछे या इस तर्क के पीछे कि सरक्षोपाय शुल्क लगाने से अंत्योत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि होगी, कोई सच्चाई नहीं है। इन पक्षधारियों द्वारा ऐसे सभी कथन देश के बृहत्तर हितों के नाम

- पर गलत है और इन पक्षधारियों का वास्तविक उद्योग कम कीमत पर उत्पाद का आयात करना और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है।
- छ. संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2009-10 में चीनी उत्पादों पर 90 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक की एंटी शुल्क लगाए। यदि अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली और विकसित अर्थव्यवस्था अपने उद्योग की सुरक्षा के लिए एंती डंपिंग शुल्क लगाना आवाश्यक समझती है तो भारत भी रक्षोपाय शुल्क न लगाए जाने का कोई करना नहीं हो सकता।

## 17. मैसर्स सुनील कैमीकल्स द्वारा 17 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से लिखित अनुरोध:-

- (क) हम पोसी फर्माचेम के साथ पूरी तरह सहमत हैं कि यह उत्पाद बढ़ी हुई मात्रा में आयात की जाती है जिससे भारतीय उद्योग को भारी क्षति होती है।
- (ख) देश में इस उत्पाद की पर्याप्त मांग है और देश में इसके आयात की आवश्यकता नहीं है।
- (ग)कुछ आयात तो "फर्मा/चिकित्सा उपयोग हेतु नहीं" बताकर किए जाते हैं। यह दावा किया जाता है कि इन आयितत वस्तु का आगे और प्रसंस्करण किया जाता है और भारतीय बाजार में दवा या खाद्य अनुप्रयोगों हेतु इस उत्पाद को बेचा जाता है। तथापि, तथ्य यह है कि आयितत सामग्री का प्रसंस्करण नहीं किया जाता है और इसको दवा या खाद्य स्तर के उत्पाद के रूप में ठहराने के लिए इसका महज रिपैकिंग किया जाता है। वास्तव में यह उत्पाद ऐसा है कि इसका आगे और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। आयातक केवल विनिमयन और निषेध से बचने के लिए ऐसे दावे करते हैं।
- (घ)यह आश्चर्य का विषय है कि एक कंपनी, जो पिछले कई वर्षों से इस उत्पाद का उत्पादक होने का दावा करती है, वही रक्षोपाय शुल्क का विरोध कर रही है। ऐसे पुराने उत्पादक द्वारा इस रक्षोपाय शुल्क का विरोध किए जाने के पीछे तार्किकता नहीं हो सकती है। सुनवाई के दौरान पोशी फर्माचेम के निर्यात द्वारा ठीक ही बताया गया था कि यह विभिन्न कारणों से किया जा रहा है- (क) इस उत्पाद को अमेरिकी बाजार को निर्माण करने हेतु, जहां चीनी उत्पाद एंटी डंपिंग शुल्क का सामना कर रहे हैं; (ख) देश में कम कीमत के आयात का लाभ लेना और देश में इसके उत्पादन से अर्जित लाभ के बदले दूसरे व्यापार के जिए अधिक लाभ कमाना।
- (ङ) एकाधिकार का दावा या इस तर्क के पीछे कोई सच्चाई नहीं है कि अंत्योत्पादों की कीमतों में इस सुरक्षोपाय से भारी वृद्धि होगी। इन पक्षों द्वारा देश के बृहत्तर हितों के नाम पर कहे गए सभी कथन गलत है और इनका वास्तविक उद्देश्य कम-कीमत की वजह से वस्तु का आयात करना और देश में इस उत्पाद का उत्पादन करने के बदले इसका व्यापार कर और अधिक मुनाफा कमाना है।
- (च)इन पक्षों द्वारा यह दावा करना अत्यधिक विरोधाभासपूर्ण है कि वे आयितत सोडियम साइट्रेट का अत्यधिक प्रसंस्करण कर उसे फर्मा ग्रेड का बनाते हैं और जब हम भी पूर्ण उत्पादन गतिविधि अपना कर इस उत्पाद का उत्पादन करते हैं तो वे कहते हैं कि उत्पादित सोडियम साइट्रेट का हम कोई व्यापक प्रसंस्करण नहीं करते हैं। यह ऐसी कंपनियों के विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दिखलाता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य कम-कीमत के आयात से लाभ उठाना और आयितत उत्पाद का व्यापार कर ऊंचा लाभ कमाना है।
- 18. मैसर्स इशिता ड्रग्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से लिखित अनुरोध: क. याचिकाकर्ता ने ट्राई सोडियम साइटेट, मोनो सोडियम साइट्रेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट को गलती से एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है जबिक ये सभी उत्पाद अलग प्रकार के रासायनिक गुणधर्मिता एवं अलग अध्याय शीर्ष तथा मॉलीक्यूलर फॉर्मूला के हैं। ये तीनों उत्पाद अलग हैं एवं अनूठी रासायनिक अस्तित्व के हैं जिनके अलग रासायनिक गुणधर्मिता हैं एवं अलग अध्याय शीर्ष संख्या और अलग-अलग मॉलीक्यूलर सूत्र हैं।
- ख. 100 प्रतिशत आयातित उत्पाद चिकित्सीय प्रयोग के नहीं हैं। इन आयतित उत्पादों का और आगे रासायनिक प्रसंस्करण किया जाता है ताकि इसे फर्मा उपयोग हेतु उपयुक्त बनाया जा सके। अतएव, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी सामग्री नहीं है।

- ग. यह दावा कि याचिकाकर्ता एवं सुनील कैमीकल भारतीय उत्पाद का 90 प्रतिशत भाग संसाधित करता है, विश्वसनीय नहीं है। भारतीय उत्पादों पर मूल अधिसूचना में उल्लिखित सूचनाओं के यह विरुद्ध है।
- घ. आयात में वृद्धि डी आई के उत्पादन के लगभग बराबर है। आयात में वृद्धि तुलनात्मक संदर्भों में भी व्यापक नहीं है।
- ङ कोई गंभीर क्षति नहीं। कुल उत्पादन के संबंध में डी आई का उत्पादन उत्पादन की कुल वृद्धि से कम है। याचिकाकर्ता इसके उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता है।
- च. याचिकाकर्ता द्वारा विक्रय एवं विपणन शेयर की जानकारी दी गई है जो गलत है क्योंकि इसमें भारतीय विनिर्माताओं द्वारा सोडियम साइट्रेट के निर्यात विक्रय को नजरअंदाज किया गया है जिसे परिकलित मांग में शामिल किया जाना चाहिए। मैसर्स इशीता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज ने (वाणिज्यिक विभाग की वेबसाइट से लिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नांकित) टेबल में बदलाव किया है। मूल अधिसूचना के पृष्ठ सं. 3 पर दिए गए टेबल में डी आई के विक्रय में 140 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा विपणन शेयर 50 प्रतिशत बढ़ा है।

वर्ष	आयात	डी आई का घरेलू विक्रय	अन्य भारतीय उत्पादकों के विक्रय	सभी भारतीय उत्पादकों के निर्यात	कुल मांग (घरेलू एवं निर्यात)	विपणन शेयग	Ţ
						डी आई	आयात
2010-11	2621	505	1454	704	2663	10%	50%
2011-12	2877	632	1769	690	3091	11%	48%
2012-13	3721	1036	1787	1067	3890	14%	49%
2013-14	4791	1214	1236	1232	3682	15%	57%

## आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाइट से लिए गए।

- छ. प्रणाली में अंतरनिहित अक्षमताओं से अधिक डी आई पेपरिंग की हानि हटाने हेतु रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाये जा सकते।
- ज. अंडरकटिंग के दावे को पुष्ट करने हेतु माह-वार/तिमाही-वार आयात शुल्क के आंकड़ों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जहां विनिमय दर व्यापक रूप से बदलती रहती है एवं अतिपरिवर्तनशील है औसत मूल्य स्वीकार्य नहीं है। आयातित वस्तुओं के बिल, अलग-अलग महीनों के आयात इन्वाइसों की मांग की जानी चाहिए।
- झ. निष्क्रिय क्षमता को सीधे सोडियम साइट्रेट से नहीं जोड़ा जा सकता। सोडियम साइट्रेट एक पुराना उत्पाद है और एक कदम में निर्मित की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के तहत इसका उत्पादन होता है। इसके लिए विशेषीकृत साजो-सामान की जरूरत नहीं होती। सोडियम साइट्रेट के निर्माण हेतु उपयोग किए गए साजो-सामान भारी मात्रा में अन्य ड्रगों के रासायनिक उत्पादन में उपयोग किए जा सकते हैं। क्षमता में वृद्धि हेतु कोई नया निवेश नहीं किया गया है।
- ञ. सोडियम साइट्रेट की लागत एवं विक्रय साइट्रिक एसिड पर निर्भर है जो भारत में आयात किया जाता है। भारतीय विनिर्माताएं साइट्रिक एसिड के आयात मूल्य एवं उसमें कमी या वृद्धि से प्रभावित होते हैं।
- ट. सोडियम साइट्रेट कम सीमांत उत्पाद है। उदारीकरण के समय से सोडियम साइट्रेट के विनिर्माताओं ने, चाहे आयात के जो भी स्तर हों, बहुत कम ही लाभ प्राप्त किए हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सोडियम साइट्रेट की निर्माण-प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसमें विशेष साजो-सामान हेतु निवेश की आवश्कता नहीं है। सोडियम साइट्रेट के आयात में वृद्धि का परिणाम कम लाभ प्राप्त होना नहीं है।
- ठ. यह नहीं बताया गया कि दावा किए गए अंडरकटिंग विदेशी कंपनियों या भारतीय आयातकों द्वारा सोडियम साइट्रेट के विक्रय के कारण हुई है।

- ड. सोडियम साइट्रेट का निर्यात करने वाली कंपनी साइट्रिक एसिड (कच्चा माल) उत्पादन भी करती है और उनकी लागत स्वभाविक तौर पर कम है।
- ढ. सोडियम साइट्रेट आई पी आई बी पी आई वी एस पी (फर्मा ग्रेड), जो कि याचिका द्वारा विनिर्मित किया जाता है, का मुख्य उपयोगों में से एक जीवन रक्षक को आर एस सैचेट्स के निर्माण में होता है। इनके मूल्यों में भारी वृद्धि होगी। चूंकि सोडियम साइट्रेट जीवन रक्षक ओ आर एस सेचेटो, बटर, पनीर इत्यादि सामान्य उपयोग की वस्तुओं में अधिकांशत: उपयोग किए जाते हैं, इन वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी।
- ण. प्रत्येक खाद्य मद के मूल्य भी रक्षोपाय शुल्क के कारण बढ़ेगे जिससे खाद्य सामग्री की मुद्रास्फीति की समस्या में बढ़ोतरी होगी।
- त. इस रक्षोपाय शुल्क के कारण भारत द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों पर अन्य देशों द्वारा बदले की कार्रवाई की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि होगी एवं कुछ उद्योगों को भी क्षति पहुंचेगी।
- थ. कोई ठोस समायोजन योजना नहीं दी गई है। केवल क्षमता विस्तार की योजना पर्याप्त नहीं है क्योंकि सभी विनिर्माताएं साइट्रिक एसिड पर निर्भर करते हैं। प्रस्तावित क्षमता विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमता के मात्र छोटे से प्रतिशत अंश के विषय में ही हागी।
- द. भारत में सोडियम साइट्रेट की कुल मांग (इसकी घरेलू मांग एवं आयात को शामिल कर) की पूर्ति व्यापक रूप से आयात के माध्यम से होती आ रही हैं और यह अचानक एवं बिल्कुल हाल की घटना नहीं है।
- ध. संयुक्त राज्य अमेरिका में ए डी डी लगाए जाने का विषय इससे संगत नहीं है। वहां ए डी डी लगाया जाना साइट्रिक एसिड पर ए डी डी लगाए जाने के विस्तार के अंतर्गत ही है तथा वहां इसकी विशाल क्षमता उपलब्ध है। अमेरिका ने साइट्रिक एसिड और सोडियम साइट्रेट के विनिर्माताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ये शुल्क लगाए हैं जबिक भारत के पास साइट्रिक एसिड की क्षमता उपलब्ध नहीं है एवं सोडियम विनिर्माता सदैव ही साइट्रिक एसिड पर निर्भर करेंगे।

# 19. मैसर्स प्रकाश कैमीकल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के दिनांक 17 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से लिखित अनुरोध निम्नांकित है।

- क. अन्वेषण की अवधि पी ओ आई (2011-14) के दौरान विक्रय परिमाण या मात्रा के संदर्भ में उनके व्यापार में वृद्धि हुई।
- ख. सोडियम साइट्रेट के बाजार में 20 से 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि हो रही है और एक या दो वर्षों के भीतर ही यह मांग 15000 एम टी से अधिक हो जाएगी जो याचिकाकर्ता एवं इसके समर्थकों द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते।
- ग. केवल 2 या 3 विनिर्माताओं के हितों को, जो सुरक्षोपाय शुल्क की वजह से अधिक ऊंचा मुनाफा कमाने का एक मात्र उद्देश्य रखते हैं, सुरक्षित करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इससे सोडियम साइट्रेट की लागत में भारी वृद्धि से 1000 से अधिक अंत उपभोक्ताओं को भारी हानि होगी।
- घ. एक समान उत्पाद के संबंध में वही विनिर्माताएं सुरक्षोपाय एवं एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों लगाने की मांग नहीं कर सकते हैं।
- ङ यदि 25 छोटे एवं बड़े विनिर्माताओं से अधिक सर्वाइव कर सकते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं है तो दो या तीन विनिर्माता केवल प्रतिस्पर्धी बाजार में कौशल एवं क्षमता की कमी के कारण पिछड़ रहे हैं।
- च. सोडियम साइट्रेट के कुछ और उपयोग हैं जिसके लिए 25 प्रतिशत उपभोग वृद्धि दर से अधिक दर पर उपभोग हो रहा है और जो याचिकाकर्ता द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है।
- (छ) कुल भारतीय उपभाग, अन्य विनिर्माताओं एवं बहुद्देश्यीय उत्पादन संयंत्र एवं उपस्कर, जिसको सोडियम साइट्रेट की संस्थापित क्षमता के रूप में दर्शाया जा रहा है, के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।
- (ज) प्रति वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक सोडियम साइट्रेट की बढ़ रही मांग से आयात एवं घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है।
- (झ) पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग बाजार अंश वृद्धि दर (52%) की तुलना में आयातित उत्पाद बाजार अंश (16%) स्थिर है।

- (ञ) कुछ और उद्योग हैं जो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जहां 25% से अधिक उपभोग वृद्धि दर है और याचिकाकर्ताओं ने इसकी तथा विभिन्न उद्योगों अर्थात् साबुन एवं डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स, सेरामिक्स उद्योग तथा पशु आहार उद्योग में नए एप्लीकेशन की भी अनदेखी की है।
- (ट) घरेलू उत्पादन में कमी का कोई प्रमाण नहीं है इसलिए बिक्री एवं उत्पादन के संदर्भ में कोई नुकसान नहीं है। पी ओ आई के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि दर 25% है, आयातों से बाजार अंश की वृद्धि दर 16% है। केवल लाभ आंकड़ा से याचिकाकर्ता पर कुछ नकारात्मक प्रभाव का पता चलता है जो विश्वसनीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता दस से अधिक उत्पादों का विनिर्माता है।
- (ठ) याचिकाकर्ता ने उत्पादों या सोडियम साइट्रेट के लिए संयंत्र उपयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, इसका औचित्य बताना बहुत ही कठिन है कि उनकी संपूर्ण संयंत्र क्षमता एवं कर्मचारी केवल सोडियम साइट्रेट के विनिर्माण के लिए लगाए गए थे।
- (ड) याचिकाकर्ता की वेबसाइट से याचिकाकर्ता के विभिन्न उत्पादों के विनिर्माता/बिक्रेता होने का पता चलता है। उनकी संस्थापित संयंत्र क्षमता का उपयोग कई उत्पादों द्वारा किया जाता है जो मांग एवं आपूर्ति आंकड़े को समझने के लिए प्राधिकारी को भ्रमित कर रहा है।
- (ढ) अन्य उत्पादक समझते हैं कि साइट्रिक एसिड मोनोहाईड्रेट को खरीदना तथा 'मूल्यवान संसाधनों जैसे कि व्यक्ति एवं मशीनरी का उपयोग करके छोटे पूंजीगत निवेश से प्रक्रिया को प्रदान करना बुद्धिमानी वाला व्यवसाय नहीं है जब अंतिम उत्पाद "सोडियम साइट्रेट" समान मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।
- (ण) सोडियम साइट्रेट कच्ची सामग्री ''साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट तथा अंतिम उत्पाद ''सोडियम साइट्रेट'' का मूल्य समान है। अंतिम उत्पाद के समान मूल्य पर कच्ची सामग्री का आयात करने तथा उसके बाद सोडियम साइट्रेट का उत्पादन करने के लिए हमारे मूल्यवान संसाधनों जैसे कि व्यक्ति, मशीनरी, ऊर्जा एवं कौशलों का उपयोग करने में कोई आर्थिक तर्क नहीं है।
- (त) रक्षोपाय (सेफगार्ड) ड्यूटी लगाने के परिणामस्वरूप साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट की मांग में वृद्धि होगी जिससे साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के मूल्य में वृद्धि होगी जिससे साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के घरेलू उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (थ) सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है।
- (द) आयातित सोडियम साइट्रेट के प्रतियोगी मूल्य के कारण कई नए उद्योगों ने सोडियम साइट्रेट का उपयोग करना शुरू कर दिया है तथा आज के विश्व बाजार में प्रतियोगी हो गए हैं। रक्षोपाय ड्यूटी लगाने के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के बहुत बड़े समुदाय का प्रचालन अव्यवहार्य हो जाएगा।
- (ध) यदि सरकार घरेलू उद्योग को सहयोग देना चाहती है तो रक्षोपाय ड्यूटी साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के मूल्य के संदर्भ में होनी चाहिए।
- (न) रक्षोपाय ड्यूटी रसायन एवं उत्पादन मानदंडों का 10 प्रतिशत आधार होनी चाहिए, साइट्रिक एसिड को सोडियम साइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के मूल्य की तुलना में केवल 3-4 प्रतिशत अतिरिक्त लागत है।
- (प) सोडियम साइट्रेट विनिर्माताओं को साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक मूल्य लेने की अनुमित दी जानी चाहिए ताकि मुद्रास्फीति तथा सोडियम साइट्रेट के घरेलू उपभोक्ताओं को होने वाले अन्याय को नियंत्रित किया जा सके।
- 20. मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में 21 जुलाई, 2014 के पत्र के तहत घरेलू उद्योग द्वारा रिज्वाइंडर प्रस्तुत करना, जो निम्नवत है:
- क. डाइ-सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट को विचाराधीन उत्पाद के रूप में शामिल नहीं किया गया है। सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डाइसोडियम साइट्रेट तथा ट्राइसोडियम साइट्रेट के रूप में आते हैं। मोनो, डाई एवं ट्राई सोडियम साइट्रेट केवल विचाराधीन उत्पाद के रूप में है जिनके समान भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा समान सीमा शुल्क वर्गीकरण होते हैं। इन उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया एवं

- उत्पादन प्रौद्योगिकी समान होती हैं। उपभोक्ता भी उनको आपस में बदलकर उपयोग करते हैं जिससे पता चलता है कि वे एक तथा समान हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी एवं समान उत्पाद हैं।
- ख. यह उल्लेख किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की गई वस्तुएं सभी प्रकार के उद्योगों जैसे कि फार्मा/खाद्य/कीटनाशक/सेरामिक आदि के लिए हैं। किसी भी स्थिति में सच यह है कि आयातित सामग्री का कोई प्रसंस्करण नहीं होता है तथा उत्पाद को फार्मा या खाद्य ग्रेड के उत्पाद के रूप में दावा करने के लिए केवल दोबारा पैक किया जाता है। वास्तव में, आयातित उत्पाद ऐसा होता है जिसे आगे प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता है।
- ग. वास्तविकता यह है कि कई कंपनियां, जो विचाराधीन उत्पाद को बेच रही हैं, वास्तव में उत्पाद का आयात कर रही हैं और उनको बेच रही हैं। तथापि, याचिकाकर्ता ने रूढिवादी नीति के रूप में अपनी बिक्री को अपना उत्पादन समझा है।
- घ. पूर्ण रूप में आयातों में काफी वृद्धि हुई है। आयात में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जबिक उत्पादन में नुकसान अविध में केवल 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे भी पता चलता है कि जांच को बाधित करने के इरादे से इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भ्रामक विवरण दिए गए हैं।
- ङ. इस तर्क के विरुद्ध कि कुल भारतीय उत्पादन इस हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में काफी नहीं बढ़ा है, यह उल्लेख किया जाता है कि सच यह है कि अन्य भारतीय उत्पादक क्रमिक रूप से व्यापार में चले गए हैं। मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के व्यवहार से भी यही साबित होता है।
- च. यह देखा जाएगा कि जबिक विचाराधीन उत्पाद की मांग सकारात्मक है एवं बढ़ रही है, घरेलू उद्योग बिक्री 2012-13 तक बढ़ी और 2013-14 में घटी। घरेलू उद्योग के समक्ष माल के काफी इकट्ठा होने की समस्या है और वे माल को परिसमाप्त करने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए बाध्य हुए हैं।आयात का बाजार अंश बढ़ा है। लिखित रूप में दिए गए आयात के बाजार अंश संबंधी आंकड़े में टंकण संबंधी त्रुटि है। सही आंकड़ा निम्नवत है:
- छ. घरेलू उद्योग की बिक्री 2012-13 तक बढ़ने के बाद घटी है। घरेलू उद्योग का बाजार अंक घटा है जबिक आयात का बाजार अंक बढ़ा है। लिखित रूप में दिए गए आयात के बाजार अंश संबंधी आंकड़े में टंकण संबंधी त्रुटि है। सही आंकड़ा निम्नवत है:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	505	632	1036	999
(मिट्रिक टन)				
मांग	4,580	5,278	6544	7,705
आयात	2,621	2,877	3721	5,300
मांग में बाजार अंश				
याचिकाकर्ता	11%	12%	16%	13%
अन्य उत्पादक एवं समर्थक	32%	34%	27%	18%

ज. इस तर्क के उत्तर में कि निर्यात बिक्री का विश्लेषण किए जाने तथा मांग में इसे शामिल किए जाने की जरूरत है, यह उल्लेख किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार में रक्षोपाय (सेफगार्ड) कानूनों की समझ की कमी है। रक्षोपाय जांच के लिए आवश्यक संगत सूचना घरेलू बाजार से संबंधित है। निर्यात बिक्री घरेलू बाजार में बाजार अंश अवधारित करने में असंगत हैं। मांग एवं बाजार अंश का मूल्यांकन घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की मांग तथा आयातों के अंश और घरेलू बाजार में इस मांग के याचिकाकर्ताओं से संबंधित हैं। निर्यात बिक्री को मांग में शामिल करना और फिर बाजार अंश का आकलन करना असंगत है। कानून के अंतर्गत यह अनुमेय नहीं है। हितबद्ध पक्षकार केवल प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है जिन्होंने लगातार मांग को कुल आयातों, घरेलू उद्योग की बिक्री और सभी अन्य उत्पादों (कैप्टिव उपयोग सहित, यदि कोई हो) की बिक्री का योग माना है। निर्यात को पृथक माना जाता है। इसलिए, इसका कोई संबंध नहीं है।

- झ. घरेलू उद्योग ने बिक्री एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं, जिनके परिणाम मात्रा संबंधी मानदंडों में देखा जा सकता है, तथापि, ऐसे प्रयास किए जाने के बावजुद इसमें हाल की अवधि में कमी आई है।
- ञ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किन्ही निहित अक्षमताओं की पुष्टि नहीं की गई है। मौखिक सुनवाई के समय याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्रमुख मुद्दा यह है कि क्यों मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उत्पाद का विनिर्माण रोक दिया है और उत्पादन क्षमता के बावजूद चीन से उत्पाद का आयात करना शुरू कर दिया है।
- ट. कानून के अनुसार लगातार कार्य पद्धित का अनुपालन किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, वास्तव में माह-वार या तिमाही-वार विश्लेषण मुद्रा दर में काफी उतार-चढ़ाव के कारण भ्रामक होगा। मुद्रा दर में काफी उतार-चढ़ाव से वास्तव में अत्यधिक विकृत स्थिति का पता चलता है।
- ठ. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र समर्पित किया है जिसका सत्यापन मौके पर जांच के दौरान भी किया गया। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए याचिकाकर्ता की क्षमता समर्पित है, इसलिए सक्रिय क्षमता का दावा सीधे बढ़े आयात के कारण है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों ने सुनवाई के समय कहा कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में अधिक निवेश शामिल नहीं है। न ही क्षमता स्थापित करना या उसका संवर्धन विचाराधीन उत्पाद में एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा होने पर, किसी भी स्थिति में, घरेल उद्योग द्वारा नया निवेश महत्वपूर्ण मानदंड नहीं है।
- ढ. तथापि, हितबद्ध पक्षकार के तर्कों के विपरीत, और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए तथा पी यू सी की बढ़ती मांग में वृहतर अंश पर कब्जा करने के विधिसम्मत पूर्वानुमान से याचिकाकर्ता ने पहले ही मार्च, 2014 में एक नई मशीन खरीद ली है। अब क्षमता बढ़कर 5000 मिट्रिक टन हो गई है। यह याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को दी गई व्यवहार्य समायोजन योजना के अनुकरण में है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह प्रायोगिक उत्पादन के अधीन है तथा याचिकाकर्ता की स्थित में सुधार होने के बाद ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा।
- ण. यदि यह भी मान लिया जाए कि यदि उत्पाद निम्न मार्जिन वाला है तो घरेलू उद्योग को गंभीर हानियां हो रही हैं, लाभ की तो बात ही छोड़ दीजिए जैसा कि नीचे तालिका से देखा जा सकता है :

2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(100)	(199)	(184)	(593)
(100)	(249)	(378)	(1,174)
	(100)	(100) (199)	(100) (199) (184)

वास्तव में दावा से घरेलू उद्योग, जिसे कम मूल्य के आयात में वृद्धि से गंभीर नुकसान हो रहा है, को संरक्षित करने की जरूरत की पृष्टि होती है।

- त. मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दावा किया कि यह रासायनिक ग्रेड में उत्पाद को आयात करता है, "महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन" करता है और उसके बाद फार्मा एवं खाद्य अनुप्रयोग के लिए भारतीय बाजार में उत्पाद की बिक्री करता है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता अभी भी उच्च मूल्य पर, आयात मूल्य से भी अधिक, आयातित उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो कोई कारण नहीं है कि क्यों रक्षोपाय ड्यूटी लगाने से उपभोक्ताओं पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ेगा।
- थ. चीन को छोड़कर, आयात केवल कनाडा से हुए हैं। ऐसा होने पर, जब रक्षोपाय ड्यूटी अन्य विकासशील देशों पर लागू नहीं होगी तथा जब विकसित देशों ने उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, तो यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि प्रस्तावित ड्युटी का अन्य देश विरोध करेंगे।
- द. याचिकाकर्ता ने व्यवहार्य समायोजन योजना दी है जिसमें क्षमता के विस्तार एवं लागतों को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वास्तव में क्षमता के विस्तार को एक व्यवहार्य समायोजन योजना माना गया है।

- ध. सोडियम साइट्रेट पर ए डी डी लगाने से कम-से-कम यह पता चलता है कि चाइनीज उत्पादकों के लिए अपनी वस्तुओं को मुक्त रूप से जमा करने के लिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार उपलब्ध नहीं है। इसलिए, वे भारतीय बाजार को लक्ष्य बना रहे हैं, (ख) विश्व में एक सर्वशक्तिमान विकसित आर्थिकि ने 90-150 की उच्च एंटी इंपिंग ड्यूटी लगाकर अपने घरेलू उद्योग को संरक्षित करने को उपयुक्त माना है।
- न. हमारे आवेदन एवं निवेदन में दिए गए अनुसार, बढ़े आयातों के लिए अदृश्य घटनाक्रम/कारण का सारांश निम्नवत है :

क.	देशों में उत्पादकों की अधिक क्षमता।	घरेलू बाजार में अधिकांशतः	आयात चीन और बहुत हाल	त्र में कनाडा
	से हैं।			

	मात्रा (एम टी)			आयात का अंश				
देश	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आस्ट्रिया	-	2	5		0%	0%	0%	0%
चीन पी आर	2,578.00	2,804.00	3,526.00	4,350.48	98%	97%	95%	82%
कनाडा				699.60	0%	0%	0%	13%
जर्मनी	11.02	64.80	19.57	41.16	0%	2%	1%	1%
पोलैंड	0.05		0.17	0.95	0%	0%	0%	0%
स्पेन	23.00	4.90	165.04	90.01	1%	0%	4%	2%
थाईलैंड	4.00				0%	0%	0%	0%
यू के	4.40	0.38	0.30	0.50	0%	0%	0%	0%
यू एस ए	0.27	1.06	2.74	117.59	0%	0%	0%	2%
अविनिर्दिष्ट			2.00		0%	0%	0%	0%
कुल	2,620.74	2,877.21	3,721.12	5,300.29	100%	100%	100%	100%

यह उल्लेख है कि चीनी बाजार की अत्यधिक क्षमता है; अतएव वे सोडियम साइट्रेट का निर्यात कर रहे हैं। अमेरिका ने साइट्रिक एसिड और कतिपय साइट्रेट साल्ट्स, जिसमें सोडियम साइट्रेट भी शामिल हैं के आयातों के खिलाफ एंटी डंपिंग अन्वेषण किया है, जिसमें अधिकारियों ने पाया है कि चीन की क्षमता बहुत अधिक है। साइट्रिक एसिड और कतिपय साइट्रेट साल्ट की वर्ष 2010 हेतु अनुमानित क्षमता 2195911 एम टी है, जो अब तक, इसकी पूरी संभावना है, बढ़ गया है।

ख. मांग और पूर्ति के बीच महत्वपूर्ण अंतर

चीन ने घरेलू मांग से कहीं अधिक हेतु क्षमताओं का निर्माण किया है। मांग और पूर्ति में विद्यमान व्यापक अंतर निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है:

वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010
प्रत्यक्ष					
क्षमता	1443	1932	2047	2193	2195
उत्पादन	1247	1719	1807	1779	1834
अंतर	924	1259	1332	1190	1227
(उत्पादन-					
खपत)					

<sup>\*&#</sup>x27;000 पाउंड; स्रोत: फाइंडिग्स यू एस ए

- ग. विभिन्न देशों द्वारा सोडियम साइट्रेट पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क चीन और कनाडा से
- आयातित सोडियम साइट्रेट अमेरिका द्वारा लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क
  अमेरिका ने 2009 में चीन और कनाडा से आने वाले सोडियम साइट्रेट पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाए हैं। यह
  भी उल्लेखनीय है कि चीन पर 2009-10 में अमेरिका द्वारा लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क विभिन्न देशों में
  इसके व्यापार की धारा ही बदल दी है। पहले चीन इस उत्पाद को अमेरीकी बाजार में बेचता था, परंतु वर्ष
  2009-10 के बाद यह बंद/प्रतिबंधित हो गया है। तदनुसार, चीनी निर्यातकों ने नए बाजार की खोज शुरू
  कर दी और भारत में इस उक्त पी यू सी की बढ़ती मांग के कारण यह इसका एक स्वभाविक गंतव्य बन
  गया है। इससे घरेलू उद्योगों को हानि हुई है। जहां यह 2009-10 में लाभ की स्थिति में था, वहीं वर्ष
  2010-11 में पहली बार हानि हुई है और यह लगातार हानि में है, जो वर्ष 2013-14 में काफी बदत्तर हो
  - चीन से सोडियम साइट्रेट के निर्यात पर यूरोपीय संघ द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क
    यूरोपीय संघ ने, 01 दिसम्बर, 2008 के परिषद विनियमन (ई सी) सं. 1193/2008 के माध्यम से चीन
    से आयात होने वाले सोडियम साइट्रेट सहित सोडियम एसिड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। दिनांक
    30 नवंबर, 2013 को अवसान समीक्षा की शुरूआत भी की गई है जो अभी चल रही है।
    ई सी ने अपने प्रारंभिक जांच में जो अंतिम जांच में भी सही ठहराया गया था, निम्नांकित रूप से उत्पाद
    को विचाराधीन श्रेणी में रखा:-

संबंधित उत्पाद साइट्रिक एसिड (सोडियम साइट्रेट सिहत) जो विभिन्न अनुप्रयोगों, यथा-पेय, खाद्य, डिटरजेंट, कॉस्मेटिक्स एवं फर्माश्युटिकल्स हेतु एक्सीड्यूलेंट एवं पी एच नियामक है। इसका मुख्य कच्चा माल चीनी-मोलेसिस, टोपियोका, कॉर्न या ग्लूकोस (खाद्यान्न से प्राप्त) एवं कार्बोहाइड्रेड के सबमजर्ड मेक्रोवियल फर्ममेंटेशन के लिए विभिन्न एजेंट हैं।

यह भी उल्लेख है कि चीन के लिए यूरोपीय संघ ने भी बाजार को सीमित कर दिया और एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया। चीन को अपनी क्षमता से अधिक उत्पाद को अन्य अनुकूल गंतव्य को निर्यात करना है और भारत ने इसका आयात करना शुरू कर दिया।

- <u>चीन से सोडियम साइट्रेट के निर्यात पर ब्राजील द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क</u> चीन से सोडियम साइट्रेट उत्पाद के बढ़े हुए निर्यात की समस्या का शिकार ब्राजील का घरेलू उद्योग भी हुआ। अतएव ब्राजील उद्योग ने सी ए एम ई एक्स संकल्प संख्या 52 के माध्यम से चीन से आयात होने वाले सोडियम साइट्रेट पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि ब्राजील का बाजार भी चीनी उद्योग के लिए प्रतिबंधित हो गया एवं इसके कारण हाल की अवधि में भारत में चीन से निर्यात में वृद्धि हुई
- प. अतएव यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न देशों यथा अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं ब्राजील द्वारा चीन के खिलाफ एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के कारण इस उत्पाद का विभिन्न देशों में निर्यात की धारा ही बदल गई। प्रारंभ में चीन अमेरिकी, यूरोपीय संघ एवं ब्राजील के बाजारों में इस उत्पाद का निर्यात करता था। जो वर्ष 2009-10 के प्रतिबंधित हो गया। तदनुसार, चीनी निर्यातक नए बाजारों की तलाश में भारत को चुना जो उक्त पी यू सी की बढ़ती मांग के कारण एक सहज स्वभाविक गंतवय सिद्ध हुआ। इसके कारण घरेलू उद्योग की दशा बिगड़ गई। वर्ष 2009-10 जहां यह लाभ की स्थिति में थी वही वर्ष 2010-11 में पहली बार हानि दर्ज की; और यह हानि लगातार कायम है जो वर्ष 2013-14 में और बदत्तर हो गई।
- फ. भारतीय उद्योग देश में इस उत्पाद की मांग की पूर्ति की पर्याप्त क्षमता रखती है। वास्तव में ऐसे उत्पादक जो सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिए थे ही केवल रक्षोपाय शुल्क लगाने का समर्थन करते हैं और वे भारत की पूरी मांग को पूरा कर सकते हैं। साथ ही इसमें कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद में, चाहे समय-सीमा या पूंजी विनिवेश में, क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है।

ब. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आयात की बढ़ी हुई मात्रा के कारण आई गिरावट निम्नांकित तालिका से देखी जा सकती है:-

(एम टी में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रतिदिन	100	102	129	128
उत्पादकता (सूची में				
शामिल)				

## 21. प्रकाश कैमीकल द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग निम्नांकित रूप से अनुरोध किया है

- (क) अभिरुचि रखने वाले पक्षों ने स्वीकार किया है कि विचाराधीन उत्पाद की क्षमता का विस्तार एक बहुत लंबा या भारी पूंजी निवेश प्रक्रिया का विषय नहीं है। यदि बाजार को सुरक्षित रखा जाता है तो मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां भी उत्पादन में वापस जुट जाएंगी। जैसा कि इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कहा गया है कि वे बहुत समय तक इसके उत्पादन करते रहे हैं। विनिर्माण की तुलना में व्यापार से अधिक लाभ कमाना ही उनको उत्पादन से हटा रहा है। अतएव मांग में वृद्धि घरेलू उद्योग के द्वारा पूर्ति की जा सकती है।
  - (ख) एक ऐसी स्थिति का अनुमान लगाते हुए जहां घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रतिबद्ध क्षमता नहीं है और इनकी क्षमताओं का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए किया जा रहा है, घरेलू उद्योग को कानून के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है। महानिदेशक (रक्षोपाय) ने पहले सिफारिश की थी और भारत सरकार ने आयात, उदाहरणस्वरूप 304 श्रंखला के हॉट रॉल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादों के आयात पर, जहां घरेलू उद्योग के पास प्रतिबद्ध क्षमता नहीं थी, रक्षोपाय शुल्क लगाया था।
- (ग) याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि 25 घरेलू उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने उन कंपनियों की सूची उपलब्ध कराई है, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं और यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता और समर्थक मिलकर भारतीय उत्पाद का 90 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। अत: कैसे मैसर्स प्रकाश केमिकल्स ने इस प्रकार का बयान दिया है कि विर्निर्माता, कौशल का अभाव तथा प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहने की समस्या से जूझ रहे हैं, यह समझ से परे है।
- (घ) भारतीय मांग, भारतीय उत्पादक का विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त आरंभिक अधिसूचना में, भारत में उत्पाद की कुल मांग और भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद भी अधिसूचित किया गया है। याचिकाकर्ता के पास प्रतिबद्ध उत्पादन संयंत्र है। प्रकाश कैमिकल्स एक व्यापारी हैं और उन्हें तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है।
- (ङ) मौखिक सुनवाई के समय याचिकाकर्ता द्वारा एक प्रमुख मुद्दा यह उठाया गया कि क्यों मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उत्पाद का निर्माण बंद कर दिया और उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद चीन से उत्पाद के आयात की ओर क्यों मुड़ गया है। जबिक सुनवाई के समय कंपनी के मालिक मौजूद थे फिर भी कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। अंतत: कंपनी ने यह स्वीकार किया कि वह उत्पाद का आयात कर रहा है और खाद्य और फार्मा क्षेत्र में इसे बेच रही है तथा अमेरिकी बाजार को उत्पाद का निर्यात कर रही है।
- (च) यह तर्क कि साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट खरीदना और मूल्यवान संसाधनों जैसे कि व्यक्ति एवं मशीनरी का बहुत छोटे पूंजीगत निवेश से भी उपयोग करना समझदारी वाला व्यवसाय नहीं है क्योंकि जब अंतिम उत्पाद ''सोडियम साइट्रेट'' समान मूल्य पर उपलब्ध है तो इससे इसकी पृष्टि होती है कि निर्यातक उत्पाद को कम मूल्य पर बेच रहे हैं यही कारण है कि आयातक आयतित उत्पाद बेच रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि विनिर्माता अर्थात् मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पी यू सी का आयात करना शुरू कर दिया है। विपक्षी पक्षकार के तर्क से यह अर्थ निकलता है कि जहां कहीं चाइनीज उत्पादक पिछड़े एकीकृत हैं, भारतीय उद्योग को विनिर्माण क्षमताओं को बंद कर देना चाहिए तथा शत प्रतिशत आयात पर निर्भर रहना चाहिए। यह निश्चित रूप से लोक

हित के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त्, महज इस तथ्य से कि चाइनीज उत्पादकों के अपने साइट्रिक अम्ल हैं और वे सोडियम साइट्रेट बेचते हैं, यह अर्थ नहीं निकलता है कि भारतीय उद्योग को संरक्षित किया जाना चाहिए।

- (छ) भारत के लिए निर्यात मूल्य, लैंडेड मूल्य एवं उच्च नुकसान मार्जिन, याचिकाकर्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए चार वर्षों के लिए रक्षोपाय ड्यूटी के लिए अनुरोध किया है।
- (ज) व्यापारियों द्वारा व्यापार से अर्जित लाभ 10 प्रतिशत से अधिक प्रतीत होते हैं और ऐसे व्यापारियों का विश्वास है कि साइट्रिक एसिड पर 10 प्रतिशत मार्कअप संपरिवर्तन लागत, ओवरहेड लागतों, ब्याज, मूल्यहास, पारिश्रमिक, लगाई गई पूंजी पर रिटर्न को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इससे इन व्यापारियों के दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप से पता लगता है जिनका सीमित उद्देश्य व्यापार से लाभ अर्जित करना है।
- (i) रक्षोपाय ड्यूटी लगाना लोकहित में होगा। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्य रूप से ओ आर एस, पनीर, कफ सिरप, साफ्ट ड्रिंक जेली, फोटोग्राफिक उद्योग, पेय पदार्थों और फार्मास्यूटिकल उद्योग में किया जाता है। याचिकाकर्ता ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार, 30% रक्षोपाय शुल्क की दर से सोडियम साइट्रेट पर लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव की गणना करने का प्रयास किया है:

उत्पाद	भूमिका	खपत	अनुमानित लागत	लागत पर प्रभाव यदि
			आई एन आर	30% शुल्क
ओ आर एस	एक अवयव के रूप में	2.9 ग्रा./लीटर	0.1885/लीटर	0.008%
पनीर	एक परिरक्षक के रूप में	2.30%	0.13/100 ग्रा.	0.016%
खांसी सीरप	कफ़-निस्सारक के रूप में	1.1 ग्रा./मि.ली.	0.0175/100 मि.ली.	0.049%
सॉफ्ट ड्रिंक	नमकीन एवं तेज स्वाद के लिए	<2%	<0.12/लीटर	0.090%
जेली	नमकीन एवं तेज स्वाद के लिए	<2%	<0.12/100 ग्रा.	0.018%
फोटोग्राफी उद्योग	जमाव-रोधी के रूप में	<2%	<0.12/100 ग्रा.	0.004%
पेय पदार्थ	नमकीन एवं तेज स्वाद के लिए	<2%	<0.12/लीटर	0.072%
दवा उद्योग	जमाव-रोधी के रूप में	<2%	<0.12/100 ग्रा.	0.004%

याचिककाकर्ता ने ऊपर उल्लिखित प्रत्येक उपभोक्ता-क्षेत्र में सोडियम साइट्रेट की अनुमानित खपत पर विचार किया है और तत्पश्चात अंतिम लागत पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना की है। यह देखा जा सकता है कि सोडियम साइट्रेट के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अंतिम प्रभाव नगण्य है।

#### जांच और निष्कर्ष:

- 22. मैंने मामले से संबंधित रिकार्डों, घरेलू उत्पाद, प्रयोक्ता/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक देशों द्वारा प्रस्तुत उत्तर को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा दिए गए उत्तर तथा उनसे उत्पन्न हुए मुद्दों के बारे में नीचे दिए गए निष्कर्ष में उचित स्थानों पर उल्लेख किया गया है।
- 23. सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख, आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित है। इसकी उप-धारा (1) में, किसी वस्तु पर केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना उपबंधित है, यदि वह वस्तु

इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में भारत में आयातित की जा रही हो, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही हो या होने का खतरा हो।

- 24. सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 में जांच का तरीका और उक्त को शासित करने वाले सिद्धांत उपबंधित हैं।
- 25. जांच, उक्त नियमों के अनुसार की गई है और अंतिम निष्कर्ष इस अधिसूचना के माध्यम से रिकार्ड किए जा रहे हैं। इन निष्कर्षों में और यहां नीचे, समुचित स्थानों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों से निपटा गया है :
- कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग, एंटी डंपिंग शुल्क और रक्षोपाय शुल्क, दोनों को लगाए जाने की मांग नहीं कर सकता है। यह नोट किया गया कि एंटी डंपिंग शुल्क और रक्षोपाय शुल्क को एक साथ लगाए जाने के मुद्दे से कानून के तहत ही भली-भांति प्रकार से निपटा गया है। यह सच है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की भी मांग की है और वर्तमान में जांच चल रही है। अभिहित प्राधिकारी ने अब तक निष्कर्ष रिकार्ड नहीं कराया है और एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश अभी नहीं की गई है। जांच से एंटी डंपिंग शुल्क को लगाने का औचित्य साबित या नहीं साबित हो सकता है। यह भी नोट किया गया कि एंटी डंपेंग शुल्क भी व्यापार से संबंधित एक निराकरण उपाय है जिसके द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर, डंप किए गए आयातों के बुरे प्रभावों का मुकाबला और उन्हें निष्फल किया जा सकता है। रक्षोपाय शुल्क एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा प्रशुल्क सीमा को बढ़ाकर बढ़ते आयात के हानिकर प्रभावों से घरेलू उद्योग की रक्षा की जा सकती है। दोनों शुल्कों में अन्य कार्यों के अलावा एक कार्य एक जैसा है अर्थात् आयात के हानिकर प्रभावों को निष्फल करना। अत: यह अनिवार्य है कि रक्षोपाय शुल्क को तभी लगाया और जारी रखा जाए, जब व्यापार से संबंधित निराकरण उपाय, चाहे वे जिस भी स्वरूप में हों, घरेलू उद्योग की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं। यहां यह भी अंतर्निहित है कि बहुविध सुरक्षा उसी सीमा तक उपलब्ध होगी जहां तक वह आवश्यक हो। मौजूदा मामले में, यह सच है कि आयात में कई गुणा वृद्धि हुई है और अभिहित प्राधिकारी ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की आवश्यकता को अब तक सिद्ध नहीं किया है। आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है। मौजूदा प्रशुल्क, जिसमें एंटी डंपिंग शुल्क शामिल नहीं था, बड़ी मात्रा में आयात को रोकने हेतु पर्याप्त नहीं था। अत: यह विचार करना उचित होगा कि क्या रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक है। इस संबंध में, यह भी नोट किया गया कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि सोडियम साइट्रेट का निर्यात कर रहीं चीन की कंपनियां वैसी कंपनियां हैं जो साइट्रिक एसिड (कच्चा सामान) का भी उत्पादन कर रही हैं और इसलिए उनकी लागत स्वभाविक रूप से कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पाद के आयात मृल्य और घरेलू लागत में संपूर्ण अंतर, उत्पाद के डंपिंग के कारण से नहीं है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) :क. विचाराधीन उत्पाद 'सोडियम साइट्रेट' (जिसे इसमें इसके बाद विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) है, जो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के सीमा-शुल्क प्रशुल्क शीर्ष 29181520 के अंतर्गत भारत में आयातित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद अर्थात् ''सोडियम साइट्रेट'' एक रासायनिक अवयव है, जो मोनो-सोडियम साइट्रेट, डाई-सोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। यह साइट्रिक अम्ल का सोडियम लवण है और यह कड़वा और नमकीन स्वाद लिए होता है। सोडियम साइट्रेट का मुख्यत: उपयोग दवा उद्योगों में एक कफ़-निस्सारक और यूरीन ऐलकॅलाइज़र के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल औषधीय सहायक सामग्री, डेयरी उद्योगों में खाद्य योगज (अडिटिव), जल-शोधन में प्रयोगशाला अभिकर्मक (रीएजेंट), पेय पदार्थों में अम्लता विनियामक (एसिडिटी रेग्युलेटर), पनीर बनाने में तेलों के इमल्सिफायर तथा भोजन में एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि के रूप में भी किया जाता है।
  - क. सोडियम साइट्रेट
  - ख. ट्राई सोडियम साइट्रेट
  - ग. ट्राई सोडियम साइट्रेट डाईहाइड्रेट
  - घ. सोडियम साइट्रेट डाईहाइड्रेट
  - **ङ**. टाईबेसिक सोडियम साइट्रेट
  - च. सोडियम साइट्रेट ट्राईबेसिक डाईहाइड्रेट
  - छ. सोडियम साइट्रेट डाइबेसिक सेसक्वीहाइड्रेट
  - ज. सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोक्सटा
- 26. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ट्राई सोडियम साइट्रेट, मोनो सोडियम साइट्रेट और डाई-सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट को गलत ढंग से एक साथ जोड़ दिया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि डाई-सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, मोनो/डाई/ट्राई सोडियम साइट्रेट महज सोडियम साइट्रेट के रूप हैं और जिनका उपयोग, कार्य समान होने के साथ-साथ पारंपरिक वर्गीकरण के तहत इनकी पहचान भी एक

है। इन स्वरूपों के निर्माण से संबंधित उत्पादन-प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया भी एक और समान है। उपभोक्ता भी बिना किसी भेदभाव के इनमें से एक-दूसरे का प्रयोग करते हैं। अत:, मोनो/डाई/ट्राई सोडियम साइट्रेट के किसी संदर्भ को सोडियम साइट्रेट, जो विचाराधीन उत्पाद है, के रूप में मान लिए जाने को उचित समझा गया है।

- 27. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग सोडियम साइट्रेट का उत्पादन केवल फार्मा ग्रेड के लिए ही करता है। तथापि, यह नोट किया गया कि उक्त को सिद्ध करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकार ने कोई सूचना मुहैया नहीं कराई। इस दावे के विपरीत यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया और इसे फार्मा/खाद्य/कीटनाशक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेचा, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद और इसे केवल फार्मा क्षेत्र को बेचे जाने पर कोई प्रतिबंध अथवा सीमा नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित सामान का उपयोग फार्मा/खाद्य/कीटनाशक आदि जैसे सभी प्रकार के उद्योगों में किया जाता है।
- 28. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि उत्पाद को कच्चे स्वरूप में आयात किया गया था और आगे भारत में संसाधित किया गया। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि आयातित सामग्री को संसाधित नहीं किया जाता है और उत्पाद को फार्मा या खाद्य ग्रेड उत्पाद बनाने के लिए केवल इसकी पैकिंग फिर से की जाती है। घरेलू उत्पादकों ने दावा किया है कि उत्पाद के उत्पादन अथवा इसे संसाधित किए जाने में शामिल बारीकियों को देखते हुए आयातित उत्पाद को वस्तुत: संसाधित नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि चूंकि फार्मा ग्रेड का उत्पाद देश में आयातित नहीं किया जा सकता है, ये पक्षकार, "दवा संबंधी उपयोग के लिए नहीं" का उल्लेख, जो संसाधित किया जाना दर्शाता है, करते हुए उत्पाद का आयात करते हैं और तत्पश्चात इसे बाजार में बेचते हैं। यह नोट किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों ने आयातित उत्पाद के संबंध में उनके द्वारा पालन की जा रही उत्पादन संबंधी प्रक्रिया का न तो उल्लेख किया है और न ही इस संबंध में घरेलू उद्योग के दावों का खंडन किया है। यह भी नोट किया गया कि उत्पाद का आयात कुछ ऐसे पक्षकार कर रहे हैं जो पहले भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक रहे हैं। इन पक्षकारों ने कथित रूप से उत्पादन बंद कर दिया है और अब उत्पाद का आयात कर रहे हैं। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये पक्षकार उत्पाद को, उनके द्वारा निर्मित सामान के रूप में अथवा एक व्यापारी के रूप में बेच रहे हैं। अत:, यह सिद्ध नहीं हुआ कि आयातित उत्पाद को वस्तुत: आगे आयातकों द्वारा संसाधित किया जाता है।
- ं. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता केवल फार्मा ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं; जिसकी आपूर्ति केवल फार्मा और खाद्य संबंधी उद्योगों को की जाती है न कि एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि जैसे अन्य रासायनिक उद्योगों को। तथापि, याचिकाकर्ता ने दस्तावेजी साक्ष्य (वाणिज्यिक इन्वॉयस) उपलब्ध कराए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद की सभी किस्मों का उत्पादन किया है।
- ii. यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता निश्चित ही विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक है और आयात के कारण कोई गंभीर क्षिति नहीं हुई है। तथापि, यह नोट किया गया कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता उत्पाद का निर्यात करता रहा है, का अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को क्षिति बढ़े आयात से नहीं हुई है। सामानों को निर्यात करना केवल उत्पाद को बेचने का एक तरीका है।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा इसकी उपयोगिता में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की जाती है। तथापि, इसके साथ-साथ यह भी नोट किया गया कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि वे कच्चे स्वरूप में उत्पाद का आयात करते हैं, इसकी उपयोगिता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हैं और तब यह उत्पाद तैयार होता है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा परस्पर विरोधी तर्क दिए गए हैं। चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता की उत्पादन संबंधी सुविधाएं, स्थान-सत्यापन संबंधी वचनपत्र द्वारा सत्यापित की गईं और यह पाया गया कि याचिकाकर्ता महत्वपूर्ण उत्पादन संबंधी गितविधियां चला रहा है।
- iv. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है और वह अपनी क्षमता का उपयोग अन्य विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए भी करता है। तथापि, उत्पाद शुल्क संबंधी रिकार्डों से विधिवत रूप से सत्यापित सूचना से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास विचाराधीन उत्पाद से संबंधित एक समर्पित संयंत्र मौजूद है।
  - 29. अत: यह निर्णय दिया जाता है कि जिस उत्पाद की जांच की जा रही है, वह ''सोडियम साइट्रेट'' है, जो सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के सीमा-शुल्क प्रशुल्क शीर्ष 29181520 के अंतर्गत आता है।

## 30. घरेलू उद्योग:

- i. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6) (ख) में घरेलू उद्योग को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:
  - (क)"घरेलू उद्योग" से वे विनिर्माता अभिप्रेत हैं-
  - (ख) जो भारत में एक जैसा अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक सामान का विनिर्माण करते हैं; अथवा
  - (ग)जिनके एक जैसे सामान अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक सामान का संयुक्त उत्पादन भारत में उक्त सामान के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हो।

ii. उक्त आवेदन सोडियम साइट्रेट के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के संबंध में मैसर्स पोजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उक्त आवेदन का मैसर्स सुनील कैमीकल्स द्वारा समर्थन किया गया है। आवेदक ने अन्य अनेक ऐसे विनिर्माताओं को अभिज्ञात किया है जो भारत में संबंधित उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता पैदा करने के लिए जाने जाते हैं तथा जो देश में उस उत्पाद को बेचते आ रहे हैं। तथापि, विनिर्माताओं के रूप में ठोस सूचना की अनुपस्थिति में उनकी ज्ञात बिक्रियों को उनके उत्पादन के रूप में माना गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से देश में समान उत्पादन अथवा प्रत्यक्ष रूप में प्रतिस्धित्मक सामान के परिमाण का निम्न प्रकार पता चलता है:

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
याचिकादाता	1,184	1,211	1,531	1,521
याचिकादाता+समर्थनकर्ता	2,423	2,674	2,992	2,783
अन्य भारतीय विनिर्माता	133	207	235	109
कुल भारतीय उत्पादन	2,556	2,881	3,227	2892
भारतीय उत्पादन में हिस्सा				
याचिकादाता	46%	42%	47%	53%
याचिकादाता+समर्थनकर्ता	95%	93%	93%	96%
अन्य भारतीय विनिर्माता	5%	7%	7%	4%
कुल भारतीय उत्पादन	100%	100%	100%	100%

iii. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि आविदक का उत्पादन भारत में सोडियम साइट्रेट के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा था। इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मैसर्स सुनील कैमीकल्स सहित याचिकादाता का हिस्सा भारतीय उत्पादन का 90 प्रतिशत नहीं है। तथापि इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी विनिर्माता ने उनके पास उपलबध क्षमता से संबंधित आंकड़े मुहैया नहीं कराए हैं। अत: याचिकादाता द्वारा प्रदान की गई सूचना को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में माना गया है। अभिहित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि इस बारे में याचिकादाता के दावे उपयुक्त नहीं हैं। इसके विपरीत एक पक्षकार ने यह दावा किया कि समर्थनकर्ता पक्षकार, मैसर्स सुनील कैमीकल्स ने सामान का उत्पादन नहीं किया है। तथापि, सुनील कैमीकल ने जो सुचना प्रदान की है उसमें संगत अवधि के दौरान उत्पादन का उल्लेख किया गया है। किसी भी स्थिति में, यदि सुनील कैमीकल को शून्य (जीरो) मान लिया जाए तो उसका अर्थ यह होता है कि याचिकादाता का उत्पादन उससे काफी अधिक होगा जो मौजूदा निष्कर्षों में माना गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी इच्छुक पक्षकार का यह तर्क नहीं है कि याचिकादाता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। iv. अत: तदनुसार, मेरा यह मानना है कि मैसर्स पोजी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा सभी विनिर्माताओं में सबसे अधिक है और वह इस मामले में घरेलू उद्योग के मानदंडों को पूरा करता है क्योंकि अभी हाल की अवधि में भारतीय उत्पादन में उसका हिस्सा 52 प्रतिशत है तथा भारतीय उत्पादन में समर्थनकर्ता, मैसर्स सुनील कैमीकल का हिस्सा लगभग 96 प्रतिशत है। जांच (लोक सुनवाई) के दौरान एक दूसरे घरेलू विनिर्माता अर्थात् मैसर्स वांग फार्मास्यूटीकल्स एंड कैमीकल्स ने भी आवेदक का समर्थन किया है जिससे घरेल उद्योग के रूप में, व्यक्तिगत रूप से अथवा समर्थनकर्ताओं सिहत आवेदक के दावे के बारे में कोई संदेह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अत: यह माना जाता है कि आवेदक, घरेलू विनिर्माता, सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6) (ख) के अंतर्गत अपेक्षित और परिभाषित अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का भाग है और उसका प्रतिनिधित्व करता है।

### 31. सूचना का स्रोत:

क. जिस उत्पाद की जांच चल रही है उसका भारत में आयात सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के सीमा-शुल्क प्रशुल्क शीर्षक 29181520 के अंतर्गत किया जाता है। सुरक्षोपाय संबंधी जांच अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2013 तक डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता से तथा अक्तूबर, 2013 से जनवरी 2014 तक की अवधि तक आई बी आई एस, मुंबई से लिए गए आयात संबंधी आंकड़ों (सौदा-वार) के आधार पर शुरू की गई। वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक (अक्तूबर, 2013 तक) के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों पर आधारित घरेलू आंकड़ों का, विभाग द्वारा स्थल का दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक तथा दौरे के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, सत्यापन किया गया है। उसके पश्चात जनवरी, 2014 तक की अवधि के घरेलु उद्योग आंकड़ों का सत्यापन उत्पाद-शुल्क रिकॉर्ड से किया गया और इन सत्यापित आंकड़ों पर जांच शुरू किए जाने के नोटिस के समय हानि विश्लेषण की दृष्टि से गौर किया गया। अत: जांच शुरू किए जाने का नोटिस जनवरी, 2014 तक की अवधि की सूचना पर आधारित था। वर्तमान जांच के दौरान विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में मार्च, 2014 तक की अ**तिरिक्त** अवधि से संबंधित आंकड़ों पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी रिकॉर्ड, जो उचित रूप से प्रमाणित हैं, के अनुसार विचार किया गया है ताकि हानि के विश्लेषण के लिए वर्ष 2013-14 तक के वार्षिक समेकित आंकड़ों का पता लगाया जा सके। वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए आयात अब डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात संबंधी सूचना पर आधारित है। इच्छुक पक्षकारों को अतिरिक्त सुचना सुरक्षोपाय नियम. 1997 के नियम 6 (7) के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार पब्लिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय के आंकड़े घरेलू उद्योग (डॉमेस्टिक इण्डस्ट्री) द्वारा दिनांक 06/09/1997 के ट्रेड नोटिस सं. एम जी/टी एन/1/97 के साथ पठित सुरक्षोपाय शुल्क नियम 1997 के नियम 5 (2) के अंतर्गत डी जी (सेफगार्ड) द्वारा निर्धारित रूप में तथा तरीके से प्रदान किए गए हैं। सत्यापन रिपोर्ट के गैर-गोपनीय भाग को सभी संबंधितों की टिप्पणियों के लिए पब्लिक फाइल में रखा गया है। लागत संबंधी आंकड़े तथा हानि की गणना याचिकादाता द्वारा मुहैया कराई गई है जिसे एक स्वतंत्र लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ख. यह भी देखा गया है कि किसी भी इच्छुक पक्षकार ने विचार किए गए आयात संबंधी आंकड़ों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है अथवा भारत में सोडियम साइट्रेट के कुल आयात के बारे में सूचना नहीं दी है अथवा आवेदक/घरेलू उद्योग (डॉमेस्टिक इंडस्ट्री) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विवाद खड़ा नहीं किया गया है।

ग. मैसर्स प्रकाश कैमीकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने आयातों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इन कंपनियों ने प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किए हैं।

#### 32. जांच की अवधि:

क. न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और न ही सीमा शुल्क प्रशुल्क (सुरक्षोपाय शुल्क का निर्धारण एवं मूल्यांकन) नियम, 1997 में 'जांच की अविध' अथवा सुरक्षोपाय जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली न्यूनतम अविध को विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सुरक्षोपायों के बारे में विश्व व्यापार संगठन के करार में जांच की अविध तय करने के बारे में कोई सामान्य अथावा विशिष्ट प्रावधान अथवा दिशानिर्देश नहीं हैं। तथापि, जांच की अविध के मुद्दे पर कोरिया के विरुद्ध यू एस-लाइन पाइप मामले में पैनल के निष्कर्षों में विस्तार से विचार किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि 'जांच की अविध' तथा इसके ''बंद होने (ब्रेकडाउन)'' के बारे में निर्णय करना आयातकर्ता सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर होता है।

"हम यह नोट करते हैं कि उक्त करार में न तो कोई ऐसी अपेक्षाएं निहित हैं कि सुरक्षोपाय संबंधी जांच में जांच की अविध कितनी लंबी होनी चाहिए और न ही यह निहित है कि विश्लेषण के प्रयोजन से अविध को किस प्रकार ब्रेकडाउन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जांच की अविध तथा इसका ब्रेकडाउन जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है। हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में आई टी सी द्वारा चुनी गई अविध पांच वर्ष और छ: माह थी तथा यह अविध अर्जेन्टीना-फुटवीयर सेफगार्ड में अर्जेन्टीनी जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त अविध के बराबर लंबी है। तथापि, हम यह नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने उन निष्कर्षों, जिनका जांच की अविध की लंबाई के प्रश्न पर आपित्त करने के लिए कोरिया ने सहारा लिया, में परस्पर अविध की लंबाई पर जोर नहीं दिया बिल्क इस बात पर जोर दिया कि हाल में किए गए आयातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए न कि मात्र जांच की अविध के दौरान प्रवृत्तियों पर। समान जांच के मामले में आई टी सी ने मात्र अंतिम बिंदुओं की तुलना नहीं की अथवा जांच की अविध के दौरान समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेन्टीना ने सेफगार्ड मामले की जांच में किया था)। इसने 5 पूरे वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया तथा इस बात पर विचार किया कि क्या अंतिम 1998 की तुलना में अंतिरम 1999 में वृद्धि हुई। हमारा यह मत है कि जांच की अविध, जो 5 वर्ष और छ: माह से अधिक है, तय करके आई टी सी ने अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद XIX के अनुसार असंगत कार्रवाई नहीं की। यह निष्कर्ष इस बात पर आधारित है: प्रथम यह कि इस करार में जांच की अविध की लंबाई के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं; दूसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अविध हाल के आयातों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए पर्याप्त हैं; और तीसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अविध हाल के आयातों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए पर्याप्त हैं; और तीसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अविध हाल के आयातों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)।

ख. पैनल ने इसी प्रकार के यू एस-लाइन पाइप मामले में यह निर्णय दिया कि:

"सुरक्षोपाय संबंधी जांच में बढ़े हुए आयातों की प्रवृत्तियों की जांच के लिए जांच की अविध घरेलू उद्योग के लिए गंभीर हानि की जांच के बराबर होनी चाहिए। यह एंटी-डंपिंग स्थित अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टीगेशन के विपरीत है जहां डंपिंग अथवा सबसीडाइजेशन की मौजूदगी का मूल्यांकन करने संबंधी अविध सामान्यत: किसी महत्वपूर्ण जांच के निष्कर्ष के लिए जांच की अविध से कम होती है। हमारा यह मत है कि इस अंतर के पीछे अर्जेन्टीना-फुटवियर सेफगार्ड में अपीलीय निकाय द्वारा ढूंढ़ा गया एक कारण यह है "इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में आयातों की आवश्यकता का निर्धारण" पूरा हो पाता है, यह मात्र गणितीय अथवा तकनीकी निर्धारण नहीं है। "अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जब बढ़े हुए आयातों के निर्धारण का मामला हो तो "सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अविध की तुलना में आयातों की प्रवृत्त्यों पर विचार करना चाहिए।" घरेलू उद्योग के लिए गंभीर हानि के निर्धारण के लिए प्रासंगिक घटकों में प्रवृत्तियों के मूल्यांकन के साथ-साथ आयातों में प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कुछ समय बाद ही किया जा सकता है। अत: हमारा यह निष्कर्ष है कि किसी हानि के निर्धारण के लिए संगत अविध के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त की गई बातें बढ़े हुए आयातों के निर्धारण के संबंध में भी लागू होती है।" (पैरा 7.209)

ग. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि न तो सुरक्षोपाय संबंधी कानूनों, न ही सुरक्षोपाय संबंधी करार और जी ए टी टी के अनुच्छेद XIX में जांच की अविध के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। तथापि, ऊपर उदधृत संदर्भों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संगत जांच अविध पर्याप्त रूप से इतनी लंबी होनी चाहिए कि बढ़े हुए आयात तथा गंभीर हानि के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके और यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम न पड़े बिल्क जांच की अविध थोड़ी अधिक ही होनी चाहिए।

घ. इस बात पर गौर करते हुए, कि चुनी गई अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए कि बढ़े हुए आयातों की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके और मौसमी अंतर के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके, वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक आंकड़ों पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विचार करना चाहिए। जांच शुरू किए जाने संबंधी नोटिस में जनवरी 2014 तक के आयात आंकड़ों पर वार्षिक आधार पर विचार किया गया था। अब आयात संबंधी आंकड़ों को मार्च 2014 तक अद्यतन कर लिया गया है। अत:, इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर गौर करते हुए मौजूदा जांचों के प्रयोजन से 2010-11 से 2013-14 की अवधि, जिसे इस मामले में जांच की अवधि (जिसे इसमें इसके पश्चात पी ओ आई कहा गया है) माना गया है, तक के आंकड़ों को अंगीकार करना उपयुक्त समझा गया है।

## 33. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

i. सीमा शुल्क प्रशुल्क (सुरक्षोपाय शुल्क का निर्धारण एवं मूल्यांकन), नियम, 1997 और सुरक्षोपाय के बारे में विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.2 में कितपय सूचना के बारे में गोपनीयता संबंधी कार्रवाई का प्रावधान है। इन नियमों में यह प्रावधान है कि किसी इच्छुक पक्षकार को वस्तुत: ऐसी सूचना का खुलासा नहीं करना होता है जो किसी कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसके खुलासे से उस पक्षकार के व्यापारिक हितों को गंभीर नुकसान पहुंचे तथा जो सूचना सार्वजनिक न हो और जिसका याचिकादाता ने विगत में जनता के बीच सामान्यत: खुलासा नहीं किया हो।

ii. घरेलू उद्योग (डॉमेस्टिक इंडस्ट्री) ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना मुहैया कराई है तथा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों के बारे में गोपनीयता की मांग की है। डॉमेस्टिक इंडस्ट्री ने सुरक्षोपाय संबंधी नियम 1997 के प्रावधानों तथा दिनांक 06.09.1997 के ट्रेड नोटिस नं. एस जी/टी एन/1/97 का गैर-गोपनीय पाठ मुहैया कराया था। इसके अतिरिक्त, डॉमेस्टिक इंडस्ट्री ने आवेदन दायर करने के समय गोपनीयता की मांग के कारण प्रस्तुत किए हैं जो उचित प्रतीत होते हैं और अत:, जब कभी इन्हें प्रस्तुत किया गया है तो इनको स्वीकार किया गया है।

## 34. बढ़े हुए आयात

क. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख सुरक्षोपाय शुल्क लगाने संबंधी केन्द्र सरकार की शक्ति से संबंधित है तथा इसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

"यदि केन्द्र सरकार, ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, करने के बाद इस बात से संतुष्ट हो कि भारत में किसी सामान का इतनी बढ़ी हुई मात्रा में तथा ऐसी शर्तों के अंतर्गत आयात किया गया है जिनसे घरेलू उद्योग के हानि हो या हानि होने का खतरा हो तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उस सामान पर सुरक्षोपाय शुल्क लगा सकती है।"

ख. इन नियमों में किसी सुरक्षा उपाय को लागू करने की पूर्विपक्षा के आधार के रूप में आयातों में वृद्धि को अधिदेशित किया गया है। इस प्रकार, यह निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद का आयात "इतनी मात्रा में बढ़ गया है" कि सुरक्षा उपाय लागू करना जरूरी है तो नियमों में आयात की वृद्धि का पूर्ण रूप से अथवा घरेलू उत्पादन की दृष्टि से विश्लेषण करना अपेक्षित है।

ग. सीमाशुल्क प्रशुल्क (सुरक्षोपाय शुल्क का निर्धारण एवं मूल्यांकन) नियम, 1997 के नियम 2 (ग) में निम्नलिखित प्रावधान है:

''ग) 'बढ़ी हुई मात्रा' में आयातों में वृद्धि शामिल है चाहे वह समग्र तौर पर हो अथवा घरेलू उत्पादन के सापेक्ष में हो।

घ. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में अर्जेन्टीना में अपीलीय निकाय फुटवियर (ई सी) ने पैनल के विपरीत यह निर्णय दिया कि आयातों में वृद्धि हाल ही में, अचानक, एकदम तेजी से और इतनी अधिक हुई होनी चाहिए कि उससे गंभीर हानि हो या गंभीर हानि का खतरा हो। उसका प्रासंगिक उद्धरण निम्न प्रकार है:

ङ "131. इस बात का निर्धारण, कि क्या इतनी बढ़ी हुई मात्रा में आयातों की आवश्यकता पूरी कर ली गई है, मात्र गणितीय अथवा तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों में किसी जांच में मात्र यह दर्शाना काफी नहीं होता कि इस वर्ष उत्पाद के आयात पिछले वर्ष-अथवा पांच वर्ष पहले से अधिक थे। पुन: यह उल्लेख किया जाता है कि आयातों की मात्र कोई बढ़ी हुई मात्रा पर्याप्त नहीं होगी। 'बढ़ी हुई मात्रा' इतनी होनी चाहिए कि घरेलू उद्योग को हानि हो सके अथवा हानि का खतरा हो ताकि सुरक्षोपाय लागू करने की यह अपेक्षा पूरी हो सके। और हमारा यह मानना है कि सुरक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 और जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद XIX: 1 (क) दोनों में प्रयुक्त इस भाषा के लिए यह अपेक्षित है कि आयातों में वृद्धि एकदम अभी हाल में हुई होनी चाहिए, अचानक हुई होनी चाहिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से इतनी अधिक हुई होनी चाहिए कि उससे 'गंभीर हानि' हो सके अथवा गंभीर हानि का खतरा हो।"

च. यू एस पैनल-व्हीट ग्लूटेन 4, ने ''इतनी बढ़ी मात्रा में'' शब्दों की निम्न प्रकार व्याख्या की:

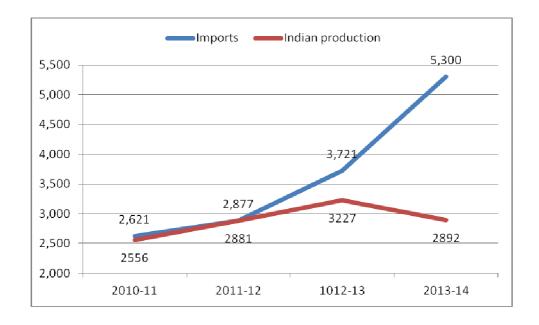
"8.31 जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद XIX: 1(क) और सुरक्षोपाय संबंधी करार ("एस ए") के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में 'वृद्धि' का उल्लेख नहीं है। बिल्क उनमें संबंधित उत्पाद के आयातों में वृद्धि की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकृति के संबंध में विशिष्ट अपेक्षाएं निहित हैं। जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद: 1 (क) और एस ए के अनुच्छेद 2.1 दोनों में यह अपेक्षित है कि किसी उत्पाद का संबंधित सदस्य के भू-भाग में इतनी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जा रहा हो (घरेलू उत्पादन की समग्र दृष्टि से अथवा सापेक्ष दृष्टि से) जिससे कि गंभीर हानि होगी अथवा गंभीर हानि का खतरा होगा। इस प्रकार, आयातों में मात्र कोई वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। बिल्क हम अर्जेन्टीना-फुटवीयर सेफगार्ड में अपीलीय निकाय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि वृद्धि एकदम हाल में हुई होनी चाहिए, अचानक हुई होनी चाहिए बहुत तेजी से तथा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से इतनी अधिक हुई होनी चाहिए जिससे कि गंभीर हानि हो या गंभीर हानि का खतरा हो।"

छ. विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त मूल्यांकनों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संपूर्ण तथा सापेक्ष, दोनों दृष्टि से तेज वृद्धि देखी गई है। संपूर्ण दृष्टि से आयातों में वृद्धि अचानक है तथा इतनी पर्याप्त है कि इससे घरेलू उद्योग को गंभीर हानि होगी। विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के आंकड़े संपूर्ण दृष्टि से निम्न प्रकार हैं।

## 35. संपूर्ण दृष्टि से आयातों में वृद्धि

क. भारत में सोडियम साइट्रेट का आयात अनेक देशों से तथा मुख्यत: चीन से होता है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हानि की पूरी अविध में संपूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई है। हाल की अविध में अचानक, तेज तथा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में आयात 2,629 मीट्रीक टन से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 5,300 मीट्रिक टन हो गए जो आयातों में 102 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि है तथा इसे नीचे दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	कुल आयात	अखिल भारतीय उत्पादन (मीट्रिक	प्रतिशत में वृद्धि
		टन)	
2010-11	2,621	2,556	
2011-12	2,877	2,881	10%
2012-13	3,721	3,227	42%
2013-14	5,300	2,892	102%



यह देखा गया है कि वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के बीच आयात में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई और उसके बाद आयात में तेजी से वृद्धि हुई।

### 36. उत्पादन के संबंध में आयात में वृद्धि:

ख. पूर्ण रूप में आयातों में वृद्धि के अतिरिक्त, यह देखा गया है कि पी ओ आई के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भी घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। नीचे तालिका से देखा जा सकता है कि कुल उत्पादन के संबंध में आयात वर्ष 2010-11 में 103% से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 183% हो गया अर्थात् इसमें 80% की वृद्धि हुई जो एक स्पष्ट उत्कर्ष है। पूर्ण रूप में, यद्यपि, अखिल भारतीय उत्पादन में केवल 336 मिट्रिक टन की वृद्धि हुई, तथापि, आयात में 2679 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह पता चलता है कि जहां भारतीय उत्पादन में केवल 13% की वृद्धि हुई, वहीं आयात में 102% की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	अखिल भारतीय उत्पादन	भारतीय उत्पादन के
	(मिट्रिक टन)	(मिट्रिक टन)	संबंध में आयात (%)
2010-11	2,621	2,556	103%
2011-12	2,877	2,881	100%
2012-13	3,721	3,227	115%
2013-14	5,300	2,892	183%

- i. एक हितबद्ध पक्षकार ने तर्क दिया है कि बढ़े हुए आयात और गंभीर नुकसान (इंज्यूरी) का अवधारण घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री को शामिल करने के बाद किया जाना चाहिए। यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई निर्यात बिक्री को विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उद्योग अवधारित करने में शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए, घरेलू उद्योग की बिक्री की जांच निर्यात बिक्री को हटाकर की जानी चाहिए।
- ii. ऊपर से यह स्पष्ट है कि जांच अवधि के दौरान पूर्ण रूप से और घरेलू उत्पादन के संबंध में, दोनों रूप में आयातों में तेजी आई है। पूर्ण रूप से आयातों में वृद्धि आयातों में स्पष्ट तेजी है और इसमें बढ़ता रूझान है जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के अर्थ के भीतर ''बढ़ते आयात'' के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

### 37. गंभीर नुकसान और गंभीर नुकसान का खतरा:

- 1. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख उप-धारा 6(ग) में निम्नवत प्रावधान है :"गंभीर नुकसान" से ऐसा नुकसान अभिप्रेत है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र हानि पैदा हुई हो; तथा "गंभीर नुकसान का खतरा" से गंभीर नुकसान के स्पष्ट एवं आसन्न खतरा अभिप्रेत है।
- 2. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा 6(घ)में निम्नवत प्रावधान है: "गंभीर नुकसान का खतरा" से गंभीर नुकसान के स्पष्ट एवं आसन्न खतरा अभिप्रेत हैं।
- **3.** सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय ड्यूटी का निर्धारण एवं मूल्यांकन) नियम, 1997 के नियम 8 के अनुलग्नक के पैरा 1 में निम्नवत प्रावधान किया गया है :
  - 'यह अवधारित करने के लिए जांच में कि क्या बढ़े आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पैदा हुआ है या गंभीर नुकसान पैदा होने का खतरा है, महानिदेशक वस्तुगत एवं निर्धारणीय प्रकृति के सभी संगत कारकों का आकलन करेंगे जिसका उस उद्योग की स्थिति, विशेषकर पूर्ण एवं सापेक्ष दोनों रूपों में संबंधित वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर एवं मात्रा, बढ़े आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के अंश, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता, उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तनों पर प्रभाव होगा।"
- 4. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2 (क) और सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय ड्यूटी का निर्धारण एवं मूल्यांकन) नियम, 1977 के नियम 8 में अपेक्षा की गई है कि कितपय सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों का आकलन गंभीर नुकसान या गंभीर नुकसान के खतरे को अवधारित करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी आकलन विभिन्न मामलों में विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न होगा जो मामला विशेष के तथ्यों और संबंधित उद्योग की

स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के आकलन में अनिवार्य रूप से यह नहीं दर्शाया जाना होगा कि प्रत्येक ऐसे कारक में गिरावट हो रही है।'' उदाहरण के लिए एक मामले में, बिक्री, रोजगार एवं उत्पादकता में काफी गिरावट हो सकती है जो घरेलू उद्योग में ''वास्तविक नुकसान'' को दर्शा सकती है तथा इसलिए बाजार के नष्ट होने का पता लगाने का औचित्य हो सकता है, दूसरे मामले में, कतिपय कारक में गिरावट नहीं हो सकती है किंतु समग्र तस्वीर घरेलू उद्योग को ''वास्तविक नुकसान'' को प्रदर्शित कर सकती है।

- 5. इस प्रकार, सभी सूचीबद्ध कारकों तथा किसी अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का आकलन उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव वाले सभी संगत कारकों के आलोक में किया जाए।
- 6. अर्जेटीना में- फूटवीयर (ई सी), अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1 (क) में ''गंभीर नुकसान'' की परिभाषा और अनुच्छेद 4.2 (क) में ''सभी संगत कारकों'' के मूल्यांकन की आवश्यकता के बीच संबंध पर चर्चा की:
- "[[] केवल तभी जब घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का आकलन उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव वाले सभी संगत कारकों के आलोक में किया जाता है, यह अवधारित किया जा सकता है कि क्या उस उद्योग की स्थिति में 'काफी समग्र हानि' हुई है। तथापि, अनुच्छेद 4.2 (क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा है कि कितपय सूचीबद्ध कारकों का आकलन किया जाना चाहिए तथा कि सभी अन्य संगत कारकों का आकलन किया जाना चाहिए जो प्रावधान में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे आकलन में क्या प्रदर्शित होना चाहिए। स्पष्टतया, ऐसा कोई भी आकलन विभिन्न मामलों में विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न होगा जो मामला विशेष के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के आकलन में अनिवार्य रूप से यह नहीं दर्शिया जाना होगा कि प्रत्येक ऐसे कारक में गिरावट हो रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में, विक्री, रोजगार एवं उत्पादकता में काफी गिरावट हो सकती है जो उद्योग की स्थिति में "अत्यधिक समग्र हानि" को दर्शा सकती है तथा इसलिए गंभीर नुकसान का पता लगाने का औचित्य बताएगा। दूसरे मामले में, कितपय कारक में गिरावट नहीं हो सकती है किंतु समग्र तस्वीर उद्योग को "अत्यधिक समग्र हानि" को प्रदर्शित कर सकती है। इस प्रकार, इस बात की तकनीकी जांच के अतिरिक्त कि क्या मामला विशेष में सक्षम प्राधिकारियों ने सभी सूचीबद्ध कारकों और किन्हीं अन्य संगत कारकों का आकलन कर लिया है; हमें विश्वास है कि किसी भी पैनल के लिए यह आवश्यक है कि वह 'गंभीर नुकसान' के किसी अवधारण की अपनी समीक्षा में रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1 (क) में गंभीर नुकसान' की गरिभाषा को ध्यान में ले।"
- 7. यू एस पर पैनल व्हीट ग्लूटेन ने अपीलीय निकाय द्वारा सही बताए गए एक निष्कर्ष में शब्द ''गंभीर नुकसान'' के अर्थ की विस्तृत व्याख्या की :
  - "[क] ऐसे अत्यधिक समग्र हानि' के अस्तित्व के बारे में अवधारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के आकलन के आधार पर ही किया जा सकता है। हम नहीं मानते कि अत्यधिक समग्र हानि की स्थिति में होने के लिए किसी उद्योग हेतु प्रत्येक एकल कारक में नकारात्मक रूझान की जांच आवश्यक है। इसके बजाए, कुल रूझानों और उनकी परस्परता को गंभीर नुकसान के अवधारण में ध्यान में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, कई कारकों में ऐसे सुधार गंभीर नुकसान के अवधारण को अनिवार्य रूप से प्रतिबाधित नहीं करेगा। यह जांच प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन एवं आकलन करें और इस बारे में पर्याप्त, तर्कसंगत एवं समुचित स्पष्टीकरण दें कि किस प्रकार तथ्य किए गए अवधारण का समर्थन करते हैं।"
  - 8. तदनुसार, गंभीर नुकसान या गंभीर नुकसान के खतरे को विश्लेषण करने में सभी कारकों, जो नियमों में उल्लिखित हैं और अन्य कारकों, जो गंभीर नुकसान या गंभीर नुकसान के खतरे के अवधारण के लिए संगत हैं, पर

विचार किया गया है। किसी भी एकल कारक पर विन्यास के रूप में विचार नहीं किया गया है। संगत व्यवसाय चक्र एवं स्थितियों, जो प्रभावित उद्योग के लिए संगत हैं, के संदर्भ में सभी संगत कारकों पर विचार किया गया। हितबद्ध पक्षकारों, घरेलू उद्योग, समर्थक घरेलू उत्पादकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है। गंभीर नुकसान या गंभीर नुकसान के खतरे का अवधारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के आकलन पर आधारित है जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

#### 38. **बाजार अंश** :

i. नीचे तालिका से यह देखा गया है कि कुल उपभोग में घरेलू उद्योग का बाजार अंश घटा है, जबकि आयातों का बाजार अंश बढ़ा है।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात ( <b>मी</b> .टन)	डी आई की बिक्री	बाजार अ	शं का प्रतिशत
		(मी.टन)		
			डी आई	आयात
2010-11	2,621	505	11	57
2011-12	2,877	632	12	55
2012-13	3,721	1036	16	57
2013-14	5,300	999	13	69

ii. आवेदक का बाजार अंश वर्ष 2012-13 तक बढ़ा और उसके बाद घटा। इसके विपरीत, आयातों का बाजार अंश वर्ष 2010-11 में 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 69 प्रतिशत हो गया है जो कि 12 प्रतिशत की वृद्धि है। बाजार अंश का काफी हिस्सा आयात के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का बाजार अंश घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमताओं के बावजूद घटा है।

#### 38. **उत्पादन**

घरेलू उद्योग का उत्पादन विगत समय में बढ़ा है। घरेलू उद्योग का तर्क है कि वे उत्पादन बढ़ाने में समर्थ रहे हैं क्योंकि उसने मूल्य को लागत के स्तर से नीचे रखा है। नीचे तालिका से देखा गया है कि किए गए प्रयास के बावजूद, वर्ष 2013-14 में उत्पादन में मामूली कमी आई है और उसी अविध के दौरान आयात में काफी तेजी आई है। वर्ष 2013-14 में उत्पादन में मामूली गिरावट पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष मांग में 18 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद आई है।

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मि.टन)
2010-11	1,184
2011-12	1,211
2012-13	1,531
2013-14	1,521

#### 39. क्षमता उपयोग

घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के मद्देनजर अपनी क्षमता बढ़ायी। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्ष 2012-13 तक बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है और उसके बाद 2013-14 में यह काफी गिरकर 46 प्रतिशत हो गया है (किंतु आधार वर्ष से अधिक) जबिक मांग में वृद्धि हुई है तथा उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रयास किए गए हैं। भारत में पर्याप्त क्षमता के बावजूद कम मूल्य के आयातों तथा आयातों में तेजी के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमता की समस्या है। यह जांच की गई कि क्या क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमताओं में वृद्धि के कारण हुई है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग का अवधारण वर्ष 2012-13 में क्षमता पर विचार करते हुए किया गया।

वित्तीय वर्ष	क्षमता (मि.टन)	क्षमता उपयोग (%)
2010-11	2,700	44
2011-12	2,700	45
2012-13	2,725	56
2013-14	3,300	46

यह जांच करने के लिए कि क्या निम्न उपयोग घरेलू उद्योग की बढ़ी क्षमता के कारण, यह जांच करना विवेकपूर्ण माना गया कि क्या क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता में वृद्धि के कारण थी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई होती तो वर्ष 2013-14 में इसका उपयोग अभी भी 56 प्रतिशत ही होता जो वही स्तर दिखाता है, यदि वर्ष 2010-11 से आगे क्षमता उपयोग में गिरावट का रूझान नहीं है।

हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग में पर्याप्त क्षमता विद्यमान नहीं है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने मार्च, 2014 में पहले ही अपनी क्षमता बढ़ा ली है। इसलिए, समर्थक की क्षमता सहित आवेदक की क्षमता राष्ट्र में वास्तविक उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है।

#### 40. बिक्री के स्तर में परिवर्तन

घरेलू उद्योग की बिक्रियां वर्ष 2012-13 तक बढ़ी और उसके बाद वर्ष 2012-13 में 1036 मिट्रिक टन के सतर से लगभग 4 प्रतिशत घटकर वर्ष 2013-14 में 999 मिट्रिक टन हो गया है। बिक्री में यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद है कि मांग वर्ष 2012-13 में 6544 मिट्रिक टन के स्तर से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 7287 हो गई अर्थात् 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आयातों में तेजी की कीमत पर बिक्री में हानि हुई जैसाकि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

वित्तीय वर्ष	घरेलू बिक्री (मि.टन)	कुल मांग (मिट्रिक टन)
2010-11	505	4,580
2011-12	632	5,278
2012-13	1036	6,544
2013-14	999	7,705

#### 41. रोजगार:

घरेलू उद्योग ने नुकसान अविध में विचाराधीन उत्पाद में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। आवेदक ने कहा है कि क्षमता में वृद्धि, उत्पाद का उत्पादन एवं बिक्री करने के प्रयासों में वृद्धि के कारण तथा इस तथ्य के कारण कि कर्मचारी केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित हैं, और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। यह माना गया है कि रोजगार कई अन्य मानदंडों पर निर्भर करता है और यह घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाता है।

		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	53	96	105	105

#### 42. उत्पादकताः

उत्पादन में वृद्धि होने से, उत्पादकता आधार वर्ष से वर्ष 2012-13 तक बढ़ी और उसके बाद वर्ष 2013-14 में मामूली कमी आई। तथापि, घरेलू उद्योग की उत्पादकता प्रति यूनिट कर्मचारी वर्ष 2011-12 में घटी तथा उसके बाद कर्मचारियों में वृद्धि के कारण बढ़ी।

वित्तीय वर्ष	प्रतिदिन उत्पादकता (मिट्रिक टन) (सूचीबद्ध)	उत्पादकता प्रति कर्मचारी (सूचीबद्ध)
2010-11	100	100
2011-12	102	56
1012-13	129	65
2013-14	128	75

**43. लाभ और हानि** क. घरेलू उद्योग के निवेशों पर लाभ प्रदायकता और प्रतिफल में इस सीमा तक तेजी से गिरावट हुई है कि घरेलू उद्योग वित्तीय नुकसान उठा रहे हैं। घरेलू उद्योग की वित्तीय हानि में जांच की अविध के दौरान और अधिक तेजी आई है। यह नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है:-

वित्तीय वर्ष	लाभ	लाभ प्रदायकता	निवेश पर प्रतिफल
	(रु./लाख)	(रु./किलोग्राम)	% (अनुक्रमित)
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	
2010-11	(100)	(100)	-100%
2011-12	(249)	(199)	-155%
2012-13	(378)	(184)	-146%
2013-14	(1174)	(593)	-549%

- ख. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि बाज़ार में आयातित सामानों की भारी मात्रा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग को अपने मूल्य, बिक्री लागत से कम रखना पडा। इससे उनकी लाभ प्रदायकता तेजी से प्रभावित हुई, जिसमें हाल में वर्ष 2013-14 की अविध के दौरान उल्लेखनीय रूप से तेजी आई है। अत:, घरेलू उद्योग, आयात के कारण गंभीर वित्तीय क्षति का सामना कर रहा है।
- ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि सोडियम साइट्रेट एक कम मुनाफ़े वाला उत्पाद है और निर्माताओं को हमेशा कम मुनाफ़ा प्राप्त होता रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग का दावा यह है कि कम मुनाफा या लाभ की बात तो दूर उन्हें वित्तीय हानि हुई है। यह भी नोट किया गया कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा दिनोंदिन बढ़ी है।

## 44. अन्य महत्वपूर्ण कारण :

सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के अनुलग्नक के पैरा (2) में यह निर्धारित है कि उप-पैरा (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विषयपरक साक्ष्य के आधार पर की गई जांच से यह पता नहीं चल जाता कि संबंधित वस्तु के बढ़े हुए आयात तथा गंभीर क्षति या खतरे के बीच औपचारिक संबंध विद्यमान है और जब बढ़े हुए आयात के अतिरिक्त कारण घरेलू उद्योग को ''गंभीर क्षति" पहुंच रहे हों तब उस समय इस प्रकार की ''गंभीर क्षति" का कारण बढ़ा हुआ आयात नहीं माना जाएगा। तथापि, कोई विशिष्ट कारण न तो भारतीय नियमों के अंतर्गत अथवा डब्ल्यू टी ओ समझौते के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। महानिदेशक से यह अपेक्षित है कि वह छान-बीन के दौरान उसकी जानकारी में आए कारणों की जांच करे। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक ने सामान्य रूप से ज्ञात उन कारणों की भी जांच की है, जो रक्षोपाय संबंधी विधान के तहत किसी विशिष्ट बाध्यता के अभाव में एंटी डंपिंग विधान के अंतर्गत विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं।

- **44.1** मांग/खपत : अत:, संभावित अन्य कारण, जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के पीछे हो सकते थे, की जांच की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक हैं :-
  - क. उत्पाद की मांग : विचाराधीन उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। अत: उत्पाद की मांग में संभावित कमी, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है। वस्तुत: समग्र मांग

बढ़ी है, वहीं यह देखा गया कि आयात में वृद्धि की दर, मांग में वृद्धि की दर से काफी अधिक थी। आयात में बाज़ार के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आयात, घरेलू बाज़ार में अच्छी-खासी हिस्सेदारी रखते हैं। अत: यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बढ़े हुए आयात ने मांग का एक प्रमुख हिस्सा छीन लिया है।

ख. भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को सभी स्रोतों से सभी घरेलू उत्पादकों और आयात की बिक्री के जोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया कि सोडियम साइट्रेट की मांग में पूरी अविध के दौरान एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। यह भी नोट किया गया कि जहां मांग में 68% की वृद्धि हुई, वहीं आयात में 102%, जो यह दर्शाती है कि आयात में वृद्धि, देश में उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि से कहीं अधिक थी।

मांग	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की बिक्री	एम टी	505	632	1,036	999
अन्य उत्पादकों (समर्थक सहित)	एम टी	1454	1769	1,787	1,405
की बिक्री					
कुल आयात	एम टी	2,621	2,877	3,721	5,300
मांग/खपत	एम टी	4,580	5,278	6,544	7,705

- ग. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि देश में उत्पाद की वास्तविक मांग, याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित की गई मांग के मुकाबले बहुत अधिक थी। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि खपत का निर्धारण, विचाराधीन उत्पाद के आयात तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा बिक्री पर गौर करते हुए किया गया है। इस संबंध में उपलब्ध सारी सूचना को ध्यान में रखा गया है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए, अनुमानित मांग के संबंध में उनका दावा तथ्यों के अभाव में सिद्ध नहीं हो सका।
- घ. वर्ष 2013-14 में उत्पादन में गिरावट, पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में इस वर्ष मांग में हुई 18% की वृद्धि के बावजूद थी। इसके अतिरिक्त, जबिक वर्ष 2013-14 में बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई, वहीं घरेलू बाज़ार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया कि घरेलू उद्योग की क्षमता की उपयोगिता कम रही है, जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन उस स्तर से काफी कम है जो घरेलू उद्योग, बढ़े हुए आयात के अभाव में उत्पादन कर सकता था। स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग, आयात में तेजी के अभाव में अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से उपयोग करता होता।

## 44.2 खपत की तुलना में आयात में वृद्धि:

विशुद्ध रूप से आयात में वृद्धि के अतिरिक्त और भारतीय उत्पादन के संबंध में यह नोट किया गया कि जांच की अविध के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात, देश में उत्पाद की खपत के मुकाबले भी बढ़ा है। नीचे दी गई तालिका और आरेख से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 में, कुल खपत की तुलना में आयात में हुई 57.23% की वृद्धि, वर्ष 2013-14 में बढ़कर 68.80% हो गई अर्थात् 11% की वृद्धि रही, जो कि एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी है।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	खपत	खपत की तुलना मेंआयात
	(एम टी)	(एम टी)	(%)
2010-11	2,621	4,580	57.23%
2011-12	2,877	5,278	54.51%
2012-13	3,721	6,544	56.86%
2013-14	5,300	7,705	68.80%

44.3 माल-सूची (इन्वेंट्री): घरेलू उद्योग माल-सूची के जमाव का सामना कर रहा है, जिसमें जांच की अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी, जो आधार वर्ष अर्थात् वर्ष 2010-11 की स्थिति के मुकाबले वर्ष 2013-14 में लगभग पाँच गुणा अधिक थी। जब इसकी तुलना वर्ष 2012-13 से की जाती है तब, यह, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में उत्पादन में मामूली गिरावट के बावजूद वर्ष 2013-14 में लगभग 65% अधिक रही थी।

6	X .
वित्तीय वर्ष	औसत माल-सूची
	(एम टी)
2010-11	18
2011-12	37
2012-13	52
2013-14	86

यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की माल-सूची में, बाज़ार में उत्पाद की मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री बढ़ा पाने में घरेलू उद्योग की नाकामी के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जिसके फलत: गंभीर क्षति हुई।

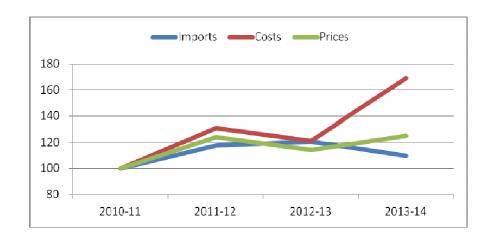
44.4 निर्यात निष्पादन : आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। यह नोट किया गया कि जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में लगभग 10% कम भी हो गई। अत: निर्यात घरेलू उद्योग की बिक्री-लागत पर किया गया, जिसमें वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात कमी आई, जिसका आशय यह है कि घरेलू बाज़ार में उत्पाद की उपलब्धता बढ़ी। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को कथित क्षति घरेलू व्यापार के कारण हुई। आवेदकों ने घरेलू व्यापार के बारे में लागत तथा क्षति संबंधी जानकारी दी है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने, निर्यात संबंधी अपेक्षा या इसके विलोमत: का उल्लेख करते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति न किए जाने के बारे में कोई साक्ष्य सामने नहीं रखा है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसे केवल निर्यात हेतु जबरन विवश होना पडा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि हो रही थी। घरेलू उद्योग का लक्ष्य घरेलू बाज़ार है और घरेलू उद्योग केवल उसकी जरूरतों को पूरा करेगा और उत्पाद का निर्यात तभी होगा, जब घरेलू उद्योग, उत्पाद को घरेलू बाज़ार में बेच पाने में असमर्थ रहे। इसलिए, यह दावा कि घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात के कारण नहीं हुई, स्वीकार किया जाता है।

अवधि	निर्यात (एम टी)
2010-11	674
2011-12	545
2012-13	501
2013-14	448

## 44.5 मूल्य में कमी, रोक/मंदी:

क. यह देखा गया कि सोडियम साइट्रेट के आयात का अंतिम कुल मूल्य उल्लेखनीय रूप से न केवल घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य बल्कि घरेलू उद्योग की उत्पादन-लागत से भी कम है। घरेलू और आयातित उत्पादन के बीच मूल्य में उल्लेखनीय अंतर है। आयात के अंतिम कुल मूल्य की तुलना में विक्रय-लागत और बिक्री-मूल्य में अन्तर निम्नानुसार है:-

	इकाई	2011-12	2012-13	2013-	2014-
				14	15
आयात का अंतिम कुल मूल्य	रु./किलोग्राम	44.67	52.62	53.87	48.92
	प्रवृत्ति	100	118	121	110
	(अनुक्रमित)				
विक्रय लागत	रु./किलोग्राम	100	131	121	169
	(अनुक्रमित)				
बिक्री मूल्य	रु./किलोग्राम	100	124	114	125
	(अनुक्रमित)				



- ख. उपर्युक्त तालिका और आरेख से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का बिक्री-मूल्य, जांच की अविध के दौरान लागत के स्तर से नीचे रहा है। जबिक विक्रय लागत और बिक्री मूल्य समय, के साथ-साथ बढ़े हैं, वहीं विक्रय लागत में वृद्धि की दर, बिक्री मूल्य में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, जबिक हानि की अविध के दौरान, आयात के अंतिम कुल मूल्य में 10% की बढ़ोतरी हुई, वहीं बिक्री मूल्य में 25% और लागत में 69% की वृद्धि हुई। यह तथ्य कि वर्ष 2012-13 में अंतिम कुल मूल्य, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य से अधिक था, यह जाकर वर्ष 2011-12 की तुलना में उक्त वर्ष में बिक्री में हुई तेजी से परिलक्षित हुई, जिसके फलत: हानि में कमी आई। इस प्रकार से, सस्ते आयात, जिसके कारण मूल्य में कमी आयी तथा घरेलू उद्योग की मंदी के बीच निश्चित रूप से संबंध है, जिसके कारण हानि में बढ़ोतरी हुई। अत: आयात घरेलू उद्योग के मूल्य में गिरावट और मंदी ला रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित हुई है।
- ग. हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क कि सोडियम साइट्रेट के उत्पादन की कच्ची सामग्री अर्थात ''साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट" तथा अंतिम उत्पाद ''सोडियम साइट्रेट" का मूल्य लगभग बराबर है और इसलिए, सोडियम साइट्रेट

का उत्पादन करना एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। वस्तुत: इस तर्क से यह प्रदर्शित होता है कि आयात ऐसे मूल्य पर हो रहा है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से बहुत कम है। यह भी एक कारण प्रतीत हो रहा है जिसके बिना पर मैसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसे निर्माता आयात के क्षेत्र में चले गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि देश में उपलब्ध कम मूल्य पर आयात के मद्देनजर यह कहना कि देश में सोडियम साइट्रेट का उत्पादन करना एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा, कुल मिलाकर सार्वजनिक हित के खिलाफ़ है। केवल आयात पर ही निर्भर होना उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। कुल मिलाकर घरेलू उद्योग की उपस्थित सार्वजनिक हित में है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कहा गया है, यह उनके द्वारा अंतिम उत्पाद और कच्ची सामग्री के मूल्य के बारे में प्राधिकरण को भ्रम में डालने का प्रयास है, जो उतना सरल भी नहीं है, जितना उसे प्रस्तुत किया गया है। यह नोट किया गया कि 1 कि.ग्रा. सोडियम साइट्रेट के उत्पादन के लिए अन्य कच्ची सामग्रियों सहित केवल 0.75 कि.ग्रा. साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अत: जैसाकि घरेलू उद्योग ने कहा है, सोडियम साइट्रेट के मूल्य की तुलना केवल साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के मूल्य से करना सही नहीं होगा।

घ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मूल्य में कमी के दावों को सिद्ध करने के लिए माह-वार/ितमाही-वार आयात मूल्य नहीं दिया गया है। यह देखा गया है कि एक विशिष्ट परिस्थिति, जिसमें आयात संबंधी आंकड़ों का माह-वार/ितमाही-वार विश्लेषण अपेक्षित हो, बताई नहीं गई है और कानून के अनुसार, सुसंगत प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि विनिमय दर में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव से वस्तुत: बेहद विकृत स्थिति प्रदर्शित होती है।

## ङ. अन्य परिवर्तन, जिनके कारण गंभीर क्षति या खतरा उत्पन्न हुआ :

- (क) खपत के पैटर्न में बदलाव: घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने खपत के पैटर्न में परिवर्तन का दावा किया है और इसलिए रिकार्ड यह नहीं प्रदर्शित करता है कि जहां तक भारतीय बाज़ार का संबंध है, खपत के पैटर्न में कोई विशेष बदलाव आया है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग के इस दावे को गलत ठहराने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है।
- (ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधी प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धाः ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड में मौजूद नहीं है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधी प्रक्रियाओं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है।
- (ग) प्रौद्योगिकी में विकास: आवेदक ने यह दावा किया है कि उत्पादन के निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका खंडन किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं किया गया है। अत: इस मामले में प्रौद्योगिकी का विकास, क्षति का कारण नहीं है।
- (**घ**) अत:, यह नोट किया गया कि अन्य संभावित कारणों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। कम मूल्य पर आयात में वृद्धि को छोड़कर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने के संबंध में कोई अन्य कारण नहीं रहा।

#### 45. गंभीर क्षति के बारे में निष्कर्ष:

- क. विचाराधीन उत्पाद के आयात में वास्तविक रूप से तथा भारत में इसके उत्पादन के संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में सोडियम साइट्रेट के आयात की मात्रा में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। आयात में हुई इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों में गंभीर क्षति हुई है।
- ख. जांच की अविध के दौरान बढ़ते आयात के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी आई। घरेलू उद्योग के प्रयासों से वर्ष 2012-13 तक बाज़ार में भागीदारी, उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता-उपयोगिता बढ़ी, फिर भी बढ़ते आयात के कारण इसके बाद, वर्ष 2013-14 में इन सभी पैरामीटरों के निष्पादन में गिरावट आई। घरेलू उद्योग, विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग, सस्ते आयात के कारण विचाराधीन उत्पाद को अपनी उत्पादन लागत से भी नीचे बेच रहा है।

- ग. निवेश पर लाभ और मुनाफा जैसे पैरामीटर ऋणात्मक रहे और घरेलू उद्योग की हानि, जांच की अवधि के दौरान और बढ़ी। अवधि के दौरान मूल्य में गिरावट देखी गई। आयात का अंतिम कुल मूल्य, घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री मूल्य से नीचे रहा, जिसके कारण घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप मूल्य में वृद्धि नहीं कर पाया।
- घ. अत:, घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव रखने वाले सभी संगत कारणों के मद्देनजर घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन, 'समग्र रूप से उल्लेखनीय हानि' प्रदर्शित करता है। अत:, यह निष्कर्ष दिया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बढ़े आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई।

## 46 गंभीर हानि का खतरा:

- क. भारत में सोडियम साइट्रेट का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को बढ़ते आयात तथा भारत में होने वाले आयात की मात्रा की मौजूदा प्रवृत्ति से गंभीर हानि का खतरा भी है। समय के साथ-साथ आयात की बाजार में भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन-क्षमता तथा निर्यात के प्रति उनके दृष्टिकोण पर विचार करते हुए इस बात की संभावना काफी प्रवल है कि आयात में बढ़ोतरी जारी रहेगी।
- ख. सोडियम साइट्रेट के बिक्री मूल्य और आयात के बीच मूल्य के अंतर ने भारतीय बाजार को निर्यातकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल बना दिया है। यह नोट किया गया कि आयात-मूल्य, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के स्तर से काफी नीचे है। उद्योग को पहले से वित्तीय क्षति हो रही है। इसके परिणामस्वरूप आयात में होने वाले वृद्धि के कारण भविष्य में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का जबरदस्त खतरा है।
- ग. आयात की बढ़ती प्रवृत्ति सहित लाभ और निवेश पर मुनाफ़े की दृष्टि से घरेलू उद्योग की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष दिया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क की लेवी के अभाव में, घरेलू उद्योग, जिसे जांच की अविध के दौरान गंभीर क्षति हुई है, को और गंभीर क्षति होने का खतरा है, जो घरेलू उद्योग की पहले से अनिश्चित स्थिति को और गंभीर कर सकती है।

## 47. बढ़े आयात तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच औपचारिक संबंध:

- 1. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुसार, महानिदेशक (रक्षोपाय) को "अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के अनुलग्नक में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण" करने के लिए बाध्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुलग्नक के पैरा 2 में कथित रूप से बढ़े आयात और गंभीर क्षति या उसके खतरे के बीच औपचारिक संबंध स्थापित किया जाना अपेक्षित है। नियम 8 के अनुलग्नक के पैरा 2 में निम्नानुसार उपबंधित है:
- पैरा (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विषयपरक साक्ष्य के आधार पर की गई जांच से यह पता नहीं चल जाता कि संबंधित वस्तु के बढ़े हुए आयात तथा गंभीर हानि या खतरे के बीच औपचारिक संबंध विद्यमान है और जब बढ़े हुए आयात के अतिरिक्त कारण घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" पहुंचा रहे हों तब उस स्थिति में इस प्रकार की ''गंभीर क्षति" का कारण बढ़ा हुआ आयात नहीं माना जाएगा।
- ।. कोरिया-डेयरी संबंधी पैनल ने ''कार्य-कारण-संबंध" के निर्धारण हेतु बुनियादी दृष्टिकोण निर्धारित किया था :

"इसके औपचारिक संपर्क का आकलन करने में हमारी यह राय है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को यह विश्लेषण तथा निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या गंभीर क्षित को सिद्ध करने के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण के विचाराधीन उद्योग में घटनाक्रम, बढ़े आयात के कारण हुए हैं। कारणों के बारे में अपना आकलन करते समय राष्ट्रीय प्राधिकरण, उक्त उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले विषयपरक और परिमाण-योग्य सभी संगत कारणों का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने बढ़े आयात के अतिरिक्त उन कारणों की पहचान की है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षिति हुई, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के कारणों से हुई किसी क्षिति को बढ़े आयात के कारण हुआ न माना जाए। औपचारिक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ेगा कि उसके घरेलू उद्योग को क्षिति बढ़े आयात के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ेगा कि एस एम पी पी के आयात से दुग्ध पाउडर और कच्चे दूध का उत्पादन कर रहे घरेलू उद्योग को क्षिति हुई है। इसके

- अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, कोरियाई प्राधिकरण बाध्य होगा कि वह अन्य कारणों से हुई किसी क्षति के लिए बढ़े आयात को दोषी न माने।"
- 2. उपर्युक्त पैरामीटरों के व्यापक मूल्यांकन से यह प्रदर्शित होता है कि गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा, बढ़े हुए आयात के कारण है। कारण का पता लगाने के उद्देश्य से, विषयपरक और परिमाण-योग्य प्रकृति के सभी संगत कारणों, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव हो सकता है, का मूल्यांकन किया गया है। मौजूदा मामले में, निम्नलिखित बातें इस संबंध में प्रासंगिक हैं
  - i. आयात से घरेलू उद्योग के मूल्यों में कमी हो रही है। इसके फलत: आयात की मात्रा उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है;
  - ii. चूंकि घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य के मुकाबले कम मूल्य पर आयात उपलब्ध हैं इसलिए उपभोक्ता आयात की ओर मुड़ रहे हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग बिक्री की कमी और बढ़ रही माल-सूची की समस्या का सामना कर रहा है;
  - iii. आयात-मूल्य वस्तुत: घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है, और इसलिए आयात, घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की लागत के स्तर तक भी मूल्य को बढ़ाने से रोक रहा है।
- iv. डंप आयातों से मूल्य में कमी/गिरावट के प्रभाव से घरेलू उद्योग की लाभ प्रदायकता में इस सीमा तक कमी आई कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- v. आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी और उसने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया।
- vi. कम मूल्य पर आयात के बढ़ने के कारण घरेलू उद्योग, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन तथा बिक्री बढ़ाने में असफल रहा है।
- vii. वर्ष 2013-14 में, बढ़े आयात के कारण क्षमता की उपयोगिता, बिक्री, बाजार में हिस्सेदारी, लाभ, निवेश पर मुनाफा, सभी में कमी आई।
- ग. अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति, बढ़े आयात से हुई है, जिससे आगे भी क्षति होने का खतरा है।

### 48. समायोजन संबंधी योजना :

- क. सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 (2) में 'आयात से प्रतिस्पर्धा के प्रति सकारात्मक सामंजस्य बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों या उन प्रयासों, जिनकी योजना बनाई जा रही है या दोनों' के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ समझौते में यह उपबंधित है कि कोई सदस्य, रक्षोपाय संबंधी उपाय केवल उसी सीमा तक लागू करेगा जितनी गंभीर क्षति को रोकने या उसे दूर करने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो।
- ख. निर्णायक रक्षोपाय उपाय का उद्देश्य, घरेलू उत्पादकों को वह सीमित समय-सीमा उपलब्ध कराना है, जिसमें वह पुनर्गठित होकर आयात से अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (4) तथा सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16(2) में उपाय का कोई संभावित विस्तार निषिद्ध है यदि इस बात का कोई साक्ष्य न हो कि घरेलू उत्पादक समायोजन कर रहा है।
- ग. इस मामले में, घरेलू उत्पादक ने समायोजन योजना निर्धारित की है, जिसमें बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में विस्तार, मशीनरी/प्रौद्योगिकी को स्वचालित बनाना, ऊर्जा लागत में बचत और लागत में कमी लाने हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दिया गया है।
- घ. आवेदक ने उल्लेख किया है कि अपनी याचिका में उल्लिखित समायोजन संबंधी अपनी योजना के अनुसरण में वे मार्च, 2014 माह में एक नई मशीन खरीद चुके हैं। अब क्षमता बढ़कर 5000 एम टी हो गई है। यह उल्लेख किया गया है कि संयंत्र में विस्तार होने से कंपनी, होने वाले आयात से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने चार वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क हेतु अनुरोध किया है जिससे कि वे आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में रहें।
- ङ. आवेदक द्वारा यह भी स्पष्ट िकया गया है िक उपर्युक्त समायोजन संबंधी योजना के कारण कंपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती स्वीकार करने की स्थिति में होने के साथ-साथ भारत में अध्यधीन सामानों की संभावित मांग को पूरा करने में समर्थ होगी। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है िक केवल क्षमता को बढ़ाने की योजना पर्याप्त नहीं है क्योंिक सभी निर्माता साइट्रिक एसिड पर निर्भर हैं। तथापि, यह नोट िकया गया कि यह तर्क िक

- भारतीय उद्योग साइट्रिक एसिड पर निर्भर है, सोडियम साइट्रेट के आयात से संबंधी मौजूदा जांच के उद्देश्य से नितांत अनावश्यक है।
- च. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह निष्कर्ष दिया जाता है कि आवेदक ने सोडियम साइट्रेट की बढ़ती मांग को पूरा करने के संबंध में एक व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत की है, जिसमें लागत में कमी, क्षमता के निर्माण पर ध्यान दिया गया है।

### 49 अप्रत्याशित घटनाक्रम:

- क) यह नोट किया गया कि महानिदेशक (रक्षोपाय) की कोई सीधी बाध्यता/अपेक्षा नहीं है कि वह अप्रत्याशित परिस्थितियों का विश्लेषण करें क्योंकि इस प्रकार की कोई विशिष्ट अपेक्षा न तो भारतीय नियमों, जिसमें वह क्रियाविधि दी गई हो, जिसका पालन अप्रत्याशित घटनाक्रमों के विश्लेषण हेतु किया जाना हो, में और न ही रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ समझौते में है, जिसमें उस क्रियाविधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका पालन किया जाना चाहिए या उन पैरामीटरों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अप्रत्याशित घटनाक्रमों पर निर्णय लेते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। तथापि, गैट के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय संबंधी समझौते में राष्ट्रीय प्राधिकारी के लिए यह बाध्यकारी बनाया गया है कि वह उन ''अप्रत्याशित घटनाक्रमों'' की जांच करेगा जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो। यह महानिदेशालय निरंतर अपनी छान-बीन के दौरान ''अप्रत्याशित घटनाक्रमों या परिस्थितियों की जांच कर जांच करता रहा है। अतः यह महत्वपूर्ण समझा गया कि उन अप्रत्याशित घटनाक्रमों या परिस्थितियों की जांच की जाए जिसके कारण आयात बढ़े हैं। इस संबंध में मैंने पाया कि गैट, 94 के अनुच्छेद XIX में यह उपबंधित है कि गंभीर क्षति, अप्रत्याशित घटनाक्रमों का परिणाम होनी चाहिए। गैट 1994 के अनुच्छेद XIX में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:
  - 1.(क) यदि प्रशुल्क संबंधी छूट सहित अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण और इस समझौते के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्ष की बाध्यता के प्रभाव से कोई उत्पाद, उतनी बढ़ी मात्रा में और इस प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत उक्त संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में आयातित किया जा रहा हो, जिससे कि उसके समान या सीधी प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पादों के संबंध में उक्त भू-भाग के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती हो या होने का खतरा हो, तब संविदाकारी पक्ष, उक्त उत्पाद के संबंध में तथा उस सीमा तक एवं उस समय तक, जो इस प्रकार की क्षति को रोकने या दूर करने के लिए आवश्यक हो, बाध्यता को पूर्णत: या उसके भाग या छूट को वापस लेने या आशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
  - (ख) अर्जेंटिना- फुटवियर (ई सी) मामले में अपीलीय निकाय ने यह निर्णय दिया कि "अप्रत्याशित घटनाक्रमों" का अर्थ वे घटनाक्रम हैं, जिनकी आशा नहीं की गई थी। "अप्रत्याशित घटनाक्रमों" से अपेक्षित है कि घटनाक्रम, जिनके परिणामस्वरूप उतनी मात्रा में तथा इस प्रकार की स्थितियों में एक उत्पाद का आयात किया गया जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई या उनका खतरा बना, 'अप्रत्याशित' होने चाहिएं। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि जब सदस्य द्वारा बाध्यता का निर्वहन किया गया तब अप्रत्याशित घटनाक्रम वे घटनाक्रम थे, जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सका या जिनकी आशा नहीं थी।
  - ग. आवेदक ने आयात में तेजी आने के अनेक कारण दिए हैं, जो उनकी समझ में इस मामले में अप्रत्याशित घटनाक्रम रहे, जिनका सार नीचे दिया गया है :

## ग.1 <u>चीन की क्षमता में वृद्धि, जो भारत को निर्यात में परिवर्तित हुआ :</u>

भारत में अधिकांश आयात, चीनी मूल के और हाल में कनाडा से होते हैं, जैसाकि नीचे देखा जा सकता है :

		मात्रा (एम टी)			आयात में वि	आयात में हिस्सेदारी			
देश		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आस्ट्रिय	Т	=	2	5		0%	0%	0%	0%
चीन आर	पी	2,578.00	2,804.00	3,526.00	4,350.48	98%	97%	95%	82%
कनाडा					699.60	0%	0%	0%	13%
जर्मनी		11.02	64.80	19.57	41.16	0%	2%	1%	1%

पोलैंड	0.05		0.17	0.95	0%	0%	0%	0%
स्पेन	23.00	4.90	165.04	90.01	1%	0%	4%	2%
थाईलैंड	4.00				0%	0%	0%	0%
यू के	4.40	0.38	0.30	0.50	0%	0%	0%	0%
यू एस ए	0.27	1.06	2.74	117.59	0%	0%	0%	2%
अनिर्दिष्ट			2.00		0%	0%	0%	0%
कुल	2,620.74	2,877.21	3,721.12	5,300.29	100%	100%	100%	100%

यह देखा गया कि चीन से होने वाला आयात, जांच की अविध के दौरान भारत में हुए कुल आयात का लगभग 82% है (5300 एम टी के संचयी आयात की तुलना में चीन से संचयी आयात 4351 एम टी रहा)। यह इसिलए रहा क्योंकि चीन जैसे देशों के उत्पादकों के पास अत्यिधक क्षमता है। चीन के बाजार में अत्यिधक क्षमता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साइट्रिक एसिड और कितपय साइट्रेट लवणों (सॉल्ट), जिसमें सोडियम साइट्रेट शामिल है, के आयात के संबंध में डंपिंग-रोधी जांच की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मानना रहा है कि चीन की क्षमता उल्लेखनीय है। वर्ष 2010 के लिए साइट्रिक एसिड और कितपय साइट्रेट लवणों की अनुमानित क्षमता 21,95,911 एम टी आंकी गई थी। इसके कारण चीन में मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर काफी अधिक हो गई है। चीन ने अपनी घरेलू मांग की तुलना में अपनी क्षमता काफी बढ़ा ली है। नीच दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि मांग और आपूर्ति के बीच जो दूरी है, वह काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप चीन पी आर के निर्यातक भारत को सामान निर्यात करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निष्कर्षों में अनुमान लगाए गए अनुसार, मांग और आपूर्ति का अन्तर निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

(चीन में मांग और आपूर्ति में अन्तर) 000 पौंड में -							
वर्ष 2006 2007 2008 2009 20					2010		
प्रत्यक्ष खपत	323	460	475	589	607		
क्षमता	1443	1932	2047	2193	2195		
उत्पादन	1247	1719	1807	1779	1834		
अन्तर (उत्पादन-	924	1259	1332	1190	1227		
खपत)							

स्रोत : संयुक्त राज्य अमेरिका के निष्कर्ष

यह देखा गया कि चीन के उत्पादकों की मौजूदा अधिक क्षमता, भारत में उत्पाद संबंधी सकल भारतीय मांग पर गौर करते हुए उल्लेखनीय रूप से अधिक है। चीन के विभिन्न उत्पादकों की क्षमता भारत में कुल मांग से कहीं अधिक है। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि लगातार बढ़ते आयात से यह पता चलता है कि इन देशों के उत्पादकों ने अपनी क्षमता अत्यधिक बढ़ा ली है जिसके कारण उन्हें कम मूल्य पर विभिन्न बाजारों में निर्यात करने पर विवश होना पड़ रहा है। उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि के साथ भारत एक बड़े बाजार होने के नाते यहां पर होने वाली मांग उन्हें आकर्षित करती है। विदेशी उत्पादक अधिक निर्यात का दृष्टिकोण रखते हैं और चूंकि उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है इसलिए वे भारत में निर्यात को बढ़ाकर भारतीय बाजारों में अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास कर रहे हैं।

## ग.2 विभिन्न देशों (यू एस, ई सी और ब्राजील) द्वारा लगाया गया एंटी डंपिंग शुल्क

घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अनेक देशों ने मुख्यत: चीन से साइट्रिक एसिड और कितपय साइट्रेट लवणों, जिनमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है, के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क पहले से लगा रखा है। ई सी ने चीन के खिलाफ विचाराधीन उत्पाद पर पहले लागू किए गए अपने एंटी डंपिंग उपायों की समीक्षा भी की है। विचाराधीन उत्पाद पर इन देशों द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाने के कारण ये बाजार चीन के लिए प्रतिबंधित हो गए हैं। अत: अपनी अत्यधिक क्षमता के साथ चीन को किसी अन्य लाभदायक स्थान पर अपने निर्यात का मुंह मोड़ना पड़ रहा है और इसी क्रम में उसने भारत को निर्यात करना आरंभ किया है।

रिकार्ड में उपलब्ध सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह देखा गया कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का आयात, चीन की अत्यधिक क्षमता, वहां मौजूद मांग और आपूर्ति में अन्तर तथा विभिन्न देशों द्वारा सोडियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क के कारण बढ़ा है। चीन के उत्पादक अपने उत्पाद के लिए एक उभरते हुए बाजार की तलाश करने के लिए विवश है और उन्होंने एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में भारत को लक्ष्य बनाया गया, जिसके फलत: भारत में आयात बढ़ा। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए अनुसार, ये सभी कारण, सोडियम साइट्रेट के आयात, मुख्यत: चीन से, में बढ़ोतरी के संबंध में अप्रत्याशित घटनाक्रम का निर्माण करते हुए प्रतीत होते हैं।

अत:, मैं, चीन से सोडियम साइट्रेट के आयात के खिलाफ विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क के साथ-साथ अत्यधिक क्षमता के कारण चीन में इस उत्पाद के संबंध में मांग और आपूर्ति के बीच बहुत अधिक अंतर को अप्रत्याशित घटनाक्रम मानता हूं, जिसके परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और घरेलू क्षति का खतरा रहा।

## 50 सार्वजनिक हित:

क. रक्षोपाय संबंधी समझौते के अनुच्छेद 3 में निम्नानुसार उल्लिखित है :

"कोई सदस्य, पूर्व में स्थापित तथा गैट 1994 के अनुच्छेद X के अनुरूप सार्वजिनिक की गई प्रक्रियाओं के अनुसरण में उक्त सदस्य के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा की गई जांच के बाद ही रक्षोपाय संबंधी उपाय लागू कर सकता है। इस जांच में, सभी हितबद्ध पक्षकारों को उचित सार्वजिनिक नोटिस और सार्वजिनिक सुनवाई या अन्य उचित माध्यमों, जिसमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार अन्य बातों के साथ-साथ रक्षोपाय उपाय को लागू करना या अन्यथा सार्वजिनक हित में होने के बारे में साक्ष्य या अपनी राय रख सकते हों, शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जिसमें उनके निष्कर्षों और तथ्य एवं कानून से संबंधित सभी समीचीन मुद्दों पर लिए गए उचित निर्णयों का उल्लेख होगा।"

- ख. एक अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों के हितों में अंतर होता है और कभी-कभी प्रतिस्पर्धात्मक भी। रक्षोपाय शुल्क के लगाने से विभिन्न व्यक्ति अलग-अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं और यदि उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक हित हों, तब अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों पर इसका प्रभाव सबसे उपयुक्त भी नहीं होता है। अत: अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न समूहों के हितों का उपलब्ध सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया है।
- ग. आयात का अंतिम कुल मूल्य, (क) घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य, और (ख) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इन आयातों से घरेलू मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आ रही है। मूल्य में गिरावट से मूल्य पर दबाव बन रहा है। यह देखा गया कि घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य, बिक्री लागत से बहुत कम है। बाजार में बने रहने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में अपना बिक्री मूल्य बढ़ाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण भारी क्षति हुई। रक्षोपाय शुल्क न लगाए जाने की स्थिति में निवेश पर लाभ और मुनाफे में गिरावट की दर को देखते हुए घरेलू उद्योग के पास, जैसाकि उनके द्वारा दावा किया गया है, अपना व्यापार बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का लगाया जाना, सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि इससे न केवल घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की रोकथाम होगी अपितु घरेलू उद्योग में और गिरावट होने पर भी अंकुश लगेगा। जहां तक उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं पर रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का संबंध है, यह देखा गया है कि सोडियम साइट्रेट का उपयोग मुख्यत: ओ आर एस, पनीर, खांसी के सीरप, सॉफ्ट ड्रिंक, जेली, फोटोग्राफी उद्योग, पेय पदार्थों और दवा उद्योग में होता है।
- ङ घरेलू उद्योग ने एक उदाहरण का उल्लेख किया है तथा संभावित अंतिम उत्पादों पर 30% रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव की गणना करने का प्रयास किया है। घरेलू उद्योग ने ऊपर उल्लिखित प्रत्येक उपभोक्ता क्षेत्र में सोडियम साइट्रेट की अनुमानित खपत पर विचार किया है और तत्पश्चात अंतिम लागत पर इसके प्रभाव की गणना की है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क के कारण मूल्य में होने वाली 30% वृद्धि यदि अंतिम उत्पाद पर पूर्णत: हस्तान्तरित कर दी जाती है (यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग मूल्य को

30% से बढ़ा देंगे) तो इसका प्रभाव अंतिम उत्पादों पर नगण्य होगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:-

## क्षेत्र-वार विचाराधीन उत्पाद की खपत और तैयार माल की प्रति इकाई लागत

उत्पाद	भूमिका	खपत	अनुमानित लागत	लागत पर प्रभाव यदि
			आई एन आर	30% शुल्क
ओ आर एस	एक अवयव के रूप में	2.9 ग्रा./लीटर	0.1885/लीटर	0.008%
पनीर	एक परिरक्षक के रूप में	2.30%	0.13/100 ग्रा.	0.016%
खांसी सीरप	कफ़-निस्सारक के रूप में	1.1 ग्रा./मि.ली.	0.0175/100 मि.ली.	0.049%
सॉफ्ट ड्रिंक	नमकीन एवं तेज स्वाद के लिए	<2%	<0.12/लीटर	0.090%
जेली	नमकीन एवं तेज स्वाद के लिए	<2%	<0.12/100 ग्रा.	0.018%
फोटोग्राफी उद्योग	जमाव-रोधी के रूप में	<2%	<0.12/100 ग्रा.	0.004%
पेय पदार्थ	नमकीन एवं तेज स्वाद के लिए	<2%	<0.12/लीटर	0.072%
दवा उद्योग	जमाव-रोधी के रूप में	<2%	<0.12/100 ग्रा.	0.004%

- च. इस छानबीन में, हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग के उपर्युक्त दावे का खंडन नहीं किया गया है। इस मामले में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विपरीत तथ्य/उत्तर न दिए जाने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा रखा गया तथ्य उचित समझा गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदर्शित किए गए अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विषयपरक उत्पाद के प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर पड़ने वाला रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव, मामूली होगा। यह निष्कर्ष दिया जाता है कि यदि मूल्य में 30% वृद्धि की जाती है तक अंतिम उत्पाद पर इसका कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के कारण अंतिम उत्पादों के मूल्य में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी।
- छ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से स्थिति दो केन्द्रों में केन्द्रित हो जाएगी और उत्पाद के मूल्य और डाउनस्ट्रीम उत्पाद में वृद्धि होगी। तथापि, जब मौखिक सुनवाई के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौजूदा जांच के संदर्भ में अपने दावे को सिद्ध करने की सलाह दी गई तब यह नोट किया गया कि इन विरोधी पक्षकारों ने कोई समर्थनकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ये पक्षकार यह सिद्ध नहीं कर पाए कि घरेलू उद्योग का यह दावा कि उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव नगण्य रहेगा, गलत है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क के लगाए जाने के परिणामस्वरूप दो केन्द्रों में स्थित होने वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। देश में निश्चय ही उत्पाद के अनेक उत्पादक मौजूद हैं। हितबद्ध पक्षकार सहमत हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्माण सुविधाएं स्थापित करने में किया जाने वाला निवेश न ही बहुत अधिक है और न ही इस संबंध में क्षमताएं स्थापित करने अथवा विकसित करने के लिए समय की

- आवश्यकता है। अत: ऐसा मामला नहीं है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के कारण दो केन्द्रों में केन्द्रित होने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी।
- ज. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं का संचालन अव्यवहार्य हो जाएगा और अंतिम उत्पादों, विशेषकर औषधि में मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ता विशेष रूप से नुकसान की स्थिति में होंगे। तथापि, यह नोट किया गया है कि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा और अत: यह सिद्ध नहीं हो सका कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं का संचालन अव्यवहार्य हो जाएगा।
- झ. रिकार्ड पर प्रस्तुत तथ्यों के मद्देनजर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क का लगाया जाना सार्वजनिक हित में होगा और इससे अंतिम प्रयोक्ताओं के हितों पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 51. विकासशील देश:

- क. विकासशील देशों से होने वाले आयात की प्रतिशतता की भी जांच की गई है। चीन पी आर, जिसकी हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में कुल आयात का 82% थी, को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की हिस्सेदारी अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से भारत में कुल आयात के क्रमश: 3% तथा 9% से कम है। अत: चीन पी आर को छोड़कर विकासशील देशों से होने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परन्तुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं होगा।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क से भारत द्वारा इन देशों को निर्यात किए जा रहे कुछ उत्पादों पर उक्त देश इसका प्रतिकार करेंगे। रक्षोपाय शुल्क लगाने के खिलाफ किसी भी देश द्वारा कभी भी बदले की कार्रवाई नहीं की गई है। भारत डब्ल्यू टी ओ का एक हस्ताक्षरकर्ता देश भी है और उसने डब्ल्यू टी ओ रक्षोपाय समझौते के अनुरूप अपने कानून अधिनियमित किए हुए हैं। स्वयं डब्ल्यू टी ओ अपने सदस्यों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया का पालन करके अपने उद्योग की रक्षा करे।
- 52. निष्कर्ष : उपर्युक्त जांच और किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि :-
  - क. वास्तविक आधार के साथ-साथ जांच की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद, सोडियम साइट्रेट के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में विशेष रूप से तेजी आई, जिससे गंभीर क्षति हुई या इसका खतरा बना रहा। आयात में यह तेजी कुल मांग की तुलना में भी काफी उल्लेखनीय है।
  - ख. घरेलू उद्योग यह दर्शाने में सफल रहा है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में तेजी के संबंध में बाजार में हुए घटनाक्रम, विशेषकर चीन पी आर के संदर्भ में (कुल आयात का 82%) अप्रत्याशित थे।
  - ग. जांच से पता चलता है कि सूचीबद्ध आर्थिक पैरामीटरों अर्थात् बाजार में हिस्सेदारी, बिक्री, क्षमता के उपयोग, उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में गंभीर क्षित हुई है। तथापि, लाभ प्रदायकता में आधार वर्ष से वर्ष 2013-14 तक में तेजी से गिरावट आई है। यद्यपि रोजगार बढ़ा है, परन्तु प्रित कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष से वर्ष 2013-14 तक गंभीर कमी आई जबिक माल-सूची में आधार वर्ष से वर्ष 2013-14 तक तेजी से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग, देश में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के बावजूद बिक्री में गिरावट के कारण बढ़ रही हानि और जमा हो रही माल-सूची के रूप में गंभीर क्षित को प्रदर्शित करने में सफल रहा है। यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि, देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी की तुलना में काफी कम है और घरेलू उद्योग की क्षमताओं का विशेष रूप से उपयोग नहीं हो सका। इसके कारण घरेलू उद्योग की स्थित को विशेषकर समग्र हानि पहुंची है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी, वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में कम हुई है, जिसके साथ-साथ, उक्त अविध में आयात की बाजार में हिस्सेदारी में तदनुरूपी

- वृद्धि हुई है। यह सिद्ध करता है कि जांच की अवधि के दौरान आयात में बढ़ोतरी और घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच औपचारिक संबंध है।
- घ. यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने 4 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क के रूप में संरक्षण मांगा है, जिसके लिए उन्होंने समायोजन योजना प्रस्तुत की है। समायोजन योजना भी व्यवहार्य पाई गई है। घरेलू उद्योग का यह दावा कि वे अपनी क्षमता का विस्तार कर चुके हैं और वे अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ, घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, स्वीकार्य प्रतीत होता है।
- ङ. घरेलू उद्योग यह भी दर्शाने में सफल रहा है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला रक्षोपाय शुल्क का संभावित प्रभाव मामूली है। यह भी पाया गया कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के दौरान इस पहलू का खण्डन या विरोध नहीं किया।

## 53 **संस्तृति**:

क. अत:, भारत में सोडियम साइट्रेट के बढ़ते आयात से सोडियम साइट्रेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षित हुई है और उन्हें गंभीर क्षित होने का खतरा रहा है और यह सार्वजिनक हित में होगा कि 3 (तीन) वर्ष की अविध के लिए सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 के अनुसार, भारत में सोडियम साइट्रेट के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए। लगाई गई पूंजी पर उचित मुनाफे की अनुमित देने के पश्चात्, घरेलू उत्पादक द्वारा सोडियम साइट्रेट की औसत बिक्री लागत पर गौर करते हुए, एतद्वारा रक्षोपाय शुल्क, जिसे घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम अपेक्षित समझा गया है, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्ष 29181520 (एच एस कोड केवल निर्देशात्मक है और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में मान्य होगा) के अंतर्गत आने वाले सोडियम साइट्रेट के आयात पर लगाए जाने की संस्तृति की जाती है, जो इस प्रकार हे:

अवधि	रक्षोपाय शुल्क की दर
प्रथम वर्ष	55प्रतिशत यथामूल की दर
दुतीय वर्ष	50 प्रतिशत यथामूल की दर
तृतीय वर्ष	40 प्रतिशत यथामूल की दर

ख. चूंकि चीन पी आर को छोड़कर विकासशील देशों से होने वाले आयात अलग-अलग 3% तथा सामूहिक रूप से 9% से अधिक नहीं हैं, इसलिए चीन पी आर को छोड़कर विकासशील देशों से होने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परन्तुक के अनुसार, रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं होगा।

[ फा. सं. डी-22011/20/2013]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARD

(Central Board of Excise and Customs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2014

Subject:-Safeguard investigation concerning imports of Sodium Citrate - Final Findings.

**G. S. R. 663** (E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

#### I. Procedure

- 1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as Safeguard Rules) by M/s. Posy Pharmachem Private Limited, No. 187/1A, Karoli, Nr. Khatraj Ckokdi, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat through their consultant M/s. TPM Solicitors & Consultants for imposition of Safeguard Duty on imports of 'Sodium Citrate' into India, to protect the domestic producers of Sodium Citrate against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of "Sodium Citrate" (hereinafter referred to as Product Under Consideration, i.e., PUC) into India.
- 2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visit to the plant of the domestic producer to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of the said Rule 5 were met and the application was updated on dated 24/2/2014, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Sodium Citrate into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 4<sup>th</sup> March, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary vide G.S.R.140 (E) on the same day i.e. 4th March, 2014.
- **3.** A copy of the Notice of Initiation dated 4<sup>th</sup> March,2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997:

#### (IV) Domestic Industry

a. **POSY PHARMACHEM PRIVATE LIMITED,** No. 187 / 1 A,Karoli,Nr. Khatraj chokdi, Ta. Kalol, Dist: Gandhinagar, Gujarat - 382 721.

#### (V) Other Indian Producers

- a. Sunil Chemicals, 311, Janki Centre, Off. Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai 400 053
- b. Ishita Drugs And Industries Drugs And Industries Ltd. Drugs And Industries Ltd., 11, Valmik Complex, C.G.Road, Ahmedabad. 380006, Gujarat.
- c. G.Amphray Laboratories, Sambava Chembers, 4<sup>th</sup> Floor, Sir P.M.Road, Navnidh Pharma Lab. 37, Bindal East, Sakinaka, Mumbai. Maharastra.
- d. Navnidh Pharma Lab, 37, Bindal East, Sakinaka, Mumbai.
- e. Wang Pharmaceuticals & Chemicals, A 77, Vishal Enclave, New Delhi 110027.
- f. V M Chemicals., C / 1,243, Gidc, II Phase, Ambavadi, Wadhavan, Surendranagar, Gujarat. 363035

#### (VI) Importers

- a. Crystal Crop Protection Pvt. Ltd., GI-17, GT Karnal Road, Industrial Area, Azadpur, Delhi 110033
- b. Desmo Exports, 125-Arenja Arcade, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai 400703, Maharashtra.
- c. New Drug & Chemical Co., 4, Jay Mahal Estate, 2nd Floor, 20/48, Lohar Chawl, Maharashtra.
- d. Colorcon Asia Private Limited, 38-AB, Govt Industrail Estate, Charkop, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra.
- e. ACID-India, Mulratra 2nd Floor, 334-Narshi Natha Street, Mumbai 400703, Maharashtra.
- f. Pradip kumar Pharma Pvt. Ltd., Address: 701, Arun Chambers, 80, Tardeo Road, Mumbai 400034, Maharashtra.
- g. Amijal Chemicals, 5/4, Mungekar Industrial Estate, Off Aarey Road, Goregaon (E), Mumbai, Maharashtra.
- h. Adani Pharmachem Pvt. Ltd., Plot No. 2729 to 2731, Road-I-1, Lodhika, G.I.D.C, Village, Metoda, Tal. Lodhika, Rajkot-360021, Gujarat.
- i. Sujata Chemicals, 802, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat.
- j. Prakash Chemicals Pvt. Ltd., Induchacha House, Opposite Cchani Octroi naka, Vadodara, Gujarat.
- k. RM Chemicals, Guru Kripa Complex, 131, Anna Pilai Street, Sowcarpet, Chennai 600001, Tamil Nadu.
- 1. Pfizer Limited, Pfizer Center, Patel Estate, SV Road, Jogeshwari (W), Mumbai-400102, Maharashtra.
- m. FDC Limited, B-8, MIDC Area, Waluj-431136, Aurangabad, Maharashtra.
- n. Wallance Pharmaceutical Ltd., 3rd Floor, Dempo Trade Centre Building, Pattp Plaza, EDC Complex, Panaji-403001, Goa.
- o. Kaira District Co-op Milk Producers Union Ltd., Station Road, Anand-388001, Gujarat.

- p. Schreiber Dynamix Daries Ltd., E-94, MIDC, Bhagwan Road, Baramati, Dist. Pune 413133, Maharashtra.
- q. Vasa Pharmachem Pvt. Ltd., D1 & D2, 2nd Floor, "Nikumbh", NR. Reliance House, CG Road, Ahmadabad 380006, Gujarat.

#### (IV) EXPORTERS

- a. Qingdao Sonef Chemical Company Limited, Rm 1504, Jinhua Building 1, No. 100, Nanjing Rd, Shandong, Qingdao, China.
- b. Weifang Vot International Business Co. Ltd. No. D2704, Dong Feng Street, Shandong 261000 Weifang, China.
- c. Hai Hui Group Cp., Ltd. Industrial Park of Ju County, Shandong 276500 Rizhao, China.
- d. Foodchem International Corporation Building 9, 2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi- Tech Park, Shanghai 201203, China.
- e. Yixing Zhenfen Medical Chemical Co. Ltd. Zhoutie Town, Yixing City, Jiangsu Province 214262, China.
- f. Hainan Huarong Chemical Co. Ltd. 21A, Beijing Building, No. 56, Guomao Road, Hainan Haikou 570125, China.
- g. Lianyungang Dongtai Food Ingredients Co. Ltd. Room 201, Unit 1, No. A3, Building,
   Yingzhou Road, Xinpu District, Jiangsu 222000 Lian Yungang, China.
- h. Lianyugang Shuren kechuang Food Addivtive Co. Ltd. The East of Linhong Road, Dapu Chemical Industry Zone, Lianuungang TEDA, Jiangsu 222000, China
- i. Honson Pharmatech Group Ltd, 275 Don park Road, Markham, Ontario, Canada.
- j. Gadot Biochemical Industries LTC, P.O.Box 10636, Haifa Bay, 26118 Israel.
- k. Showa Kako Corporation, Nissho Bldg.6F,2-2, Dojima 1-chome,Kita-ku, Japan.
- 1. Chemical Supply Co LLC, 10405 NW 37th Terrace, Miami, Florida,
- m. Archer Daniels Midland Company, 4666 Faries Parkway Decatur, IL 62526, United States of America, USA.
- n. Cargill INC. 15407 Mcginty Rd W Wayzata, Mn 55391-2365 (800) 227-445
- o. Tate & Lyle PLC, 1 Kingsway London WC2B 6AT, United Kingdom.

#### (V) Exporting Nations:

- a. The Embassy of People's Republic of China, 50-D, Shantipath, Chanakya Puri, New Delhi 110021.
- b. The Embassy of United States, Shanti Path, Chanakya Puri, New Delhi -110021.
- c. The Embassy of Spain, 12, Prithviraj Road, Khan Market, New Delhi -110001.
- **4.** Questionnaires were sent to the known exporters, known importers/users in India and other interested parties as per the information available, with request to make their views known in writing within 30 days of the Notice of Initiation.
- 5. Requests to consider them as interested parties were received from the following parties:
  - a. Trade & Economic Section, Delegation of the European Union of India, 65, Golf links, New Delhi-110003. E-mail- chaitanya.kaushal@eeas.europa.eu
  - b. Minister Counsellor (Economic Affairs) High Commission of Malaysia, 50-M, satya Marg, Chanakyyapuri, New Delhi. E-mail- <a href="mailto:brecta.robert@miti.gov.my">brecta.robert@miti.gov.my</a>
- **6.** All requests were accepted.
- **7.** Following Interested Parties have filed the Questionnaire response:
- a. Domestic Industry: POSY PHARMACHEM PRIVATE LIMITED, No. 187 / 1 A,Karoli,Nr. Khatraj chokdi, Ta. Kalol, Dist: Gandhinagar, Gujarat 382 721.
- b. Importer: (i) M/S Adani Pharmachem Private Limited, Tal. Lodhika, Distt. Rajkot-360021
- c. M/s FDC Limited, 142-148, S.V. Road, Jogeshwari(W), Mumbai. C) M/s Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Ltd, Anand-388001, Gujarat.
  - **8.** Submissions were also received from the following Interested Parties in response to the Notice of Initiation:
    - a. Desmo Exports Ltd. vide letter dated 21/3/2014
    - b. Ishita Drugs And Industries Ltd Pharmaceuticals. vide letter dated 17/3/2014
    - c. Prakash Chemicals Agencies Pvt. Ltd. vide letter dated 09/4/2014
    - d. New Drug & Chemical Co. vide letter dated 27/3/2014
    - e. Wang Pharmaceuticals & Chemicals. vide letter dated 03/4/2014

- **9.** Ministry of External Affairs, Eurasia Division vide F No. WI(AD)123/04/2012 dated 19<sup>th</sup> June, 2014 forwarded a letter enclosing therewith a note verbal no. 923/n dated 5<sup>th</sup> June, 2014 from Mr. Viktor Evtukhov, Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation wherein it is said that during the period of investigation from 2010-2013, the import of goods falling under sub-heading 29181520 of the Customs Tariff Act 1975 and importing from the Russian Federation to India did not exceed three per cent, and therefore, in accordance with the Safeguard Provisions under the Customs Tariff Act, 1975 (Section 8B) and the Article 9 of the WTO Safeguards Agreement the Russian Federation should be excluded from the list of countries under investigation.
- M/s Sunil Chemicals, 311, Janki Centre, Off. Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai 400 053 vide their letter dated 11<sup>th</sup> November,2013 gave their support to the Domestic Industry in filing an application for safeguard measures against increased imports of Sodium Citrate into India. They also co-operated in the investigation by providing data regarding production, sales, and inventory of the PUC; which was considered and taken on record for overall injury analysis.
  - 11. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential information received or acquired has been kept in the public file.

#### **Views of the Interested Parties (Post-Notice of Initiation):**

**12.** Only a few Interested Parties submitted their comments in response to the Notice of Initiation issued in this case, which is as below:

#### A. Desmo Exports Ltd.

a. No anti dumping duty on sodium citrate should be imposed.

#### B. Ishita Drugs And Industries Ltd Pharmaceuticals.

- a. Wrong interpretation of the raw data on imports, domestic production and sales and any consequent action detrimental to the national interest, especially SSI manufacturers.
- b. Crude PUC imported is further processed and purified form is sold in domestic and export markets and any duty would make the export uncompetitive and lead to loss in foreign currency earnings.
- c. Total demand is much higher than provided in the Notice of Initiation as significant percentage of sales of other Indian manufacturers is after processing the imported sodium citrate. Also, the sales of DI are much higher than in Notice of Initiation and so a detailed investigation is necessary.
- d. Any duty would lead to duopolistic situation and lead to increase in PUC prices and other finished products like butter, cheese, life saving ORS, dialysis reagents, etc.

#### C. Prakash Chemicals Agencies Pvt. Ltd.

- a. The petitioners cannot apply for both anti dumping and safeguard duties at the same time which they have, as objectives of the both are different.
- b. Petition does not give actual production of other four domestic producers which if taken in to account make the claim of petitioners of 90% of production unacceptable.
- c. The supporter producer has no production since 2010-11 till date whereas the application attributes 44% share to it. Thus, the Notice of Initiation is not supported by the facts.
- d. None of the exporters mentioned in the petition are actual exporters and even if they export, quantities are too insignificant.
- e. The petitioners are admittedly exporters of PUC, thus, no serious injury due to imports.
- f. Petitioners do not mention total demand. The estimated demand of 14000 MT cannot be met by production claim of 4000MT by the petitioners and any duty would create monopoly in favour of petitioners.
- g. No significant value addition in PUC manufacturing vis a vis value of raw materials and hence, safeguard duty on such product makes no economic sense.
- h. Duty would make the operation of downstream users unviable and cause significant disadvantage to the consumers due to price increase of end products especially, Pharma.

#### D. New Drug & Chemical Co.

- a. Safeguard duty on PUC would make Chinese manufactures increase supply of citric acid which is the raw material of PUC used by the Indian manufactures.
- b. Petitioners produce only pharma grade PUC catering only to pharma & food industries and not to other chemical industries like agrochemicals, electroplating etc.
- c. Safeguard duty on PUC will make other than pharma & food industries suffer as domestic producers other than petitioners manufacturing those items have pending orders and cannot cater to the demand.

#### E. Wang Pharmaceuticals & Chemicals.

a. Due to cheap imports from China, sodium citrate industry is in bad shape. USA and Europe have already imposed huge ADD (anti dumping duty) on products from China and we expect at least 35% ADD for at least 3 years to safeguard our industry.

#### **Public Hearing:**

- **13.** A notice for holding a Public Hearing was sent on 20th June, 2014 to all the Interested Parties which was scheduled for 23-06-2014. However, due to some unavoidable circumstances, the Public Hearing was rescheduled and was finally held on 07-07-2014. Following parties attended the hearing:
  - a. Posy Pharmachem Pvt ltd (Domestic Industry)
  - b. Sunil Chemicals (Supporter)
  - c. Wang Pharmaceuticals (other domestic producer)
  - d. Ishita Drugs & Industries Limited (other domestic producer)
  - e. Prakash Chemicals Agencies Pvt. Ltd (importer)
  - f. Minister Counsellor (Economic Affairs), High Commission of Malaysia.
- 14. All Interested Parties who participate in the public hearing are required to file a written submission of the views presented orally in terms of Sub Rule (6) of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Thereafter, copy of written submissions filed by an Interested Party is made available to all other Interested Parties. Interested Parties are also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties, including that of the Domestic Industry. In the instant Public Hearing, all interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally by 17<sup>th</sup> July 2014. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties, including the Domestic Industry. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties, including Domestic Industry, by 25<sup>th</sup> July, 2014. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination. However, one Interested Party, namely, Minister Counsellor (Economic Affairs), High Commission of Malaysia who participated in the Public Hearing, neither made any oral submission nor filed any written submission nor any rejoinder to the written submission by the Domestic Industry.

#### **Post-Public Hearing written submissions:**

- **15.** Written Submission by M/s Posy Pharmachem Private Limited vide letter dated 17th July 2014 as follows:
- a. The product under consideration in the present petition is "Sodium Citrate". Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and trisodium citrate. Goods produced by them are like article to the goods imported in India. The product under consideration can also be transacted by following alternate names
  - i. Sodium Citrate
  - ii. Tri sodium Citrate
  - iii. Tri sodium citrate dihydrate
  - iv. Sodium citrate dihydrate
  - v. Tribasic sodium citrate
  - vi. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate
  - vii. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate
  - viii. Sodium Citrate Monobasic Bioxtra
- b. Sodium Citrate is mainly used as an expectorant and a urine alkanizer. It is also used as a pharmaceutical aid and as a food additive in dairy Industries which cater in cheese manufacturing and beverages. It is also a water treatment chemical and as a laboratory reagent.
  - c. The goods produced by the petitioners are like article to the goods imported in India. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods in terms of essential product properties.

- d. Present application has been filed by M/s Posy Pharmachem Private Limited. The application was supported by M/s Sunil Chemicals.
- e. M/s Ishita Drugs And Industries Ltd, M/s Navnidh Pharma Lab, M/s G.Amphray Laboratories, M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals and M/s V M Chemicals are the companies who have been selling the product under consideration in the market. As per the market intelligence of the petitioner, some marginal producers like M/s Vasa Pharma, M/s Adani Pharma and M/s Sujata Chemicals who were earlier producing product concerned have shifted to imports and started trading the imported product due to continued dumping.
- f. Petitioner has considered their known sales volumes and presumed the same as production. The production of the applicant constitutes a major proportion of domestic production of sodium citrate and hence, the petitioner constitutes Domestic Industry.
- g. M/s Wang Pharmaceuticals, and M/s Ishita Drugs and Industries Ltd. have participated in the investigation as domestic producers. It is requested that the Director General may seek their production details and accordingly determine the standing of the petitioner.
- h. M/s Wang Pharmaceuticals has extended support to the plea for imposition of safeguard duty during the oral hearing. However, surprisingly, M/s Ishita Drugs and Industries Ltd., who has also claimed to be a domestic producer of the subject goods, has opposed imposition of safeguard duty. The reason for such strong opposition seems to be that the company is importing the product under consideration and selling the same in the domestic and international market.
- i. The requirement under the law is that imports should have shown sudden and significant surge. WTO in the matter of *Argentina Footwear (EC)* has held that increased imports must be sudden and recent:
  - "[T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfil this requirement for applying a safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."
- j. The petitioner submits that the imports of Sodium Citrate have shown sharp increase in absolute terms as well as in relative terms. The increase in imports is sudden and significant, causing market disruption and threat of market disruption. Thus imports of product under consideration has "increased within the meaning of the rules"
- k. Imports of Sodium Citrate have shown sharp increase in absolute terms as well the imports of the product under consideration from 2010-11 up-to March 2014. It would be seen that the actual figures of 2013-14 have shown further increase in imports.

Parameter/Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Imports	2,621	2,877	3,721	5,300

- Imports of product under consideration in India have increased rapidly in relation to production of the domestic
  industry and the increase is higher than the increase observed at the time of Initiation of the safeguard
  investigation.
- m. The imports of product under consideration have increased rapidly in relation to Indian consumption of product under consideration. Imports have increased to such an extent that the imports in relation to consumption constitutes 71% of Indian consumption.

Parameter/Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Imports in relation to				
consumption	57%	55%	57%	71%

#### Corrected by DI in Rejoinder 69% in place of 71% in 2013-14

- n. Reasons for increase in imports:
  - i. Majority of imports into the domestic market are from China which has excessive capacities and are therefore exporting sodium citrate. The US has conducted an anti-dumping investigation against imports of Citric Acid and certain Citrate Salts, which includes Sodium Citrate as well, wherein the US authorities have held that China has significant capacities.

Year	2006	2007	2008	2009	2010
Apparent Consumption					
Capacity	1443	1932	2047	2193	2195
Production	1247	1719	1807	1779	1834
GAP (production –consumption	924	1259	1332	1190	1227

<sup>\*</sup> in '000 pound; Source: USA Findings

ii. There exists significant demand supply gap which is further forcing the exporters from China PR to export the goods to India.

#### o. Serious Injury and Threat of Serious Injury to the Domestic Industry

- Demand for the product under consideration has been determined by the petitioner, as the imports of
  product into India, domestic sales of the domestic industry and domestic sales of other domestic
  producer. This also includes captive consumption, which is not present in this case. The overall
  demand for the product under consideration over the injury period has increased.
- ii. Production of the domestic industry has declined after increasing till 2012-13.

Parameter/Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Production	1,184	1,211	1,531	1,521

 Capacity utilization of the domestic industry has also declined in the recent period after increasing till 2012-13. Industry is facing significant un-utilized capacities due to low priced imports and surge in imports in last two years despite sufficient capacities in India. Domestic Industry is utilizing only 45% of its capacities.

Parameter/Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Capacity Utilisation	44	45	56	46

- ii. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry.
- iii. Sales of the domestic industry have also declined after increasing till 2012-13.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Domestic Sales (In MT)	505	632	1036	999

- iv. Landed price of imports is significantly lower than the (a) selling price of the domestic industry and (b) cost of production of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in price suppression.
- v. The domestic industry is suffering financial losses. Further, the losses suffered by the domestic industry kept increasing throughout the injury period

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Profit/Loss (In Rs/MT) (indexed)	-100.00	-198.76	-184.14	-593.15

vi. Return on investment was also negative and deteriorated over the injury period.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ROI (%)(Indexed)	-100	-155	-146	-549

p. In addition to the serious injury already inflicted on the domestic industry, increased imports of Sodium Citrate are threatening serious injury to the domestic industry. The price difference between domestic and imported product is quite significant. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Landed price (avg.)	Rs/MT	44.67	52.62	53.87	48.92
Landed price (avg.)	Indexed	100.00	117.80	120.67	109.51
	Rs/MT				
Domestic Selling Price (avg.)	Indexed	100.00	123.58	114.00	125.32

- q. Whereas the imports of the product under consideration are already causing serious injury, the same is likely to intensify in due course, should the safeguard duties not be imposed immediately.
- r. Domestic industry submits that, it can be concluded that
  - i. the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India;
  - ii. imports are significantly undercutting the domestic prices.
  - iii. whereas cost of production was increasing, the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to the increase in cost of production. Resultantly, imports were suppressing the domestic prices.
  - iv. as a result of significant surge in imports, the market share of the domestic industry has significantly declined:
  - v. imports have caused serious injury to the domestic industry in terms of decline in market share of the domestic industry, decline in production, capacity utilization, sales volumes, profits, significant losses and negative ROI.
- s. Other factors causing Injury
  - i. Demand of the product under consideration has increased. Thus, the injury to the domestic industry is not due to any decline in demand.
  - ii. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.
  - iii. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
  - iv. Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are therefore, not a factor of injury in this case.
  - v. The analysis of injury is in respect for domestic operations only. Therefore, possible deterioration in the export performance of the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

vi. Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. Petitioner has segregated data and provided in respect of product under consideration only.

#### t. Causal link

- i. There is a sudden and sharp spike in volume of imports into the domestic market in the recent period.
- ii. Volume of imports is very high and shows an increasing trend throughout the injury period.
- iii. The imports in relation to Indian production and demand have increased significantly.
- iv. Production, sales and capacity utilization have declined in the most recent past. The domestic industry is faced with significant unutilized capacities in view of significant imports into India.
- v. The imports are causing (i) price suppression (ii) financial losses (iii) negative returns on capital employed (iv) under-utilization of production capacities of Domestic Industry.
- vi. Imports have increased and are significant in relation to production and consumption in India. As a direct consequence, whereas the market share of imports has increased rapidly, that of the Indian industry has remained very low and declined.
- vii. Price suppression caused by the increased imports at low prices has led to severe decline in profitability.
- viii. The domestic industry has been facing negative return on capital employed, lower levels of productivity, underutilized capacities, and financial losses.

#### u. Public Interest

- i. The effect of safeguard measures on public interest is commonly studied from the perspective of three different parties the producers, the consumers and the general public. When considered in this context, imposition of safeguard duty in the present case shall be in public interest.
- ii. The imposition of safeguard duty on imports of product under consideration would be in the interests of domestic manufacturers. The measure would prevent further injury to the domestic industry from increased imports. Domestic industry is suffering significant injury and imposition of safeguard duty would prevent this injury to the domestic industry.
- iii. Imposition of safeguard duty would be in the interests of domestic consumers, as it is in the consumer's interest to have a competitive Indian domestic industry capable of supplying the product under consideration to the consumers and compete with foreign producers. This is possible only when the domestic industry is able to recover from the injury suffered due to the increased imports.
- iv. It is in the interests of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry. This will not be possible if injury to the domestic industry as a result of increased imports is allowed to continue.
- v. The consumption segment of Sodium Citrate is as follows:

Consumption Segment	Approx Consumption (MT)
CHEESE	As preservative
COUGH SYRUP	As Expectorant
SOFT DRINKS	As Salty & Tangy taste
JELLY	As Salty & Tangy taste
PHOTOGRAPHIC INDUSTRY	As Anti Coagulant
PHARMACEUTICAL INDUSTRY <b>B</b>	As Anti Coagulant
BEVERAGES	As Salty& Tangy taste

vi. The eventual impact on the cost of the end products is insignificant on the consumer segment. Accordingly, a detailed costing of impact on different user sector has been provided by the Domestic Industry. That Public interest has to be considered as the interests of domestic producers, domestic consumers and public at large. In this regard, considering almost negligible impact on the eventual

end product and considering that survival of the domestic industry is must, it must be concluded that the imposition of safeguard duty shall be in public interest.

## v. Adjustment Plan

- i. Petitioner at present has 3300 MT capacity. Petitioner plans to increase its capacity gradually from present levels to 6600 MT per annum.
- ii. Higher volume would result in higher requirements / sourcing of raw material. This would allow company to enter into quarterly contracts with raw material suppliers. Sourcing of higher volume of inputs would provide company bargaining power and this would result into reduction of cost of production gradually.
- iii. Higher capacity and production would be achieved by the company by Automation of present setup like conveyor belt, FSS (feel, seal, stitch) machine etc. This would result into better productivity by lower number of individual. This automation would provide cost saving in terms of labour cost, repair & maintenance cost, manufacturing expenses, depreciation per unit of production.
- iv. Company intends to use solar energy as additional source of power. This would mean reduction of cost of power.
- v. Increase in capacity and production, would not require any significant change in administration and sales manpower.

## 16. Written Submission by M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals vide letter dated 17<sup>th</sup> July 2014 as follows:

- a. The increased volume of imports is causing serious injury to the Domestic Industry & eventually may result in closure of the domestic industry.
- b. Even if the demand for this product increases in the country by two or three fold in next five years, as claimed by representatives opposing the safeguard duty, it will not be difficult for the Domestic Industry to fulfill the increased demand
- c. Since <u>The Drug controller of India</u>, has imposed restriction on import of Sodium Citrate without registration process, lot of imports are coming in this country by labeling / describing the same material as "<u>Not for Pharma / Medicinal use</u>". In fact, the product is such that it cannot be processed further. The importers are claiming so merely to evade the regulation and prohibition.
- d. As against the submissions of M/s Ishita Drugs and Industries Ltd contention, it is submitted that it is very strange that a company who claims itself as a producer of the product for past several years is opposing safeguard duty. There can be no rationality why such an old producer will oppose safeguard duty.
- e. There is no truth in their statement that larger public interest demands that the product need not be produced in the country and can be imported from China.
- f. There is no truth in the claims of monopoly or the argument that imposition of safeguard duty would significantly increase the prices of the end products. All statements of such parties in the name of larger country's interests are bogus and the real objective of these parties is to import the product because of low price and earn higher profits
- g. USA has earlier imposed anti dumping duties ranging from 90% to 150% on Chinese imports during 2009-10. If a powerful developed economy such as USA considers imposition of anti dumping duties necessary to protect their industry, there is no reason why safeguard duties should not be imposed by India.

## 17. Written Submission by M/s Sunil Chemicals vide letter dated 17<sup>th</sup> July 2014 as follows:

- a. We are in full agreement with Posy Pharmachem that the product is being imported in increased volumes and the same is causing very serious injury to the Indian industry.
- b. The country has sufficient demand for the product and there is no need for any imports for the product in the country
- c. Some of the imports are being made by describing the product as "not for Pharma/Medicine use". It is claimed that these imports are processed further and the product is sold in the Indian market for pharma or food

- application. The fact, however, is that there is no processing of the imported material and the product is merely repacked to claim pharma or food grade product. In fact, the product is such that it cannot be processed further. The importers are claiming so merely to evade the regulation and prohibition.
- d. It is very strange that a company who claims itself as a producer of the product for past several years is opposing safeguard duty. There can be no rationality why such an old producer will oppose safeguard duty. As rightly pointed out by the counsel of Posy Pharmachem at the time of hearing, this is being done for different reasons (a) to export the product to US market where Chinese producers are now attracting anti dumping duties; (b) to take advantage of low priced imports in the country and earn better profits in trading as compared to profits that are available in manufacturing.
- e. There is no truth in the claims of monopoly or the argument that imposition of safeguard duty would significantly increase the prices of the end products. All statements of such parties in the name of larger country's interests are bogus and the real objective of these parties is to import the product because of low price and earn higher profits by trading instead of producing the product in the country
- f. It is highly contradictory on the part of such parties to claim that they carry out significant processing on the imported Sodium Citrate to make it Pharma grade and even when we are producing the product by undertaking full production activity, they say there is no significant activity being carried out by us on the produced sodium citrate. This clearly shows significant contradictory approach by such companies whose sole objective is to take advantage of low priced imports and earn higher profits by trading in the imported product.

## 18. Written Submission by M/s Ishita Drugs And Industries Ltd vide letter dated 17<sup>th</sup> July 2014 as follows:

- a. Petitioner has wrongly clubbed tri-sodium citrate, mono-sodium citrate and di-sodium hydrogen citrate as all these products are different with different chemical properties and different chapter heading and molecular formula. All these 3 products are different, distinct chemical entities with different chemical properties, with different chapter heading nos. and different molecular formulae.
- b. 100% of imported products are not for medicinal use. The imported product has to be further processed chemically to make it suitable for pharma use and therefore are not directly competitive article.
- c. Claim that petitioner and Sunil Chemical constitutes 90% of the Indian production is not credible. It is in contradiction with the information in the initiation notification on Indian production.
- d. Increase in imports is almost equal to increase in production of the DI. Increase in imports in relative terms is also not significant.
- e. No severe injury. Production of DI in relation to total production has lagged behind the total growth in production. Petitioner could not increase its production.
- f. Sales and market share given by the petitioner is misleading as it ignores the export sales of Indian manufacturers of Sodium Citrate which should be included in calculating demand. M/s Ishita Drugs and Industries have recast (the table as below on the basis of the data taken from Website of Deptt. of Commerce) the table given on page 3 of the Notice of Initiation as that Sales of DI has increased by 140% and market share has increased by 50%.

Year	Import	Domestic sales of DI	Sales of other Indian producer	Exports of all Indian producers	Total Demand (Domestic & Export) @	Market Share (%)	
						DI	Import
2010-11	2621	505	1454	704	2663	10%	50%
2011-12	2877	632	1769	690	3091	11%	48%
2012-13	3721	1036	1787	1067	3890	14%	49%
2013-14	4791	1214	1236	1232	3682	15%	57%

Data taken from Website of Deptt. of Commerce.

g. Safeguard duties cannot be imposed to wipe away losses of DI papering over inherent inefficiencies in the system.

- h. Detailed data on month wise/quarter wise import price has not been provided to substantiate claims of undercutting. In a situation of where exchange rate has been fluctuating and volatile, average prices is not acceptable. Bills of imported goods, import invoices for different months should be called for.
- i. Idle capacity cannot be directly attributed to Sodium Citrate. Sodium Citrate is a very old product and involves a single step simple manufacturing process. It does not require any specialized equipment. Whatever equipment is used for manufacture of Sodium Citrate, can be used for manufacture of other chemical products bulk drugs as well. No fresh investment has been made to enhance the capacity.
- j. Costing and selling of sodium citrate is dependent on citric acid which is imported into India. Indian manufacturers are affected by the import price of citric acid and fluctuations thereof.
- k. Sodium citrate has been a low margin product. Since liberalisation, sodium citrate manufacturers have always enjoyed very low margins, irrespective of level of imports. This has more to do with the fact that the manufacturing process of Sodium Citrate is very simple and it requires no special equipment investment. The low margins are not a result of increase in imports of Sodium Citrate.
- 1. It is not explained whether claimed undercutting is being caused by foreign company selling sodium citrate or by Indian importers.
- m. Companies exporting sodium citrate are the companies also producing citric acid (raw material) and therefore their costing is naturally lower.
- n. One of the major uses of Sodium Citrate IP *I BP I VSP* (Pharma grade) as manufactured by the petitioner is in manufacture of life saving ORS sachets. Prices will shoot up, and since sodium citrate is most commonly used in life saving ORS sachets, butter, cheese, etc., prices of these commodities of common use will also increase.
- o. Safeguard duty will also increase prices of everyday food items, fuelling further the problem of food inflation.
- p. Safeguard duty will also lead to retaliation by countries, on some products exported by India to these countries, thereby causing loss of foreign exchange and some industry.
- q. No concrete adjustment plan has been given. Mere plan of expanding capacity is not sufficient as all manufacturers depend on citric acid. Proposed capacity would only be about a small percentage of the capacity available with the foreign producers.
- r. The total demand for Sodium Citrate in India (including its domestic demand and its exports) have always been met through imports in a major way and this is not a sudden or recent phenomenon.
- s. Imposition of ADD in USA has no relevance. Imposition of ADD is by way of extension of ADD on citric acid, of which there is huge capacity in USA. USA imposed duties to protect the manufacturers of citric acid and sodium citrate. Whereas India has no capacity for citric acid and sodium manufacturer will always be dependent on citric acid.

## 19. Written Submission by M/s Prakash Chemicals Agencies Pvt. Ltd vide letter dated 17<sup>th</sup> July 2014 as follows:

- a. Their business in terms of sales volume or quantity has increased during the period of Investigation POI (2011-2014).
- b. Sodium citrate Market is growing with more than 20%-25 % year on year basis and within one or two years demand will be more than 15000 MT which cannot be satisfied by petitioner and its supporters.
- c. There is no meaning to protect the interest of two or three manufacturers who has only purpose to earn higher profit by safeguard duty and which will create serious damage to more than 1000 end consumers of sodium citrate due to higher cost of Sodium Citrate
- d. In respect of the same product the same manufacturers cannot seek to impose both safeguard duty as well as anti-dumping duty.
- e. If more than 25 small and big manufacturers can survive and they do not have any problem then only two or three manufacturers are suffering may be due to lack of skill and capability to remain in competitive market.
- f. There are few more applications of sodium citrate which are growing very fast with more than 25 % consumption growth rate ignored by the petitioner.
- g. There is no specific information on total Indian Consumption, production data of other manufacturers and multipurpose production plant and equipment which are being shown as installed capacity of sodium citrate.
- h. Import as well as domestic production is increasing with growing demand of sodium citrate more than 20 % per year.
- i. Imported Product market share (16%) is stagnant whn compared to domestic Industry market share growth rate (52%) during POI.

- j. There are few more industries which are growing very fast in India with more than 25 % consumption Growth rate and petitioners have ignored this and also of new applications in different industries such as Soap & Detergent, Fertilizers, Ceramics industry and Animal feed Industry.
- k. There is no evidence of decrease in domestic production so there is no injury in terms of sales & production. Growth rate in Capacity utilization is 25 % during POI, growth rate in sales is 116 % during POI, Growth rate of Market share of Domestic industry is 52 % during POI, Growth rate of Market share of Imports is 16 %. Only profit data shows some negative impact on petitioner which is not credential because petitioner is manufacturer of more than ten products.
- 1. Petitioner did not clarify about their plant utilization for multi products or sodium citrate, it is very difficult to justify that their entire plant capacity and employees are employed only for manufacturing of sodium citrate.
- m. Website of the petitioner shows the petitioner to be a manufacturer / seller of various products. Their installed plant capacity is utilized by so many products, which is misguiding the authority to understand the demand and supply data.
- n. Other producers understand that buying Citric Acid monohydrate and giving the process by using valuable resources like people and machinery with even small capital investment is not wise business when the end product "Sodium Citrate" is available at same price.
- o. Price of Sodium citrate raw material "Citric Acid Monohydrate" and end product "Sodium Citrate" is same. There is no economic logic to import raw material at same price of finish product and then use our domestic valuable resources like people, Machinery, Energy and Skills to produce sodium citrate.
- p. Imposition of safeguard duty will lead to increase in the demand of citric acid monohydrate which in turn will lead to increase in the price of Citric Acid Monohydrate which will adversely impact the domestic consumer of citric acid monohydrate.
- q. There does not exist sufficient capacity with the domestic industry to cater the whole demand.
- r. Due to competitive price of imported sodium citrate, many new industries have started using sodium citrate and have become competitive in world market today. Imposition of safeguard duty will result into rendering the operation of a much larger community of downstream users unviable.
- s. If Government want to support domestic industry then Safeguard duty must be with reference to price of Citric Acid Monohydrate.
- t. Safeguard duty must be 10 % basis of chemistry and production norms, to convert citric acid to sodium citrate there is only 3-4 % additional cost compare to price of Citric Acid monohydrate.
- u. Sodium citrate manufacturers must be not allowed to charge more than 10 % price compare to citric acid monohydrate to control the inflation and injustice to Domestic consumers of sodium citrate.

## 20. Rejoinder Submissions by the Domestic Industry vide letter dated 21<sup>st</sup> July 2014 with regard to the issues raised by M/s Ishita Drugs and Industries Ltd. as follows:

- a. Di-sodium hydrogen citrate has not been included as product under consideration. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and trisodium citrate. Mono, Di and Tri sodium citrate is merely a form of the product under consideration having same Physical and chemical properties and same customs classifications. The production technology and process used for producing these forms are same. The consumers also use them interchangeably which shows they are one and the same and directly competitive and similar products.
- b. It is submitted that goods produced by the petitioner are for all type of industries like pharma / food / pesticide / ceramic etc. In any case, the fact is that there is no processing of the imported material and the product is merely repacked to claim pharma or food grade product. In fact, the imported product is such that it cannot be processed further.
- c. The fact is that a number of companies who have been selling the product under consideration are actually importing the product and selling the same. Yet, the petitioner, as a conservative approach considered their sales as their production.
- d. Imports have increased significantly in absolute terms. Imports have increased by more than 100%, whereas the production has increased only by 13% over the injury period. This also shows misleading statements by these interested parties with an intention to impede the investigation.

- e. As against the contention that total Indian production has not increased significantly in comparison to the production of the domestic industry by this interested party, it is submitted that the fact is that other Indian producers have gradually turned to trading. Behaviour of M/s Ishita Drugs And Industries Ltd. also establishes the same.
- f. It would be seen that whereas demand for the product under consideration was positive and growing, domestic sales of the domestic industry increased till 2012-13 and declined in 2013-14. The domestic industry is faced with significant piling up of inventories and has been constrained to increase exports in order to liquidate inventories.
- g. Sales of the domestic industry have declined after increasing till 2012-13. Market share of the domestic industry has declined whereas market share of the imports have increased. Market share figure for imports given in the written submission had typographical error. The corrected figure is as follows:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
DI Domestic Sales ( MT)	505	632	1036	999
Demand	4,580	5,278	6,544	7,705
Imports	2,621	2,877	3,721	5,300
Market share in demand	•			
Petitioner	11%	12%	16%	13%
Other producers+ Supporter	32%	34%	27%	18%
Imports	57%	55%	57%	69%

- h. In response to the argument that the Export sales are required to be analyzed and included in demand it is submitted that Interested party lack appreciation of safeguard laws. The relevant information required for safeguard investigation pertains to the domestic market. Export sales are irrelevant in determining market share in domestic market. Assessment of Demand and market share" pertains to the demand of the product concerned in the domestic market and the share of the imports and the petitioners of this demand in the domestic market. It is absurd to include export sales into demand and then calculate the market share. This is impermissible under law. The interested party is merely trying to mislead the Authority, who has consistently considered demand to be a sum of total imports, sale of DI and sale of all other producers together (including captive consumption, if any). Exports are considered separately. Therefore, it has no relevance.
- Domestic industry made dedicated efforts to improve sales and production, results of which can be seen in some improvement in volume parameters, which has however, declined in the recent period despite such efforts been made.
- j. No inherent inefficiencies have been substantiated by the interested parties. Major issue raised by petitioner at the time of oral hearing is why M/s Ishita Drugs And Industries Ltd. has stopped manufacturing the product and has turned to import of the product from China despite having production capacity.
- k. The consistent practice as per law has been followed. Contrary to the argument of interested parties, in fact, a month wise or quarter wise analysis would be misleading because of significant fluctuation in exchange rate. The significant fluctuation in exchange rate may in fact show highly distorted position.
- The petitioner has dedicated plant for the product under consideration, which was also verified during on-site
  verification. Since capacity of the petitioner for the product under consideration is dedicated, the claim of idle
  capacity is directly attributed to increased imports.
- m. The interested parties stated at the time of hearing that production of the product under consideration does not involve significant investment. Nor setting up or enhancement of capacities is a long drawn process in the product under consideration. Such being the case, in any case, fresh investments by the domestic industry is not a critical parameter.
- n. However, contrary to the arguments of the Interested Party, in order to become more competitive and with a legitimate anticipation to grab a larger share in the rising demand of the PUC, the petitioner has already

purchased a new machine in the month of March 2014. The capacity has now increased to 5000MT. This is in pursuance to a viable adjustment plan given by the petitioner to the authority. It is stated that the same is under trial production and commercial production will commence once the situation of the petitioner improves.

o. Even if it is assumed that the product is a low margin product, the domestic industry is suffering severe losses, leave aside profits as can be seen from the table below:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(Indexed)	(100)	(199)	(184)	(593)
(Indexed)	(100)	(249)	(378)	(1,174)

The claim in fact, further substantiates the need to protect the domestic industry which is getting severely injured by the increase in low priced imports.

- p. M/s Ishita Drugs And Industries Ltd Drugs claimed that it imports the product in chemical grade, undertakes "significant value addition" and then sell the product in the Indian market for Pharma and food application. In other words, the consumers are still getting the imported product at higher prices, even higher than the import price. If so, there is no reason why imposition of safeguard duty would have adverse impact on the consumers.
- q. Barring China, imports have come only from Canada. Such being the case, when the safeguard duty will not even apply on other developing countries and when developed countries have not even exported the product, there is no basis for the argument that the proposed duty will lead to retaliation by other countries.
- r. The petitioner has given viable adjustment plan which focuses on expansion of capacity and lowering of costs. Expansion of capacity is in fact considered as a viable adjustment plant.
- s. Imposition of ADD on sodium citrate, at the least, shows that (a) the USA market is no longer available to the Chinese producers to freely dump their goods. Therefore, they are targeting Indian market, (b) one of the most powerful developed economies in the World considered it appropriate to protect its domestic industry by imposition of hefty 90-150% anti dumping duty.
- t. The unforeseen development/reason for increased imports as given in our application and submission is summarized as follows:
  - a. Excess capacity with the producers across the countries. Majority of imports into the domestic market are from China and very recently from Canada.

	Quantity (MT)				Share of import				
Country	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
Austria	-	2	5		0%	0%	0%	0%	
China PR	2,578.00	2,804.00	3,526.00	4,350.48	98%	97%	95%	82%	
Canada				699.60	0%	0%	0%	13%	
Germany	11.02	64.80	19.57	41.16	0%	2%	1%	1%	
Poland	0.05		0.17	0.95	0%	0%	0%	0%	
Spain	23.00	4.90	165.04	90.01	1%	0%	4%	2%	
Thailand	4.00				0%	0%	0%	0%	
Uk	4.40	0.38	0.30	0.50	0%	0%	0%	0%	
USA	0.27	1.06	2.74	117.59	0%	0%	0%	2%	
Unspecified			2.00		0%	0%	0%	0%	
Total	2,620.74	2,877.21	3,721.12	5,300.29	100%	100%	100%	100%	

It is submitted that the Chinese market has excessive capacities and are therefore exporting sodium citrate. US has conducted an antidumping investigation against imports Citric Acid and Certain Citrate Salts, which includes Sodium Citrate as well, wherein the authorities have held that China has significant capacities. The capacity estimated for Citric Acid and Certain Citrate Salts was projected at 2195911 MT for 2010, which in all likelihood would have further increased.

#### b. Significant demand supply gap

China has built capacities far excess than the domestic demand. There exits significant demand supply gap as can be seen from the table below, which is further forcing the exporters from China PR to export the goods to India.

Year	2006	2007	2008	2009	2010
Apparent Consumption					
Capacity	1443	1932	2047	2193	2195
Production	1247	1719	1807	1779	1834
GAP (production –consumption	924	1259	1332	1190	1227

\* in '000 pound; Source: USA Findings

#### c. Antidumping duties imposed on Sodium Citrate by various countries

Anti dumping duties on Sodium Citrate from China and Canada by USA US has imposed anti dumping duties on imports of Sodium Citrate originating in China and Canada in 2009. It is also pertinent to note that imposition of anti dumping duty by the US against China in 2009-10 has changed the course of the trade of this product across countries. Earlier, China was selling this product in the US market, which after 2009-10 became restricted/closed. Accordingly, the Chinese exporters started searching for new markets and India, with its growing demand for the said PUC, became a natural destination. This led to worsening of the condition of the domestic industry, which from a situation of

losses which has aggravated steeply in 2013-14.

Anti dumping duties on Sodium Citrate from China by EU

The EC has imposed antidumping duties on imports of Citric Acid, which includes sodium Citrate vide Council Regulation (EC) No 1193/2008 on 1<sup>st</sup> December 2008. The expiry review has also been initiated on 30<sup>th</sup> Nov., 2013 and is being undertaken currently.

profit in 2009-10, went on to pose loss for the first time in 2010-11; and continues to be in

The EC in its preliminary finding which was upheld in the final finding, held the product under consideration as follows:

The product concerned is citric acid (including sodium citrate), an acidulant and pH regulator for many applications such as beverages, food, detergents, cosmetics and pharmaceuticals. Its main raw materials are sugar/- molasses, tapioca, corn or glucose (obtained from cereals) and different agents for the submerged microbial fermentation of carbohydrates.

It is submitted that the market of EU was also restricted for China with the imposition of anti dumping duties. China with its surplus capacity had to divert its export to another favorable destination and hence started exporting to India.

- Anti dumping duties on Sodium Citrate from China by Brazil
  Brazilian domestic industry also became the victim of increased imports from Chinese
  producers of Sodium Citrate and therefore the Brazilian industry imposed anti dumping
  duties on imports of Sodium Citrate from China vide CAMEX Resolution No. 52. It is thus
  - duties on imports of Sodium Citrate from China vide CAMEX Resolution No. 52. It is thus seen that the market of Brazil also became restricted for the Chinese Industries and this also became the reason for surge in imports from China, in the recent period, to India.
- u. It is therefore, pertinent to note that imposition of anti dumping duty by several countries like the US, EU and Brazil against China has changed the course of the trade of this product across countries. Earlier, China was selling this product in the US market and EU & Brazil markets, which after 2009-10 became restricted. Accordingly, the Chinese exporters started searching for newer markets and India, with its growing demand for the said PUC, became a natural destination. This led to worsening of the condition of the domestic

- industry, which from a situation of profit in 2009-10, went on to pose loss for the first time in 2010-11; and continues to be in losses which has aggravated steeply in 2013-14.
- v. Indian industry has sufficient capacities to meet the demand for the product in the country. In fact, the producers who attended Public Hearing alone supporting imposition of safeguard duty could meet the entire Indian demand. Furthermore, there is no dispute that capacity additions in the product under consideration are not significant issues either in term of time frame or the capital investment.
- w. Increase in imports has led to decline in productivity of the domestic industry as can be seen from the table below:

(In MT)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Productivity per day (indexed)	100	102	129	128

#### 21. Domestic industry has submitted with regard to the issues raised by Prakash Chemicals as follows:

- (a) Interested parties concede that the expansion of capacities in the product under consideration is not a long drawn or heavy investment process. If the market is protected, even companies such as M/s Ishita Drugs And Industries Ltd would turn back to production. As stated by Ishita Drugs And Industries Ltd, they were producing the product for quite long. The only reason for them to shift to trading is high profit margin in trading as compared to manufacturing. Therefore growth in demand could be catered by the domestic industry.
- (b) Assuming a situation where the domestic industry does not have dedicated capacity for the product under consideration and the capacities are being shared with other products, the domestic industry has been given protection under the law. The Director General (Safeguards) has earlier recommended and the Govt. of India had imposed safeguard duty on imports of, for instance, Hot Rolled Stainless Steel products of 304 series where the domestic industry does not have dedicated capacity.
- © Petitioner has not claimed that there are 25 domestic producers. The petitioner has provided a list of companies who are producers of the product under consideration and claimed that the petitioner and supporter production constitutes 90% of Indian production. Therefore, how M/s Prakash Chemicals can make such sweeping statements that these manufacturers are suffering due to lack of skill and capability to remain in competitive market, is difficult to understand.
- (d) Specific details of Indian demand, Indian production has been provided. Further, the initiation notification also notifies the total demand of the product in India and production of the product under consideration in India. Petitioner has dedicated production plant. Prakash Chemicals is a trader and has no knowledge about the facts.
- (e) Major issue raised by petitioner at the time of oral hearing is why M/s Ishita Drugs And Industries Ltd. has stopped manufacturing the product and has turned to import of the product from China despite having production capacity. Even when the owner of the company was present at the time of hearing, no satisfactory reply was forthcoming from the company. Eventually the company conceded that they are importing the product and selling the same in food & pharma application and exporting the product to US market.
- (f) Argument that buying Citric Acid monohydrate and giving the process by using valuable resources like people and machinery with even small capital investment is not wise business when the end product "Sodium Citrate" is available at same price, further substantiates that the exporters are selling the product at low price which is why the importers are buying imported product. This is precisely the reason that manufacturers such as M/s Ishita Drugs And Industries Ltd have started importing PUC. The argument of the opposing party implies that wherever Chinese producers are backward integrated, the Indian industry should close down manufacturing capacities and should depend 100% on imports. This is certainly against public interest. Moreover, the mere fact that Chinese producers have their own citric acid and sell sodium citrate does not imply that the Indian industry should not be protected.
- (g) Considering the export price to India, landed price and high injury margin, petitioner request safeguard duty for four years to address injury to the domestic industry.

- (h) The profits earned by the traders by mere trading appear more than 10%. And such traders believe that a 10% mark up on citric acid is sufficient to take care of conversion costs, overhead costs, interest, depreciation, wages, return on capital employed. This clearly shows the approach of these traders, whose limited objective is to earn profits by trading.
- (i) Imposition of safeguard duty will be in public interest. Sodium Citrate is primarily consumed in ORS, Cheese, cough cyrups, soft drinks, jellys, photographic industry, beverages and pharmaceutical industry. Petitioner has tried to quantify the impact of safeguard duty on the Sodium Citrate at 30% safeguard duty as is shown in the table below:

Product	Role	Consumption	Estimated cost	Cost Impact at
			(INR)	30% duty
ORS	As ingredient	2.9 GM/LITER	0.1885 / LITER	0.008%
Cheese	As preservative	2.30%	0.13 / 100 GM	0.016%
Cough syrup	As expectorant	1.1 GM/ ML	0.0715 /100 ML	0.049%
Soft drinks	As salty & tangy taste	< 2%	< 0.12 / LITER	0.090%
Jelly	As salty & tangy taste	< 2%	< 0.12 / 100 GM	0.018%
Photographic industry	As anti coagulant	< 2 %	< 0.12 / 100 GM	0.004%
Beverages	As salty& tangy taste	< 2 %	< 0.12 / LITER	0.072%
Pharmaceutical industry	As anti coagulant	< 2 %	< 0.12 /100 GM	0.004%

Petitioner has considered the estimated consumption of sodium Citrate in each of the above mentioned consumer segment and have then calculated the impact on the eventual cost. It would be seen that the eventual impact on the consumers of Sodium citrate is negligible.

#### **Examination and Findings:**

- 22. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producer, user/importers, exporters and exporting nations. The submissions made by the various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below.
- 23. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
- 24. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation.
- 25. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification. Various issues raised by the interested parties have been addressed at appropriate places in these findings and herein below:
  - Some interested parties have contended that the domestic industry cannot seek imposition of both anti dumping duty and safeguard duty. It is noted that the issue of simultaneous imposition of anti dumping duty and safeguard duty is well addressed in the law itself. It is a fact that petitioner domestic industry has also sought imposition of anti dumping duty and the investigation is at present on-going. The Designated Authority has not yet recorded a finding and anti dumping duty has not been recommended as yet. The investigation may or may not establish justification for imposition of anti dumping duty. It is also noted that anti dumping duty is also a trade remedy measure to counter and neutralize the ill effects of dumped imports through imposition of anti dumping duty. Safeguard duty is a measure to protect the domestic industry from injurious effects of increased imports by raising tariff barrier. Both the duties have one function in common i.e neutralizing injurious effects of imports, besides other functions. Therefore, it is imperative that the safeguard duty may be imposed and continued only when the existing trade remedies measures, in whatever form, are not able to protect the domestic industry. It is also implied that the multiple protection is available only to the extent it is necessary. In the instant case, it is a fact that imports increased many fold and the Designated Authority has not yet established the need for imposition of anti dumping

duty. The increase in imports have caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry. The existing tariff, which did not include anti-dumping duty, was not sufficient enough to prevent imports in large quantity. Therefore, it would be appropriate to consider whether imposition of safeguard duty is necessary. It is also noted in this regard that some interested parties contended that Chinese companies exporting sodium citrate are the companies also producing citric acid (raw material) and therefore their costing is naturally lower. This implies that the entire difference in the import price of the product and domestic costs is not due to dumping of the product.

#### ii. Product under Consideration (PUC):

- a. The product under consideration is 'Sodium Citrate' (hereinafter referred to as PUC) which is imported into India under Custom Tariff Heading 29181520 of Chapter 29 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration i.e., "Sodium Citrate" is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, di-sodium citrate and tri-sodium citrate. It is sodium salt of citric acid and has a sour and salty taste. Sodium Citrate is mainly used in pharma industries as an expectorant and urine alkanizer. It is also used as a pharmaceutical aid, food additive in dairy industries, laboratory reagent in water treatment, acidity regulator in drinks, an emulsifier for oils when making cheese and an antioxidant in food etc. The product under consideration can also be transacted by following alternate names
  - a. Sodium Citrate
  - b. Tri sodium Citrate
  - c. Tri sodium citrate dihydrate
  - d. Sodium citrate dihydrate
  - e. Tribasic sodium citrate
  - f. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate
  - g. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate
  - h. Sodium Citrate Monobasic Bioxtra
- 26. The Interested parties have argued that tri sodium citrate, mono sodium citrate and di-sodium hydrogen citrate have been wrongly clubbed together, it is clarified that di-sodium hydrogen citrate is not included in the scope of the product under consideration. Further, Mono/di/tri sodium citrate is merely a form of Sodium Citrate and has the same use, function as well as identification under customs classifications. The production technology and process used for producing these forms are one and same. The consumers also use them interchangeably. It is therefore, found appropriate to hold any reference to mono/di/tri sodium citrate as sodium citrate, which is the product under consideration.
- 27. Some of the Interested Parties have argued that the domestic industry produces Sodium Citrate for Pharma grade only. It is however noted that the interested party has not provided any information to substantiate the same. As against this contention, it is noted that the domestic industry produced the PUC and has sold it to different segments like Pharma/food/pesticide etc., which shows no restriction or limitation on the part of the PUC produced and sold by the domestic industry to only pharma sector. In view of the above, it is concluded that the goods produced by the applicant domestic industry are used in all type of industries like Pharma/food/pesticide etc.
- 28. Some of the interested parties have contended that the product was imported in crude form and it was processed further in India. The domestic industry has claimed that there is no processing of the imported material and the product is merely repacked to claim pharma or food grade product. The domestic producers have contended that the imported product in fact cannot be processed considering the technicalities involved in production or processing the product. Domestic industry contended that since pharma grade product cannot be imported into the country, these parties are importing the product by stating "not for medicine use", showing processing and then selling in the market. It is noted that the interested parties have not elaborated on the production process carried out by them on the imported product, nor these parties have refuted the claims of the domestic industry in this regard. It is also noted that the product is being imported by some of those parties who were earlier producer of the product under consideration in India. These parties claimed to have suspended production and now importing the product. It is however not clear whether these parties are selling the product as a goods produced by them or as a trader. It is thus not established that in fact imported product is being further processed by the importers.

- i. Some interested parties have contended that petitioners produce only pharma grade PUC catering only to pharma & food industries and not to other chemical industries like agrochemicals, electroplating etc. The petitioner has however provided documentary evidence (commercial invoices) substantiating that the petitioner has produced all types of product under consideration.
- ii. It has been contended that the petitioner is admittedly exporter of the PUC and, thus, no serious injury is caused due to imports. It is however noted that the fact that the petitioner has been exporting the product does not imply that the petitioner has not suffered injury due to increased imports. Export of goods is only one of the modes of sale of the product.
- iii. It has been contended by the interested parties that no significant value addition is done by the petitioner. It is however noted that at the same time, these interested parties have contended that they import the product in crude form, do significant value addition and then the product. This clearly shows contradictory arguments advanced by these interested parties. In any case, the production facilities of the petitioner were verified by undertaking on the spot verification and it is found that the petitioner is undertaking significant production related activities.
- iv. Some Interested parties have argued that applicant is a multi product company and the capacity is used to make various other products as well. However, it is seen from the information duly verified as per excise records, that petitioner has dedicated plant for the product under consideration.
- 29. Therefore, it is held that the product under investigation is "Sodium Citrate" falling under Custom Tariff Heading 29181520 of Chapter 29 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The scope of the product under consideration includes all forms of sodium citrate. Accordingly, it is also held that domestically produced Sodium Citrate falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced Sodium Citrate is a like article to the imported Sodium Citrate within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

#### 30. **Domestic Industry (DI):**

- i. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:
  - (a) "Domestic industry" means producers –
  - (b) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
  - (c) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.
- ii. The application has been filed by M/s Posy Pharma Pvt Ltd. for imposition of Safeguard Duty on imports of Sodium Citrate. The application has been supported by M/s Sunil Chemicals. The applicant has identified a number of other producers who are known to have created capacity to produce product concerned in India as well as who have been selling the product in the country. However, in absence of concrete information as producers, their known sales have been considered as their production. The information on record shows volume of production of like or directly competitive article in the country as shown below:

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Petitioner	1,184	1,211	1,531	1,521
Petitioner + Supporter	2,423	2,674	2,992	2,783
Other Indian Producers	133	207	235	109
Total Indian Production	2,556	2,881	3,227	2892
Share in Indian Production			·	·
Petitioner	46%	42%	47%	53%
Petitioner + Supporter	95%	93%	93%	96%
Other Indian Producers	5%	7%	7%	4%
Total Indian Production	100%	100%	100%	100%

iii. From the above table, it is noticed that the output of the applicant constituted a major share of the total production of Sodium Citrate in India. Interested parties have argued that petitioner along with M/s Sunil Chemical does not constitute 90% of the Indian production. It is however noted in this context that none of the other producers have provided data on the capacity available with them. Therefore information as provided by the petitioner has been adopted as the best available information. There is no evidence on record of the Designated Authority establishing that the claims of the petitioner in this regard are not appropriate. On the contrary, one of the parties claimed that the supporting producer, M/s Sunil Chemical has not produced the goods. However, Sunil Chemical has provided information containing therein their production over the relevant period. In any case, if Sunil Chemical production is to be treated as zero, the same implies that the production of the petitioner shall constitute significantly higher share than what has been considered in the present findings. Furthermore, it is not the contention of any of the other interested parties that the petitioner does not constitute a major proportion of the total Indian production.

iv. Accordingly therefore, I hold that M/s Posy Pharma Pvt. Ltd. has the largest share amongst all producers and fulfils the criteria of Domestic Industry in this case, having 52% share in the Indian production in most recent period and with the supporter, M/s Sunil Chemicals, around 96% share in the Indian production. During the investigation (in Public Hearing), another domestic producer, namely M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals has also lend their support to the applicant, which completely wipe out any doubt about the standing of the applicant as Domestic Industry, individually or with supporters. Therefore, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the meaning required and defined under Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act,1975.

#### 31. Source of Information:

- The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 29181520 of Chapter 29 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data taken from DGCI&S, Kolkata (Transaction wise) from April, 2010 till September, 2013 and for the period from Oct'13 to Jan'2014, it was procured from IBIS, Mumbai. The domestic data on various economic parameters from 2010-11 to 2013-14 (up to Oct', 2013) has been verified by on-site visit by the department to the extent deemed necessary and available during visit. Domestic industry data for the period thereafter till Jan., 2014 was verified from Excise records and this verified data was taken into consideration for injury analysis at the time of Notice of Initiation. The notice of initiation was therefore based on information for the period upto Jan., 2014. During the course of the present investigation, data for additional period till Mar'2014 in respect of various economic parameters have been considered as per central excise records as furnished by the applicant, duly certified, in order to arrive at yearly consolidated data for the year 2013-14 for injury analysis. Imports for the period 2013-14 is now based on the imports information published by the DGCI&S. The additional information was made available to interested parties through Public File as required under Rule 6(7) of Safeguard Rules 1997. The data for three years or longer has been provided by the Domestic Industry in the form and manner decided by DG (Safeguard) under Rule 5(2) of Safeguard Duty Rules 1997 r/w the Trade Notice No-SG/TN/1/97 dated 06/09/1997. The non-confidential version of the verification report has been placed in the public file for comments by all concerned. The cost data and calculations of injury margin have been provided by the petitioner duly certified by an independent Cost Accountant.
- b. It is also noticed that none of the interested parties have raised any objection to the import data considered or have provided information with regard to gross imports of Sodium Citrate to India or have disputed the data furnished by the applicant/domestic industry.
- c. M/s. Prakash Chemicals Agencies Pvt. Ltd. and Ishita Drugs & Industries Ltd have not provided any information about their imports or gross imports of the product under consideration in India. These companies have not filed questionnaire responses also.

#### 32. Period of Investigation (POI):

a. Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the

investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown":

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina-Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina-Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports." (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)

b. The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

"In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the Domestic Industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, "the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination." The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports "the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation". The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the Domestic Industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination." (Para 7.209)

- c. From the above it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provide specific guidelines on the period of investigation. However, in the spirit of the references cited above, it appears that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past, but the investigation period should be the recent past.
- d. Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered on year to year basis, from financial year 2010-11 to 2013-14. In the Notice of Initiation, import data up to January, 2014 had been considered on annualized basis. The import data has since been updated till March, 2014. Therefore, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2010-11 to 2013-14 for the purpose of the present investigations which is considered as the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI) in this case.

#### 33. Confidentiality of Information submitted

i. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

ii. The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non- confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application, which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

#### 34. Increased Imports

a. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose Safeguard Duty and provides as follows:

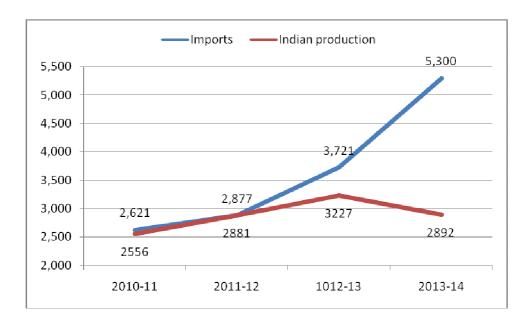
"If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:"

- b. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.
- c. Rule 2(c) of Customs Tariff ((Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides as follows "(c) 'Increased quantity' includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production
- d. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:
- e. "131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."
- f. The Panel on US Wheat Gluten4, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:
  - "8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina —Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."
- g. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned evaluations. Imports of product under consideration into India have shown sharp increase in absolute terms as well as in relative terms. The increase in imports in absolute terms is sudden and significant, causing severe injury to the domestic industry. The data relating to imports of product under consideration in absolute terms from 2010-11 to 2013-14 is as under.

#### 35. Increase in Imports in absolute terms:

a. Sodium Citrate is imported into India from a number of countries, and primarily from China. The imports of the product under consideration have increased throughout the injury period in absolute terms. There is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period. The Imports increased from 2,621 MT in 2011-12 to 5,300 MT in 2013-14 which is an increase of 102%, a very steep surge in imports, as shown below:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	Increase in %
2010-11	2,621	2,556	
2011-12	2,877	2,881	10%
2012-13	3,721	3,227	42%
2013-14	5,300	2,892	102%



It is seen that while the imports increased gradually between 2010-11 and 2011-12, the imports increased rapidly thereafter.

## 35. Increase in imports in relation to production:

**b.** Besides increase in imports in absolute terms, it is noticed that the imports of product under consideration in India during the POI have also increased in relation to production of the Domestic Industry. It is seen from the table below that the import with respect to total production increased from 103% in 2010-11 to 183% in 2013-14, i.e., by 80%, which is a clear surge. In absolute terms, while all India production increased by only 336 MT, the imports increased by 2679 MT, thus showing that whereas Indian production increased only by 13%, imports increased by 102%.

Financial Year	Total Imports	All India Production	Imports in relation to Indian
	(MT)	(MT)	production
			(%)
2010-11	2,621	2,556	103%
2011-12	2,877	2,881	100%
1012-13	3,721	3,227	115%
2013-14	5,300	2,892	183%

- i. One of the interested parties has argued that the increased imports and serious injury should be determined after including export sales of the domestic industry. It is noted that exports sales made by the domestic industry cannot be included in determining domestic consumption of the product under consideration and therefore, sales of the domestic industry should be examined after excluding export sales.
- ii. It is evident from the above that there is a surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production. The increase in imports in absolute terms is a clear surge in imports and

has a rising trend which is significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8B of the Customs Tariff Act' 1975.

## 36. Serious Injury and Threat of Serious Injury:

- 1. Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act provides as follows:
  - "Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry; and "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.
- 2. Section 8B sub section 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:
  - "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.
- 3. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

- 4. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which may show "material injury" to the Domestic Industry, and therefore may justify a finding of market disruption. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "material injury" to the Domestic Industry.
- 5. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.
- 6. In Argentina Footwear (EC), the Appellate Body discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a):
- "[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate 'significant overall impairment' of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'."
- 7. The Panel on US Wheat Gluten, in a finding upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury":

"[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. [W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."

8. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions which are relevant to the affected industry have been considered. All submissions made by the interested parties, domestic industry, supporting domestic producers and opposing interested parties, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry as discussed below:

#### 37. Market Share:

i. It is seen from the table below that the market share of the domestic industry in the total consumption has declined, whereas the market share of the imports has increased.

Financial Year	Total Imports (MT)	Sales of DI (MT)	% of Market share	
			DI	Import
2010-11	2,621	505	11	57
2011-12	2,877	632	12	55
1012-13	3,721	1036	16	57
2013-14	5,300	999	13	69

ii. Market share of the applicant increased till 2012-13 and has declined thereafter. On the other hand, the market share of the imports has increased significantly from 57% in 2010-11 to 69% in 2013-14, which is an increase of 12%. The sizeable part of market share has been seized by imports. Further, the market share of the domestic industry has declined despite un-utilised capacities and increased production by the domestic industry.

## 38. Production:

The production of the domestic industry has improved over the period. The domestic industry has contended that they have been able to increase production as it kept prices below the levels of cost. It is seen from the table below that despite the efforts made, the production has marginally declined in 2013-14 with significant surge in imports during the same period. The marginal decline in production in 2013-14 is despite 18% increase in demand in this year as compared to the preceding year.

Financial Year	Production
	(MT)
2010-11	1,184
2011-12	1,211
2012-13	1,531
2013-14	1,521

# 39. Capacity utilization:

Domestic industry increased its capacity in view of the increase in demand. Capacity utilization of the domestic industry has increased up to 2012-13 to 56% and then declined significantly in 2013-14 to 46% (but higher than the base year) despite increase in demand and efforts made by the domestic industry to increase production and sales. Domestic Industry is facing significant unutilized capacities due to low priced imports and surge in imports despite sufficient capacities in India. It was examined whether the decline in capacity utilisation is because of increase in capacities. For the purpose, capacity utilisation of the domestic industry was determined considering the capacity in 2012-13.

Financial Year	Capacity	Capacity Utilization
	(MT)	(%)
2010-11	2,700	44
2011-12	2,700	45
2012-13	2,725	56
2013-14	3,300	46

In order to examine whether lower utilization of capacity is due to increased capacity of the DI, it was considered prudent to examine whether the decline in capacity utilization was due to increase in capacity. It is, however, noted that had the Domestic Industry not enhanced its capacity, its utilization in 2013-14 would still have been 56 % only which shows same level, if not a declining trend in capacity utilization from 2010-11 onwards. Interested parties have argued that there does not exists sufficient capacity with the domestic industry to cater the whole demand, it is noted that applicant has already enhanced its capacity in March 2014. Therefore, capacity with the applicant along with the capacity of the supporter is itself sufficient to cater the demand of the end consumers in the country.

# 40. Changes in the level of Sales:

Sales of the domestic industry increased till 2012-13 and have thereafter declined from 1036 MT in 2012-13 to 999 MT in 2013-14, by about 4%. This decline in sales is despite the fact that the demand increased from 6544 MT in 2012-13 to 7287 MT in 2013-14, i.e., by about 18%. This clearly shows that the Domestic Industry suffered loss in sales at the cost of surge in imports as is shown in the table below:

Financial Year	Domestic Sales	Total Demand
	(MT)	(MT)
2010-11	505	4,580
2011-12	632	5,278
1012-13	1,036	6,544
2013-14	999	7,705

#### 41. Employment:

The domestic industry has increased number of employees in the product under consideration over the injury period. Applicant has submitted that employees have been added because of increase in capacities, increase in efforts to produce and sell the product and the fact that employees are not dedicated to the product under consideration alone. It is considered that employment is dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of imports on the Domestic Industry.

		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
No of Employees	Nos	53	96	105	105

### 42. Productivity:

With the rise in production, the productivity increased till 2012-13 from the base year, and then declined marginally in 2013-14. Productivity per unit employee of the domestic industry however, declined in 2011-12 and increased thereafter due to increase in employees.

Financial Year	Productivity per day (MT) (indexed)	Productivity per employee (indexed)
2010-11	100	100
2011-12	102	56
1012-13	129	65
2013-14	128	75

#### 43. Profit & Loss:

a. The profitability & returns on investments of the Domestic Industry has steeply deteriorated to such an extent that the Domestic Industry is suffering financial losses. The financial losses being suffered by the domestic industry has further intensified during the POI. This is evident from the table below:-

Financial Year	Profitability	Profitability	Return on investment
	(Rs/Lacs)	(Rs/Kg.)	% (indexed)
	Indexed	Indexed	
2010-11	(100)	(100)	-100%
2011-12	(249)	(199)	-155%
1012-13	(378)	(184)	-146%
2013-14	(1174)	(593)	-549%

- b. It has been contended by the domestic industry that to compete with the huge volume of imported goods in the market, the Domestic Industry had to keep its prices below the cost of sales. This has sharply affected their profitability, which has significantly intensified during the most recent period of 2013-14. The domestic industry is, thus, suffering severe financial losses on account of imports.
- c. It has been contended by the interested parties that sodium citrate has been a low margin product and manufacturers have always enjoyed very low margins. It is however the contention of the domestic industry that they have suffered financial losses, leave aside low margins or profits. It is further noticed that the extent of losses suffered by the domestic industry have increased over the period.

### 44. Other important factors:

Para (2) of Annex to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 lays down that the determination referred to in subparagraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof and when factors other than increased import are causing "serious injury" to the Domestic Industry at the same time, such "serious injury" shall not be attributed to increased imports. However, no specific factor has been listed either under Indian Rules or under WTO Agreement. The Director General is required to examine factors that come to the knowledge of the Director General during the course of the investigations. Further, the Director General has also examined certain generally known factors and which have been specifically prescribed under anti dumping legislation in the absence of specific obligation in safeguard legislation.

- **44.1Demand/consumption:** As such, the possible other factors that may be attributed to the serious injury to Domestic Industry have been examined. Followings are relevant in this regard: –
- a. **Demand of the product:** Demand for the product under consideration has shown significant positive trend. Therefore, possible decline in demand for the product is not a possible cause of serious injury to the domestic

- industry. In fact, while overall demand has increased, it is seen that rate of increase in imports was much higher than the rate of increase in demand. Market share of the imports have increased significantly and imports hold substantial share of the domestic market. It is, thus, clearly seen that the increased imports have taken away the major share of the demand.
- b. Demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of sales of all Domestic producers and imports from all sources. It is noted that the demand of Sodium Citrate has shown a positive trend throughout the period. It is also noted that whereas demand increased by 68%, imports increased by 102%, thus showing that the increase in imports was more than increase in demand for the product in the Country.

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Domestic industry's sales	MT	505	632	1,036	999
Other producers (including supporter)' sales	MT	1454	1769	1787	1405
Total Imports	MT	2,621	2,877	3,721	5,300
Demand/consumption	MT	4,580	5,278	6,544	7,705

- c. Some interested parties contended that the actual demand for the product in the country is much higher than the demand determined by the petitioner. The authority however notes that the consumption has been determined considering imports of the product under consideration and sales by the Indian producers. All available information in this regard has been taken into account. As none of the Interested Parties have provided any data in support of their claim, their claim of estimated demand is not substantiated by facts.
- d. The decline in production in 2013-14 is despite 18% increase in demand in this year as compared to preceding year. Further, whereas sale declined marginally in 2013-14, demand of the PUC in the domestic market increased significantly. It is also noted that capacity utilization of the domestic industry has been low, which shows that the production of the domestic industry is much lower than what the domestic industry could have produced in the absence of increased imports. The domestic industry would have apparently fully utilized its capacities in the absence of surge in imports.

#### 44.2 Increase in imports in relation to consumption:

Besides increase in imports in absolute terms and in relation to Indian production, it is noticed that the imports of product under consideration in India during the POI have also increased in relation to consumption of the product in the Country. It is seen from the table and graph below that the import with respect to total consumption increased from 57.23 % in 2010-11 to 68.80% in 2013-14, i.e., by 11%, which is a significant increase.

Financial Year	Total Imports	Consumption	Imports in relation to
			consumption
	(MT)	(MT)	(%)
2010-11	2,621	4,580	57.23%
2011-12	2,877	5,278	54.51%
2012-13	3,721	6,544	56.86%
2013-14	5,300	7,705	68.80%

**44.3Inventories:** The Domestic Industry is faced with accumulated inventories which have shown rising trend throughout the POI, which is about 5 times more in 2013-14 as was in base year, i.e. 2010-11. When compared with 2012-13, it is about 65% more in 2013-14 despite a marginal decline in production in 2013-14 as compared to preceding year.

Financial Year	Average Inventories
	(MT)
2010-11	18
2011-12	37
2012-13	52
2013-14	86

It is seen that the inventories with the domestic industry increased significantly as a result of inability of the domestic industry to increase its sales in proportion to increase in demand for the product in the market, causing serious injury.

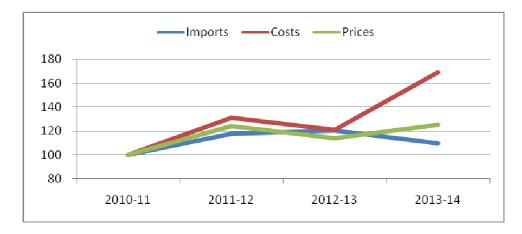
44.4Export performance: Applicants have exported the product under consideration. It is noted that the export volumes of the domestic industry has declined throughout the POI have also declined by about 10% in 2013-14 as compared to 2012-13. Therefore, export has been at the cost of DI sales, which increased till 2012-13 and declined thereafter, which implies increased availability of the product for the domestic market. In any case, the claimed injury to the Domestic Industry is on account of domestic operations. Applicants have provided costing and injury information for domestic operation. No evidence has been put forth by any Interested Party about non- supply of PUC by the DI, citing export requirement or vice-versa. Domestic industry has contended that it has been forced to export only because of increase in imports of the product under consideration. The focus of the domestic industry is domestic market and domestic industry would cater to the same and export the product only when the domestic industry is not able to sell the production in the domestic market. Claimed injury to Domestic Industry, therefore, cannot be attributed to exports, which is thus accepted.

Period	Export (MT)
2010-11	674
2011-12	545
2012-13	501
2013-14	448

### 44.5 Price undercutting, suppression/depression:

a. It is observed that the landed price of the imports of Sodium Citrate is significantly lower than not just the selling price of the Domestic Industry but also the cost of production of the domestic industry. There is a significant price difference between the domestic and imported product. The variation in cost of sales and selling price with respect to landed prices of imports are as under:-

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Landed price of imports	Rs/Kg	44.67	52.62	53.87	48.92
	Trend (indexed)	100	118	121	110
Cost of Sales	Rs/Kg	100	131	121	169
	(Indexed)				
Selling Price	Rs/KG	100	124	114	125
	(Indexed)				



b. It is seen from the table and graph above that selling price of the domestic industry has remained below the levels of costs throughout the POI. Whereas the cost of sales and the selling price both increased over the period, the rate of increase in cost of sales is much more than the rate of increase in selling price. Further, whereas the landed price of imports by 10% over the injury period, the selling price increased by 25%,

whereas costs increased by 69%. The fact that the landed value in 2012-13 was higher than the cost of production and selling price of the DI, it got reflected in the sharp rise in sale in that year as compared to 2011-12 with a resultant easing of losses. Therefore, there is a definite link between cheap imports causing price suppression and depression by the DI, leading to increased losses. Thus, the imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry causing serious injury to the domestic industry.

- c. The argument by the interested parties that the price of the raw material for producing Sodium citrate, i.e., "Citric Acid Monohydrate" and end product "Sodium Citrate" is almost similar and therefore it is not a wise decision to produce Sodium Citrate. This argument in fact shows that the imports are coming at a price much below the cost of production of the DI. This appears to also be the reason due to which manufacturer like M/s Ishita Drugs And Industries Ltd. has shifted to imports. It is claimed by the DI that it is against the interest of the public at large to argue that sodium citrate production in the country is not a wise decision in view of low priced imports available in the country. Depending only on imports is not in the interest of consumers. The existence of a domestic industry is in the interest of the public at large. Moreover, as it has been made out by the Interested parties, it is an attempt on their part to mislead the authority regarding price of the finished product and raw material, which is not so simple as it has been made out to be. It is noted that production of 1 kg. sodium citrate requires only about 0.75 kg of citric acid monohydrate, besides other raw materials also. As submitted by the DI therefore, it would be misleading to compare sodium citrate price with citric acid monohydrate price alone.
- d. Interested parties have argued that month wise/quarter wise import price has not been provided for substantiate claims of undercutting. It is seen that a peculiar circumstance warranting analysis of month wise/quarter wise import data has not been shown and the consistent practice as per law has been followed. Further as contended by the domestic industry the significant fluctuation in exchange rate may in fact show highly distorted position.

### e. Other changes causing serious injury or threat thereof:

- a) Changes in the patterns of consumption: It is claimed by the Domestic Industry that there is no change in the pattern of consumption with regard to the product under consideration. None of the interested parties have contended change in the patterns of consumption and therefore the record does not show that pattern of consumption has undergone any material change as far as the Indian market is concerned. Since none of the Interested Parties has brought out any evidence to dispute this claim of the Domestic Industry, and is, as such, accepted.
- b) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** There is no evidence on record that trade restrictive practices or competition between the foreign and domestic producers could have contributed to the injury to the Domestic Industry.
- c) Developments in technology: The applicant has claimed that the technology for production of the product has not undergone any change. This has not been refuted by any Interested Party. Developments in technology are therefore, not a factor of injury, in this case.
- d) It is thus noted that possible other factors have not caused injury to the Domestic Industry. There are no other factors that can be attributing to the serious injury to the Domestic Industry other than surge in the low priced imports.

## 45. Conclusion Regarding Serious Injury:

- a. The imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to production in India. The volume of imports of Sodium Citrate has surged significantly in 2013-14. As a result of this surge in imports, the Domestic Industry has suffered serious injury in various economic parameters.
- b. Performance of the domestic industry has declined with the surge in imports during the POI. Market share, production, domestic sales, capacity utilization, increased upto 2012-13 with efforts put in by the domestic industry, however, performance in all these parameters declined thereafter in 2013-14, with surge in imports. The DI has not been able to increase its sales despite increase in demand for the PUC. The DI is selling the PUC below its cost of production due to cheap imports.

- c. Parameters such as profitability and return on investment have remained negative and the domestic industry's losses have further increased over the POI. Price undercutting was seen throughout the period. Landed price of imports are below the cost and selling price of the domestic industry thus preventing the price increase by the Domestic Industry in proportion to increase in cost.
- d. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows 'a significant overall impairment'. It is, thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration during the POI.

### 46. Threat of Serious Injury:

- a. There is also a threat of serious injury to the Domestic Industry producing Sodium Citrate in India due to the surge of imports and the current trend of import volumes entering into India. Imports are entering India in significant volumes. The market share of imports has also substantially increased over the period. Considering the production capacities available with foreign producers and their export orientation, there is a high likelihood of continued increase in imports.
- b. The price difference between selling price and imports of Sodium Citrate renders the Indian market an attractive destination for exports. It is noted that the import price is much below the levels of cost of production and selling price of the domestic industry. The industry is already incurring financial losses. Any further increase in imports as a result of this will threaten and pose severe threat of serious injury to the Domestic Industry in future.
- c. In light of the current financial situation of the Domestic Industry in terms of profitability, and return on investment, with rising trend in imports, it is concluded that in the absence of levy of safeguard duty, the Domestic Industry which has suffered serious injury in the POI, also faces a further threat of serious injury which may accentuate the already precarious condition of the DI.

# 47. Causal Link between Increased Import and Serious injury or Threat of Serious injury:

1. As per Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, the Director General(Safeguards) is obligated to "determine serious injury or threat thereof of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to the these rules". Further, paragraph 2 of the Annex requires establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.

1. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."

2. Comprehensive evaluation of parameters as above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an

- objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard –
- i. Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly;
- ii. As the imports are available at prices lower than the selling price of Domestic Industry, the consumers are switching over to imports due to which the Domestic Industry is faced with losing sales and rising inventory;
- iii. Imports prices are in fact lower than the cost of sales of the domestic industry, thus imports are preventing the domestic industry to increase its prices even to the level of costs of production.
- iv. The price suppression/ depression effect of dumped imports was on significant decline in profitability to the Domestic Industry to such an extent that Domestic Industry is suffering huge financial losses.
- v. Market share of imports increased and captured the market share of the domestic industry.
- vi. Due to increased imports at low prices, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales in tandem with the increase in demand/consumption of product under consideration in India.
- vii. The capacity utilization, sales, market share, profits, return on investment, all declined in 2013-13 due to increased imports.
  - c. It is thus evident that serious injury to the Domestic Industry has been caused by the increased imports which are also threatening further injury.

#### 48. Adjustment Plan:

- a. Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules'1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.
- b. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producer is adjusting.
- c. The domestic producer in this case has laid down adjustment plan which focuses on capacity expansion to cater the growing demand, automation of machinery/technology, use of solar power for energy cost saving and cost reduction.
- d. The Applicant submitted that in pursuant to their adjustment plan submissions in their petition, they have already purchased a new machine in the month of March 2014. The capacity has now increased to 5000MT. It has been submitted that the plant expansion would enable the company to face fair competition from imports. Accordingly, the petitioner has requested safeguard duty for a period of four years so that they are in a position to face the import competition.
- e. It is further clarified by the applicant that owing to the above adjustment plan, the company would be in a fair position to meet the international competition as well as will be able to meet the potential demand of subject goods in India. Interested parties have argued that mere plan of expanding capacity is not sufficient, as all manufacturers depend on citric acid. It is however noted that the argument that that Indian industry is dependent on citric acid is entirely immaterial for the purpose of present investigation concerning imports of Sodium Citrate.
- f. In view of the above, it is concluded that the applicant has provided a viable adjustment plan which focuses on cost reduction, capacity enhancement to cater the growing demand of Sodium Citrate.

### 49. Unforeseen Developments:

a) It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules, on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments, or the WTO Agreement on Safeguards, which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. This Directorate has consistently been examining the issue of "unforeseen developments" in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports. In this regard, I find that Article XIX of GATT,94 provides that serious injury has to be as a result of unforeseen developments.

#### Article XIX of GATT 1994 states as follows:

1.(a)If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.

- b. The Appellate Body in Argentina Footwear (EC) case held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.
- c. The applicant has given a number of reasons for surge in imports, which in their understanding constitute the unforeseen circumstances in this case, which are summarized below:

## c.1 <u>Increase in capacity in China leading to diversion of export to India:</u>

It is seen that majority of imports into India are of Chinese origin and recently from Canada, as seen below:

	Quantity (MT)				Share of import			
Country	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Austria	-	2	5		0%	0%	0%	0%
China PR	2,578.00	2,804.00	3,526.00	4,350.48	98%	97%	95%	82%
Canada				699.60	0%	0%	0%	13%
Germany	11.02	64.80	19.57	41.16	0%	2%	1%	1%
Poland	0.05		0.17	0.95	0%	0%	0%	0%
Spain	23.00	4.90	165.04	90.01	1%	0%	4%	2%
Thailand	4.00				0%	0%	0%	0%
UK	4.40	0.38	0.30	0.50	0%	0%	0%	0%
USA	0.27	1.06	2.74	117.59	0%	0%	0%	2%
Unspecified			2.00		0%	0%	0%	0%
Total	2,620.74	2,877.21	3,721.12	5,300.29	100%	100%	100%	100%

It is seen that imports from China constitutes almost 82% of the total imports into India during the POI (cumulative imports from China were 4351 MT as against cumulative imports of 5300 MT). This is because there is excess capacity with the producers across the countries like China. Chinese market has excessive capacities. US have conducted an antidumping investigation against imports of Citric Acid and Certain Citrate Salts, which include Sodium Citrate, wherein the USA has held that China has significant capacities. The capacity estimated for Citric Acid and Certain Citrate Salts was estimated at 21, 95,911 MT for 2010. This has led into significant demand supply gap in China. China has built capacities far excess than the domestic demand. There exits significant demand supply gap as can be seen from the table below, which is further

forcing the exporters from China PR to export the goods to India. The demand supply gap as projected in the US Findings is shown below:

(Demand Supply gap in China) in '000 pound –						
Year	2006	2007	2008	2009	2010	
Apparent Consumption	323	460	475	589	607	
Capacity	1443	1932	2047	2193	2195	
Production	1247	1719	1807	1779	1834	
GAP (production –consumption	924	1259	1332	1190	1227	

Source: US Findings.

It is seen that the present surplus capacities with the Chinese producers are significantly high considering the gross Indian demand for the product in India. The capacity with various Chinese manufacturers is far more than the total demand in India. It has been contended by the petitioner that continuous rising imports show that the producers in these countries have created significant surplus capacities which force them to exports to various markets at cheap prices. India being large market with positive growth in product, demand is lucrative to them. The foreign producers are highly export oriented and have created significant production capacities and hence are competing to maintain a stronghold on the Indian markets by increasing exports to India.

## c.2 Anti dumping duty imposed by various countries (US, EC & Brazil):

It is submitted by the DI that several countries have earlier imposed anti dumping duty on imports Citric Acid and Certain Citrate Salts, which includes product under consideration, primarily from China. The EC has even undertaken review of its anti dumping measures imposed earlier on the PUC against China. Imposition of anti dumping duties by these countries on the import of PUC restricted these markets for China. Therefore, China with its surplus capacity had to divert its export to another favorable destination and hence started exporting to India.

Having regard to the information on record and submissions made by the interested parties, it is observed that the imports of the product under consideration from China have increased on account of surplus capacity, significant demand supply gap in China and imposition of anti-dumping duty on exports of sodium citrate and citric acid by various countries. Producers from China are compelled to search for the growing market for their product and India being a viable choice was targeted, leading to increased imports in India. All these factors taken together, as claimed by the DI, appear to form the unforeseen circumstances for the increase in imports of Sodium Citrate, which is primarily from China.

Therefore, I hold the rise in import of Sodium Citrate due to imposition of anti dumping duty by the various countries against imports of Sodium Citrate from China aided by huge demand supply gap for this product in China due to excessive capacities, to be an unforeseen development resulting in increase in imports causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.

# **50.** Public Interest:

a. Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."

- b. In an economy there are varying and sometimes competing interests of different economic players. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impacts may not always be most suitable for all the different economic players when they have competing interests. Therefore, interests of various economic player groups have been analyzed based on the available information.
- c. The landed price of imports is lower than the (a) selling price of the Domestic Industry, and (b) cost of sales of the Domestic Industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in price suppression. It is seen that the selling price of the Domestic Industry is far lower than the cost of sales. In order to sustain in the market, the Domestic Industry was unable to increase its selling price in proportion to increase in cost of sales thereby suffering huge losses. With the rate of decline in profits and return on investments, in case of non levy of safeguard duty, the Domestic Industry, as claimed by them, would be left with no option but to close down its business.
- d. It has been claimed by the Domestic Industry that the imposition of safeguard duty would be in public interest as it will not only prevent injury to the Domestic Industry but also would help in checking further decline of the Domestic Industry. As regards the impact of safeguard duty on consumers/users, it is observed that Sodium Citrate is primarily consumed in ORS, Cheese, cough cyrups, soft drinks, jellys, photographic industry, beverages and pharmaceutical industry.
- e. The Domestic Industry has cited an example and has tried to quantify the impact of 30% safeguard duty on eventual downstream products. Domestic Industry has considered the estimated consumption of sodium citrate in each of the above mentioned consumer segment and have then calculated the impact on the eventual cost. Domestic industry have claimed that the 30% increase in price on account of safeguard duty, if fully passed onto the eventual end product (assuming that the Domestic Industry increases the prices by 30%) would be negligible on the eventual end products, as is seen from the following table:-

Sector-wise PUC	Concumption and	Cost per II	nit of the	Finished Goods
Sector-wise I UC	Consumption and	i Cost per o	mi or me	r iiiisiicu Goous

Product	Role	Consumption	Estimated cost	Cost Impact
				at
			INR	30% duty
ORS	As ingredient	2.9 GM/LITER	0.1885 / LITER	0.008%
Cheese	As preservative	2.30%	0.13 / 100 GM	0.016%
Cough syrup	As expectorant	1.1 GM/ ML	0.0715 /100 ML	0.049%
Soft drinks	As salty & tangy taste	< 2%	< 0.12 / LITER	0.090%
Jelly	As salty & tangy taste	< 2%	< 0.12 / 100 GM	0.018%
Photographic	As anti coagulant	< 2 %	< 0.12 / 100 GM	
industry				0.004%
Beverages	As salty& tangy taste	< 2 %	< 0.12 / LITER	0.072%
Pharmaceutical	As anti coagulant	< 2 %	< 0.12 /100 GM	
industry				0.004%

- f. The above claim of Domestic Industry has not been disputed by Interested Party in these investigations. In view of the absence of any contrary submissions/rejoinders having been filed by any Interested Party in this case, the submissions made by the Domestic Industry are considered justified. As shown by the Domestic Industry, it appears that the impact of the safeguard duty on different segments of the users of the subject product would be minimal. It is concluded that if the prices are increased by 30%, the impact of the same on the eventual end product would not be significantly adverse, and that the imposition of the safeguard duty will not result in significant increase in the prices of eventual end products.
- g. Some interested parties contended that imposition of safeguard duty shall result in duopolistic situation and shall lead to increase in product prices and downstream product. However, even when all interested parties were advised at the time of oral hearing to substantiate whatever claim they have with regard to present investigations, it is noted that these opposing parties have not provided any supporting evidence. These parties have not even established how the claim of the domestic industry with regard to negligible impact on the consumers is incorrect. The investigation has shown that the impact of the proposed safeguard duty shall be

negligible on the eventual end product. Further, imposition of safeguard duty shall not lead to duopolistic situation. There are admittedly a number of producers of the product in the Country. Interested parties agree that the investment involved in settling up production facilities for the product under consideration are not high, nor it requires significant time to set up or enhance capacities. Therefore, it is not a case that imposition of safeguard duty would lead to duopolistic situation.

- h. Some interested parties contended that imposition of safeguard duty would make the operation of downstream users unviable and cause significant disadvantage to the consumers due to price increase of end products especially, pharma. It is however noted that the impact of the proposed safeguard duty would be negligible and therefore it is not established that imposition of safeguard duty would make the operation of downstream users unviable.
- i. In the light of the facts on record, it is concluded that imposition of safeguard duty would be in public interest and the interests of end users would not be very adversely impacted.

## 51. Developing Nations:

- a. The percentages of imports from developing nations have also been examined. Except China PR who constitutes 82 % of total imports in India during FY 2013-14, other developing nations individually and collectively are less than 3% and 9% share respectively of total imports in India. Therefore, imports of product under consideration originating from developing nations except China PR may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.
- b. Interested parties have argued that Safeguard duty will lead to retaliation by countries, on some products exported by India to these countries. There has never been a retaliatory action taken by any country against safeguard duty levied. India is also a signatory to WTO and has enacted its law in consonance with the WTO Safeguard Agreement. The WTO itself empowers the member countries to protect its industry after following the procedure established under the law.

# 52. Conclusion:

On the basis of above examination and analysis done, it is concluded that :-

- a. There has been a significant increase in imports of Sodium Citrate, the Product Under Consideration (PUC) in absolute terms as well as in relation to domestic production over the entire Period of Investigation (POI). Thus, it can be concluded that there is a significant surge in imports of PUC so as to cause or threaten to cause serious injury. This surge in imports is also quite significant in relation to total demand as well.
- b. The Domestic Industry has been able to demonstrate that the developments in the market for surge in imports of the Product under Consideration were unforeseen, especially with regards to China PR (82% of total imports).
- c. The investigation has shown that the domestic industry has suffered serious injury, considering overall performance, on the basis of listed economic parameters, i.e., market share, sales, capacity utilization, production and productivity in 2013-14 as compared from 2012-13. However, profitability has steeply declined from the base year till 2013-14. Though employment has increased, the productivity per employee has severely declined from base year till 2013-14 and the inventory has risen steadily till 2013-14 from the base year. The Domestic Industry has been able to demonstrate serious injury caused in the form of mounting losses and accumulated inventories by way of declining sales even when demand for the PUC rose in the country. It is also seen that the growth in production of the domestic industry is far lower than the growth in demand for the product under consideration in the Country and the domestic industry has significant unutilised capacities. This has caused significant overall impairment to the position of the domestic industry. Moreover, the market share of DI has declined in 2013-14 as compared to 2012-13 with a corresponding rise in the market share of imports in the same period. It establishes the causal link between the rise in imports and serious injury caused to the Domestic Industry during the POI.

- d. It is also seen that the Domestic Industry has sought protection in the form of Safeguard Duty for a period of 4 years, for which they have provided an adjustment plan. The adjustment plan is also found to be reasonable. The contention of the Domestic Industry that they have already expanded their capacity and they along with other domestic producers are fully capable to cater to the demand of the product under consideration in the domestic market appears acceptable.
- e. The Domestic Industry has also been able to show that imposition of safeguard duty in this case would be in Public Interest because the probable impact of the safeguard duty on end users/consumers would be minimal. It is also found that no Interested Party has refuted or disputed this aspect during the course of investigation.

#### 53. Recommendations:

a. Increased imports of Sodium Citrate into India have therefore, caused and threaten to cause serious injury to the domestic producers of Sodium Citrate and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of Sodium Citrate into India, in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules 1997, for a period of 3(Three) years. Considering the average cost of sales of Sodium Citrate by the domestic producer, after allowing a reasonable return on capital employed, safeguard duty, which is considered to be the minimum required to protect the interest of Domestic Industry, is hereby recommended to be imposed on imports of Sodium Citrate falling under Custom Tariff Heading 29181520 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (HS code is only indicative and the product description shall prevail in all circumstances) as shown below:-

Period	Rate of Safeguard Duty
First year	55 % ad valorem
Second year	50 % ad valorem
Third year	40 % ad valorem

b. As the imports from developing nations except China PR do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F. No. D-22011/20/2013]

R. K. SINGLA, Director General.